महानगर नई दिल्ली गुरुवार 26 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

सीएए पर हिंसा करने वालों को प्रधानमंत्री की नसीहत

खुद से पूछें कि क्या उनका रास्ता सही था

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नाराजगी जताई। उन्होंने उपद्रवियों को नसीहत देते हुए पूछा, 'वे लोग खुद से सवाल पूछें कि क्या उनका यह रास्ता सही था।' उन्होंने विरोध-प्रदर्शनों को लेकर कहा कि सरकार आगे भी बड़े और कड़े फैसले लेती रहेगी।

प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान नागरिकता संशोधन कानून, रामजन्मभूमि मामला और अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार विरासत में मिली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान का निरंतर प्रयास कर रही है और उसने चुनौतियों को चुनौती देने का कोई मौका नहीं छोड़ा है।

प्रधानमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चुनौतियों को चुनौती देने का स्वभाव लेकर निकले हैं। प्रधानमंत्री ने हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को नसीहत दी और अधिकार के साथ कर्त्तव्य याद दिलाए। प्रधानमंत्री ने कहा, 'यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध-प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वे अपने घरों में बैठकर खुद से सवाल पूछें कि क्या उनका यह रास्ता सही बाकी पेज 8 पर

मोदी ने कहा : सरकार आगे भी बड़े और कड़े फैसले लेगी, विरासत में मिली चुनौतियों को दे रहे चुनौती
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज्यादा जोर अधिकारों पर दिया है, लेकिन अब हम आजादी के 75 साल पूरे होने की ओर बढ़ रहे हैं।
समय की मांग है कि अब हम अपने कर्तव्यों पर भी उतना ही बल दें।
लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन।

'अटल जल योजना' शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कम पानी वाली फसलों व ऐसी सिंचाई पद्धति अपनाने की अपील की, जो जल संरक्षण में मददगार हो। उन्होंने 'अटल भूजल योजना' (अटल जल) की शुरुआत की, जिससे सात राज्यों के 8,350 गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है। लखनऊ में आयोजित समारोह में मोदी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय गठित करके सरकार ने जल के मुद्दे को विभागीय कार्यक्रम के दायरे से बाहर निकाला और समग्र दृष्टिकोण के आधार पर आगे बढ़ाया।

अटल जल योजना महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के 78 जिलों में 8350 गांवों में भूजल स्तर को बेहतर बनाने में मददगार होगी। गन्ने जैसी फसलों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसके लिए काफी पानी बाकी पेज 8 पर

असम और त्रिपुरा

हटेंगी असम राइफल्स और सेना की टुकड़ियां

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

असम और त्रिपुरा से असम राइफल्स और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां हटाई जाएंगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शनों के बाद इन क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती की गई थी।

कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को धीरे-धीरे हटाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को इस आशय की संस्तुति भेज दी है। गृह मंत्रालय एक आला अधिकारी ने कहा कि असम और त्रिपुरा में हालात सामान्य हो चुके हैं। दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है। इन राज्यों से भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को हटा लिया जाएगा। असम सरकार के अनुरोध पर 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच भारतीय सेना की 29 टुकड़ियां स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए तैनात की गई थीं। प्रत्येक टुकड़ी में 70 सैनिक और एक-दो अधिकारी होते हैं। इसी तरह त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर भी राज्य में असम राइफल्स की तीन सैन्य टुकड़ियां तैनात की गई थीं।

दोनों राज्यों में स्थानीय प्रशासन की आवश्यकतानुसार मदद के लिए सैन्य टुकड़ियों की तैनाती की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, हालात में काफी बाकी पेज 8 पर

दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था में सुधार के बाद गृह मंत्रालय का फैसला

दिल्ली सहित उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में हाड़ कंपाने वाली ठंड

कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कंपकंपी

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को दिल्लीवासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से नौ डिग्री कम है। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी।

वहीं चिल्लई कलां के दौर से गुजर रहे कश्मीर में बुधवार को तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया जबकि ठंड ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को भी अपने आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में सप्ताहांत में तापमान के चार डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में गत 16 दिसंबर से नौ सर्द दिन दर्ज किए गए हैं जो 2003 में दर्ज किए गए दिनों के बराबर है। इस बीच मध्यम गति वाली हवा ने बुधवार को हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार किया। समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम चार बजे 350 पर दर्ज किया गया जबकि मंगलवार को सूचकांक 383 था।

मौसम विभाग के अधिकारी के अनुसार समूचे कश्मीर और लद्दाख में बुधवार को न्यूनतम तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया। हालांकि आसमान साफ रहा। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। भीषण ठंड के कारण कई स्थानों पर जल आपूर्ति लाइनें जम गईं।

अधिकारी ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के स्की रिसोर्ट गुलमर्ग में मंगलवार रात पारा शून्य से नौ डिग्री सेल्शियस नीचे दर्ज किया गया। इससे पिछली रात पारा शून्य से 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दक्षिणी कश्मीर स्थित पहलगाम रिसोर्ट में रात का तापमान शून्य से 11.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। अधिकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पहलगाम घाटी में सबसे सर्द स्थान रहा।

मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के लिए मौसम के सूखे रहने का अनुमान लगाया है। 21 दिसंबर से कश्मीर चिल्लई-कलां की गिरफ्त में है, जो 31 जनवरी को खत्म होगा। दूसरी ओर हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी है। नारनौल में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगले दो दिनों तक ठंड का कहर जारी रहने का अनुमान है। हिसार में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हरियाणा में करनाल (छह डिग्री से.), रोहतक (पांच डिग्री से.), भिवानी (5.7 डिग्री से.), सिरसा (6.1 डिग्री से.) और अंबाला (5.5 डिग्री से.) समेत बाकी पेज 8 पर

घाटी में चिल्लई-कलां ने तीखे किए तेवर, पानी की पाइप लाइनें जम गईं।
अगले दो दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं

बर्फबारी के कारण लाहौल-स्पीति का संपर्क दुनिया से टूटने के बाद बुधवार को हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की गई।

चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री से. दर्ज किया गया।
नारनौल में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

सीबीआइ ने यमुना एक्सप्रेसवे घोटाले की जांच शुरू की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) भूमि घोटाला मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है और एजंसी ने अपनी प्राथमिकी में पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता और 20 अन्य को नामजद किया है।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि प्रक्रिया के अनुरूप एजंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी फिर से पंजीकृत की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गुप्ता के रिश्तेदारों और करीबियों ने मुखौटा कंपनियों के जरिए सस्ती दरों पर कथित तौर पर जमीन खरीदी और इसे उसके खरीद मूल्य से दोगुना से अधिक मूल्य पर यीडा को बेच दिया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। सीबीआइ ने मंगलवार की अपराह्न आपराधिक साजिश व धोखाधड़ी के आरोपों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

यीडा ने ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के आसपास विकास गतिविधियों के लिए मथुरा के सात गांवों में 57.15 हेक्टेयर भूमि के लिए 85.49 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि गुप्ता ने अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश के बाकी पेज 8 पर

पूर्व सीईओ, 20 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज
सीबीआइ ने उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी फिर से पंजीकृत की

संपत्ति नुकसान पर रामपुर में 25 लाख की वसूली का नोटिस

रामपुर, 25 दिसंबर (भाषा)।

रामपुर जिला प्रशासन ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के लिए पहचाने गए 28 व्यक्तियों को नोटिस जारी करके उन्हें अपनी स्थिति समझाने या सार्वजनिक व निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भुगतान करने को कहा है। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी।

सीएए के विरोध में बिजनौर में 20 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का आकलन करने के बाद जिला प्रशासन ने 43 लोगों को वसूली नोटिस भेजा है। गोरखपुर में हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल 33 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि एक हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज है।

रामपुर में अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरे जिले में लगभग 25 लाख रुपए के नुकसान का आकलन करने के बाद मंगलवार को नोटिस जारी किए थे। पुलिस ने शुरू में कहा था कि लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान बाकी पेज 8 पर

जिलाधिकारी ने कहा, 28 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी पहचान विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के लिए की गई है। उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

यूपी के डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई में मानवाधिकारों के कथित हनन होने की शिकायतें मिलने पर राज्य के डीजीपी को एक नोटिस जारी किया है।

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनएचआरसी को हाल ही में एक शिकायत मिली थी, जिसमें मानवाधिकारों के कथित हनन (राज्य पुलिस द्वारा) की घटनाओं में उससे हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'इस विषय बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना के जेसीओ शहीद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

जम्मू कश्मीर के रामपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को बिना उकसावे के गोलाबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस वारदात में सेना का एक जूनियर कमीशन अधिकारी शहीद हो गया।

पाकिस्तान के कुछ गोले नागरिक क्षेत्रों में गिरे, जिससे दो नागरिक घायल हो गए। उनमें से घायल एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को सुबह लगभग साढ़े 11 बजे हाजीपीर क्षेत्र में बिना उकसावे के गोलाबारी की। स्नाइपर राइफल से दागी गई गोली लगने से जूनियर कमिशन अधिकारी (जेसीओ) शहीद हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान के सैनिकों की ओर से दागे गए गोले असैन्य क्षेत्रों में भी गिरे जिसमें दो नागरिक घायल हो गए। इनमें से चुरुनंदा गांव बाकी पेज 8 पर

एलओसी पर हाजीपीर क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी
रिहाइशी क्षेत्रों में गिरे गोले

सचिन की सुरक्षा घटी, आदित्य ठाकरे की बढ़ी

मुंबई, 25 दिसंबर (भाषा)।

दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा घटा दी गई है जबकि शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाकर 'जेड' श्रेणी की कर दी गई है।

एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाकी पेज 8 पर

दरअसल

हिम दर्शन योजना के तहत शुरू की गई है ट्रेन

उपलब्धि

एक बार में सौ से अधिक यात्री कर सकेंगे सफर

पारदर्शी छत वाली ट्रेन चली कालका-शिमला मार्ग पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

भारतीय रेलवे ने विश्व धरोहर में शामिल कालका-शिमला मार्ग पर पारदर्शी छत वाली सात बोगियों की विस्टाडोम ट्रेन (पारदर्शी छत वाले डिब्बे) बुधवार को शुरू कर दी। रेलवे के मुताबिक बुधवार को गुब्बारों व क्रिसमस के लाल रंग की यह ट्रेन हरियाणा के कालका स्टेशन से सुबह करीब सात बजे रवाना हुई।

ट्रेन को हिम दर्शन के तहत शुरू किया गया है। इसमें 100 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता है।

रेलवे के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियों और नववर्ष के जश्न के कारण अगले कुछ दिनों तक सभी सीटें बुक हैं। रेलवे ने इस साल की शुरुआत में एक विस्टाडोम बोगी लगाई थी।

विस्टाडोम कोच की खासियत

प्रत्येक विस्टाडोम कोच में 15 सीट होंगी। इसमें दोनों तरफ पांच-पांच खिड़की वाली सीटें और शेष पांच सीटें बीच में होंगी। ग्रीष्मकाल में कूलिंग के लिए प्रत्येक कोच में दो एअर कंडीशनर की व्यवस्था होगी। अधिक गर्मियों के मौसम में कोच के भीतर आने वाली रोशनी को रोकने के लिए छत की कांच पर विंडो रोलर ब्लाइंड्स और हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स लगाए गए हैं। यात्रीगण चाहें तो ट्रेन के चलने की दिशा में सीट को कर सकते हैं। इसमें एलईडी लाइटिंग व उपकरणों को चार्ज करने के लिए मॉडयूलर टाइप स्विच व सॉकेट लगाए गए हैं। कोच में आधुनिक शौचालय का प्रावधान किया गया है।

लोगों को पसंद आने के कारण अब पूरी ट्रेन में विस्टाडोम बोगियां लगाई गई हैं। यात्री पारदर्शी छत वाली बोगियों से बर्फ और बारिश वाले बाहर के मनोहर नजारे का आनंद उठा सकेंगे। यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सीट की बुकिंग करा सकते हैं। व्यक्तिगत सीट चार्टर सेवा की परिकल्पना पर आधारित यह विस्टाडोम कोच वाली पहली भारतीय ट्रेन है। यह ट्रेन कालका स्टेशन से सुबह 7:00 बजे रवाना होगी और 12:55 बजे शिमला पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में यह ट्रेन शिमला से दोहपर 15:50 बजे चलेगी और रात्रि 21:15 बजे कालका पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बड़ोग रेलवे स्टेशन पर ठहरेगी। इस ट्रेन में कुल सात कोच होंगे। इसमें छह प्रथम श्रेणी एसी विस्टाडोम कोच और एक प्रथम श्रेणी कोच होगा।

प्रत्येक कोच में 15 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी और प्रथम श्रेणी कोच में 14 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। प्रति यात्री शुल्क 630 रुपए होगा। इस कोच में टिकट बुकिंग पर किसी छूट का कोई प्रावधान नहीं होगा।

www.readwhere.com

नवीन पटनायक ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी

भुवनेश्वर, 25 दिसंबर (भाषा)।

ओड़ीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वह हम सब के लिए प्रेरणास्रोत हैं। पटनायक 1997 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं।

तमिलनाडु के किसान ने बनाया प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर

तिरुचिरापल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

तमिलनाडु के एक किसान ने अपने खेत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया है और कहा कि वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित है और उसे इसका फायदा भी मिला है।

पी शंकर नाम के इस किसान ने यहां से करीब 63 किलोमीटर दूर इराकुड़ी गांव में पिछले सप्ताह मंदिर का उद्घाटन किया और वह प्रतिदिन आरती करता है। यह मंदिर आठ गुणा आठ फुट का है और इसकी फर्श पर टाइल लगी हुई है। लोगों के स्वागत के लिए परंपरागत रंगोली भी बनाई गई है। मंदिर की लागत करीब 1.2 लाख रुपए है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मूर्ति लगी है। मोदी की मूर्ति के दोनों तरफ परंपरागत दीप जलाए गए हैं। उनके माथे पर तिलक लगा है और मूर्ति में प्रधानमंत्री गुलाबी कुर्ते और नीले शॉल में दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि अय्या (प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मानजनक संबोधन) के मंदिर का निर्माण करीब आठ महीने पहले शुरू हुआ था।शंकर ने बताया कि कुछ दिक्कतों के चलते मैं इसे जल्दी नहीं पूरा कर सका और मंदिर का उद्घाटन पिछले सप्ताह हुआ। उन्होंने बताया कि उसे केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला और उसे प्रधानमंत्री की ऐसी पहल बेहद पसंद है। उन्होंने बताया कि मुझे किसानों की योजना के तहत 2000 रुपए (प्रधानमंत्री सम्मान निधि), गैस (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) और शौचालय की सुविधा (घर-घर शौचालय योजना) मिली।

भाजपा के तिरुचिरापल्ली क्षेत्र के प्रभारी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ला कन्नन ने बताया कि यह किसान पार्टी का सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने शंकर से पार्टी में शामिल होने और लोगों की भलाई के लिए काम करने का अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बुधवार को हैदराबाद में पथ संचालन करते हुए।

ग्वालियर में प्रशंसकों ने मनाई वाजपेयी की 95वीं जयंती

ग्वालियर, 25 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशंसकों ने उनकी 95वीं जयंती पर बुधवार को उनके पैतृक निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वाजपेयी के प्रशंसकों के एक समूह ने यहां सत्यनारायण की टेकरी पर बने उनके मंदिर में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

ग्वालियर से भाजपा सांसद विवेक शेजवलकर और भाजपा कार्यकर्ता सुबह शिंदे की छावनी स्थित वाजपेयी के पैतृक घर पहुंचे और दिवंगत नेता की तस्वीर को माला पहनाई। ग्वालियर वाजपेयी का जन्म स्थान है और अब उनके पैतृक आवास में एक पुस्तकालय चलाया जाता है।

ग्वालियर से भाजपा सांसद विवेक शेजवलकर और भाजपा कार्यकर्ता सुबह शिंदे की छावनी स्थित वाजपेयी के पैतृक घर पहुंचे और दिवंगत नेता की तस्वीर को माला पहनाई। ग्वालियर वाजपेयी का जन्म स्थान है और अब उनके पैतृक आवास में एक पुस्तकालय चलाया जाता है। शेजवलकर ने राष्ट्र निर्माण में वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम अटलजी ने शुरू किया, जो अभी तक चल रहा है। उन्होंने राजमार्ग विकसित किए, जिससे पूरे देश का विकास हुआ। इसी विकास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना है। अटलजी विकास के पर्याय थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय जेल में कैदियों के बीच कंबलों का वितरण किया। वाजपेयी समर्थकों के एक अन्य समूह ने अधिवक्ता विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में सत्यनारायण की टेकरी स्थित अटल जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा के सामने आरती की। इस मंदिर का निर्माण चौहान ने लगभग एक दशक पहले किया था। चौहान ने इस अवसर पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया। एक अन्य संगठन अटल स्मृति मंच ने भी वाजपेयी की जीवन पर आधारित एक नाटक का मंचन किया।

अवैध विदेशी नागरिकों के लिए बना कर्नाटक का पहला हिरासत केंद्र

बंगलुरु, 25 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में चल रहे प्रदर्शनों के बीच यहां के निकट सोंदेकोप्पा गांव में कर्नाटक का पहला हिरासत केंद्र बनकर तैयार हो गया है, जहां अवैध रूप से भारत आने वाले और रह रहे विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा।

सामाजिक कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर कई कमरों, एक रसोई और शौचालयों से युक्त इस हिरासत केंद्र को तैयार किया गया है। हालांकि, राज्य के गृहमंत्री बसवराज बोम्मई ने 'हिरासत केंद्र' शब्द पर एतराज जताया।

संवाददाताओं से मंगलवार को उन्होंने कहा था, 'मानदंडों के आधार पर बात करें तो यह हिरासत केंद्र नहीं है। किसी को भी नागरिकता के मुद्दे पर हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है।'

उन्होंने इससे साफ इंकार किया कि यह केंद्र चालू हो गया है। उन्होंने कहा, '.....कृपया सामाजिक कल्याण विभाग से इसकी पुष्टि करें। कम से कम मुझे ऐसी सूचना नहीं है कि यह चालू हो गया है।' उन्होंने कहा, 'यह यह चालू हो गया है तो हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को वहां होना चाहिए? वहां कोई नहीं है।'

बोम्मई का कहना है कि इस केंद्र को इसलिए तैयार किया गया है ताकि देश में वीजा अवधि से ज्यादा वक्त से रह रहे और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अफ्रीकी नागरिकों को वहां रखा जा सके।' उन्होंने कहा कि ऐसे अफ्रीकी नागरिकों की गैरकानूनी गतिविधियों से देश में कानून-व्यवस्था संबंधी दिक्कतें पैदा हो रही हैं।

उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ उन्हें वहां रखने और देश वापस भेजने के लिए है।' वहीं, सामाजिक कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें निर्देश मिला है कि 'केंद्रीय राहत केंद्र (सीआरसी)' को एक जनवरी से पहले तैयार कर लिया जाए।

20 साल पुराना यह भवन कभी गरीब और वंचित तबके के छात्रों के लिए हॉस्टल होता था लेकिन समय के साथ-साथ विद्यार्थियों की संख्या कम होती गई और दो साल से यह खाली पड़ा था। इस परियोजना में सामाजिक कल्याण विभाग को शामिल करने की वजह समझाते हुए अधिकारी ने बताया, 'हिरासत में लिए जाने वाले लोगों को भोजन, रहने की जगह और कपड़े सामाजिक कल्याण विभाग उपलब्ध कराएगा।'

किसी ने संसदीय समिति की बैठकों में नहीं किया सीएए का विरोध : बागडे

औरंगाबाद (महाराष्ट्र), 25 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को दावा किया कि किसी भी पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का उस समय विरोध नहीं किया था, जब इसे एक संसदीय समिति के पास भेजा गया था। उन्होंने कहा कि सभी दलों के सांसद समिति का हिस्सा थे, इसलिए गैर-भाजपा दल अब संशोधित अधिनियम को लेकर हल्ला क्यों मचा रहे हैं।

सीएए और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के समर्थन में शहर में क्रांति चौक से औरंगपुरा तक निकाले गए मार्च के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए बागडे ने दावा किया कि संयुक्त समिति को विधेयक भेजने का निर्णय लिया गया, जिसमें हर पार्टी के सांसद शामिल थे।

गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए वैश्विक कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

भूजल और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले 92 देशों के करीब 1,100 वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित लोगों ने सभी सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे वैश्विक स्तर पर भूजल उपलब्धता बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

एक बयान में समूह ने कहा कि पृथ्वी का 99 फीसद ताजा पानी (पीने योग्य मीठा पानी) भूजल के रूप में है। इस कारण यह पीने के पानी, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की दिशा में बेहतर करने, जैवविविधता को बनाए रखने, धरती के ऊपर मौजूद ताजा जलस्रोतों को बनाए रखने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति महत्त्वपूर्ण है।

समूह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दुर्भाग्यवश कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर या तो नीचे गिर गया है या फिर वह प्रदूषित हो गया है। इससे सामाजिक-आर्थिक विकास को नुकसान पहुंच रहा है, जल और खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो रही है और हमारी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है। इस समूह में शामिल और आईआईटी खड़गपुर में एसोसिएट प्रोफेसर अभिजित मुखर्जी ने बताया कि मानव इतिहास में इस समय हम भारत में सबसे ज्यादा भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने जीवन के आधार, तुलनात्मक रूप से एक अनवीकरणीय संसाधन को तेजी से समाप्त कर रहे हैं। मुखर्जी और अन्य लोगों ने रेखांकित किया कि भूजल से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों को अकसर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियों में जगह नहीं मिलती है।

भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो का अधिकारी 18 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

अमदाबाद, 25 दिसंबर (भाषा)।

गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के एक पुलिस निरीक्षक को सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी से कथित तौर पर घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी अमदाबाद में पुलिस उपाधीक्षक भारती पांड्या ने बताया कि जूनागढ़ में पदस्थ निरीक्षक डीडी चावड़ा को मंगलवार रात अमदाबाद के बाहरी क्षेत्र सनातन सर्किल से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वह घूस में 18 लाख रुपए नकद ले रहा था। पशुपालन विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक ने 2018 में जूनागढ़ के एसीबी में 10.16 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने जूनागढ़ जिले के पटला गांव के सरपंच और पांच अन्य पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। यह पैसा संयुक्त गोचर भूमि के विकास के लिए आया था।

पांड्या ने बताया कि मामले की जांच चावड़ा कर रहे थे। उन्होंने शिकायतकर्ता को कथित तौर पर धमकी दी कि वह इस मामले में उसे ही फंसा देंगे, बल्कि कुछ और मामलों में उसके खिलाफ जांच शुरू कर देंगे। चावड़ा ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में वह 18 लाख रुपए लेने पर सहमत हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एसीबी के उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया और फिर जाल बिछाकर चावड़ा को गिरफ्तार किया गया।

व्यक्तिगत

मैं विनोद कुमार पु. श्री राम चन्द निवास सेक्टर ए, पो ए, मकान-1234, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, अपना नाम बदलकर विनोद खट्टर करता हूँ हर प्रकार के इस्तेमाल के लिए।

I,MD. ALAM,S/O-MD. AAKAL,R/O-B-1722,SHASTRI NAGAR, DELHI-110052,have changed my name to ZUL-FAQAR ALAM for future. 0040525440-3

I,ANSHUL AGRAWAL,S/O-KRISHAN KUMAR AGGARWAL,R/o-3173,FIRST FLOOR, GALI SANG-TARASHAN, PAHARGANJ, SWAMI TIRATH NAGAR,DELHI-110055 have changed my name to ANSHUL AGGARWAL for future. 0040525440-2

I, Vani Kumar D/o Sh. Prem Kumar Ganesan R/o 13A/4, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi-110005, have changed my name to Vaani Kumar for all purposes. 0040525330-1

I, Sukhdev S/O, Payara Singh R/o Ugf-4, Plot# 1243, Sector 5, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201012 have changed my name to Sukhdev Luthra for all purposes. 0070689871-1

I, Khagesh S/o Shashi Kumar Goyal R/o K-2/24, Krishan Vihar, New Delhi-110086, have changed my name to Khagesh Goyal for all purposes. 0040525383-1

I, Jyoti W/O Sarbjit Singh R/O-B-27/6,Double Storey Ramesh Nagar,New Delhi-110015,Have Changed My Name To Jyoti Arora For All Future Purposes. 0040525440-4

I, Anuradha Chouhan W/o Chander Mohan Singh R/o G-251B Sector-22 Noida have changed my name to Anuradha Chauhan permanently. 0040525436-1

I Satbir Bhardwaj S/o Umrao Sharma R/o A-180, 2nd Floor, Majlis Park, Adarsh Nagar, Delhi-110033, have changed my name to Satbir Sharma. 0070689872-1

I, Sreeja Suji W/o Suji C Ayyar R/o Flat No-202, Grace Apartment, Gali No-5, Raj Nagar Part-1, Palam Colony, New Delhi-110077, have changed my name Sreeja OS to Sreeja Suji for all future purposes. 0040525344-1

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

क्यू ईनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	क्यू ईनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	03.11.2009
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U73100DL2009PTC195676
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	41-ए, 3रा तल, गली नं. 1, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली-110029
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	आदेश देने की तिथि: 20.11.2019 आदेश की प्रति प्राप्त हुई: 24.12.2019 को
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	21.6.2020 (आदेश की प्राप्ति की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के रूप में कार्यरत है	नाम: अनुराग शर्मा पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00209/2017-18/10728
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का पता एवं ईमेल:	पता: 40, एलजीएफ, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 ईमेल आईडी: anurag.s.irp@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पता: 40, एलजीएफ, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024 ईमेल: irp.Qnnovations@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	7.1.2020 (आदेश की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन)
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	निल
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेब लिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली ने सीपीआईबी-1602/ एनडी/2019 में 20.11.2019 को तथा जिसकी प्रति 24.12.2019 को प्राप्त की गई, क्यू ईनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद् द्वारा क्यू ईनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि मद सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के पास 7.1.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए कृपया लिंक http://www.ibbi.gov.in/home/downloads देखें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता/-

(अनुराग शर्मा)

तिथि: 26.12.2019 इन्साल्वेन्सी प्रॉफेशनल

स्थान: नई दिल्ली IBBI/IPA-002/IP-N00209/2017-18/10728

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT

IAS & HOW TO CRACK IT

FREE SEMINAR

TILAK NAGAR

Sun. 29th Dec. 2019

10 A.M. to 12 P.M.

4 P.M. to 6 P.M.

NIRVANA IAS ACADEMY

Batches Start 5th January 2020

Weekend Batches Available

www.nirvanaias.com

ROHINI: H-17/262, Near Rohini West Metro Station, (Opp. Metro Pillar No.424), Sector - 7, Rohini, New Delhi - 85.

TILAK NAGAR: 30/4, Ashok Nagar, Near Tilak Nagar Metro Station, Gate No- 3, New Delhi - 18.

Ph: 011-47032447, 011-25121005, 9990471004, 9990471005

LAST BATCH FOR 2020 PRELIMS

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

नगालैंड में क्रिसमस के जश्न पर सीएए का कोई असर नहीं

कोहिमा, 25 दिसंबर (भाषा)।

ईसाई बहुल नगालैंड में क्रिसमस के जश्न पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। ईसाई मत को मानने वाले सभी डिनोमिनेशन के लोग राज्य में रीति रिवाज से क्रिसमस का पर्व मना रहे हैं और 'विशेष प्रार्थना सभा' व दावत का आयोजन कर रहे हैं।

कैरोल गान के बाद हुए मध्यरात्रि की प्रार्थना सभा के बाद श्रद्धालुओं ने रंगीन परिधान पहन कर चर्चों में प्रार्थना सभाओं में भाग लिया। इसके बाद प्रतिवर्ष की भांति सभी ने दावत में हिस्सा लिया।

नगालैंड में जनजातीय संगठनों की शीर्ष संस्था नगा होहो के महासचिव के एलु नदांग ने कहा कि वह सीएए का विरोध करते हैं, क्योंकि इस कानून से राज्य के मूल निवासियों का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि हम सीएए लागू होने के कारण असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका क्रिसमस से कोई लेनादेना नहीं है। नदांग ने कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह और उनके अनुयायियों के बीच संबंध का पर्व है, इसलिए विरोध के बावजूद सीएए लागू होने से नगालैंड के उत्सव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

नार्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपुल्स फोरम नामक संगठन के सदस्य जोशुआ नेवमई ने कहा कि अभी उत्सव के कारण छुट्टियां चल रही हैं और क्रिसमस और नववर्ष के जश्न के बाद सीएए के खिलाफ विरोध फिर शुरू होगा।

पवार विजय और हर्षवर्द्धन एक मंच पर

पुणे, 25 दिसंबर (भाषा)।

राकांपा के दिग्गज नेता विजय सिंह मोहिते पाटिल और भाजपा के नेता हर्षवर्द्धन पाटिल बुधवार को यहां कार्यक्रम में राकांपा प्रमुख शरद पवार के साथ मंच पर नजर आए।

पूर्व मंत्री मोहिते पाटिल का बेटा 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गया था। वहीं हर्षवर्द्धन पाटिल पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा नेता हैं। अक्तूबर में हुआ विधानसभा चुनाव वह हार गए थे। वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट की सालाना महासभा में तीनों नेता गुफ्तगु करते दिखे। पवार इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। राकांपा नेता अजीत पवार भी कार्यक्रम में हर्षवर्द्धन पाटिल से बातचीत करते नजर आए।

एटीएम काटकर अज्ञात बदमाशों ने आठ लाख लूटे

धौलपुर, 25 दिसंबर (भाषा)।

शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात बदमाशों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा का एटीएम काटकर आठ लाख रुपए लूट लिए। बैंक प्रशासन को वारदात की जानकारी बुधवार सुबह मिली। बैंक के प्रबंधक की ओर से निहालगंज थाने में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है।

पुलिस ने बताया कि शहर के आरएसी लाइन इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के बाहर स्थित एटीएम को काटकर अज्ञात बदमाशों ने 8 लाख 34 हजार 700 रुपए लूट लिए। अपर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया के बैंक के सीसीटीवी में आए बदमाश के हुलिए के आधार पर धौलपुर और आसपास के इलाकों में तलाश की जा रही है। वत्ताधिकारी (शहर) देवीसहाय मीना ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहायक प्रबंधक हेमंत मीणा ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है। बैंक के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने बीती रात करीब 2:52 बजे पर इस वारदात को अंजाम दिया है।

ओड़ीशा के राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं

भुवनेश्वर, 25 दिसंबर (भाषा)।

ओड़ीशा के राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को लोगों को क्रिसमस की शुभकामना दी। यह त्योहार पूरे राज्य में उल्लास और प्रसन्नता के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने जारी संदेश में त्योहार को शांति, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए लोगों की खुशी और समृद्धि की कामना की।

पटनायक ने अपने संदेश में कहा, 'क्रिसमस के मौके पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। क्रिसमस की बधाई।' इस मौके पर पूरे राज्य में गिरजाघरों को सजाया गया था और लोग विशेष प्रार्थना व आधी रात में प्रार्थनासभा में शामिल हुए। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कंधमाल जिले में शांति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तुमुदीबंध, बालीगुडा, टिकाबाली और जिला मुख्यालय नगर फूलबनी में पर्याप्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

गोवा में नाबालिग से बलात्कार, दो श्रमिक गिरफ्तार

पणजी, 25 दिसंबर (भाषा)।

दक्षिण गोवा के गांव में दो श्रमिकों ने कथित तौर पर 12 साल की नाबालिग लड़की का बलात्कार किया। पुलिस के अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आरोपी मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। उन्हें मंगलवार की शाम में गिरफ्तार किया गया। इसी दिन उन्होंने कथित घटना को अंजाम दिया था। क्वेपेम के पुलिस निरीक्षक संतोष देसाई ने बताया कि नाबालिग के पिता की शिकायत के बाद दोनों श्रमिकों को हिरासत में लिया गया। शिकायत में कहा गया कि लड़की घर में सो रही थी जब आरोपियों ने उसका बलात्कार किया। एक आरोपी 18 वर्ष का है जबकि दूसरे की पहचान 20 वर्षीय जितेंद्र चौधरी के तौर पर हुई है। दोनों आरोपी पीड़ित लड़की के पिता के परिचित थे और उनके घर पर उनका आना जाना था। दोनों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सबंद्ध धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

डीयू में सीएए और एनआरसी के खिलाफ आयोजित रैली में लेखिका अरुंधति रॉय ने कहा,

'एनपीआर का भी विरोध होना चाहिए'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के विरोध का आह्वान करते हुए बुधवार को दावा किया कि एनपीआर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए डेटाबेस का काम करेगा। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में कला संकाय पर आयोजित एक सभा को संबोधित कर रही थीं। इस सभा में रॉय के अलावा बॉलीवुड अभिनेता मुहम्मद जीशान अयुब और अर्थशास्त्री अरुण कुमार भी उपस्थित रहे। इसे जॉइंट कमेटी फॉर एक्शन अंगेस्ट सीएए-एनआरसी और संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आयोजित किया गया।

रॉय ने कहा कि एनपीआर के अंतर्गत अधिकारी लोगों के घरों तक जाकर उनका नाम पता और अन्य जानकारी एकत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि वे आपके घरों तक जाएंगे, आपका नाम, फोन नंबर, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कागजात के बारे में पूछेंगे। हमें इसके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से लड़ना होगा। जब वे एनपीआर के लिए आपके घर आएं तो आप उन्हें कोई और नाम बता दें। पते के लिए आप उन्हें 7 आरसीआर बताएं। हमें दबाने के लिए बहुत सारी ताकतें लगेंगी। हम लोग लाठी और गोली खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं।

रॉय ने प्रधानमंत्री के ऊपर यहां रविवार को रामलीला मैदान रैली में एनआरसी प्रक्रिया के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि देश में डिटेंशन सेंटर या हिरासत केंद्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पकड़े जाएंगे यह जानते हुए भी उन्होंने (प्रधानमंत्री) झूठ बोला क्योंकि उनके पास मीडिया है जो उनसे सवाल नहीं पूछेगा। उन्होंने कहा कि जो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें विभिन्न राज्यों से बाकायदा आश्वासन लेना चाहिए कि वे इस प्रावधान को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सीएए और एनआरसी का व्यापक स्तर पर विरोध होने के बाद सरकार इसके प्रावधानों को एनपीआर के जरिए लागू करवाना चाहती है। रॉय ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुसलिमों पर हमला कर रही है और उनका दमन कर रही है। उनके अनुसार सीएए और एनआरसी मुसलिमों के अलावा दलितों, आदिवासियों और देश के गरीब लोगों के भी खिलाफ है।

वहीं, बॉलीवुड अभिनेता जीशान आयुब ने कहा कि सीएए के खिलाफ आंदोलन को लेकर जिस तरह से सरकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यह इस बात की पुष्टि है कि वह इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने इस आंदोलन को शुरू किया है और यह सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा कभी दुनिया में हुआ है कि किसी कानून के समर्थन में भी लोगों को प्रदर्शन करना पड़े। इसका मतलब समझ में आ गया है कि इन लोगों के मन में डर बैठ गया है और यह लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे समर्थन में प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि हमें सीएए के खिलाफ इसी तरह से आंदोलन को जारी रखना है और जीतेंगे हम ही। छात्रों के पास जो ताकत है, उसके सामने कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती है।

जामिया में प्रदर्शन स्थल पर मनाया क्रिसमस

सीएए और एनआरसी के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहे। क्रिसमस होने की वजह से लोगों ने प्रदर्शन स्थल पर ही क्रिसमस मनाया। यहां कुछ लोग और बच्चे सांत क्रॉज का भेष धरकर पहुंचे और इन्होंने लोगों को शांति का संदेश दिया। प्रदर्शन स्थल पर क्रिसमस ट्री को भी सजाया गया था।

'आप' के रिपोर्ट कार्ड के बाद भाजपा तैयार करेगी आरोपपत्र

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (आप) के रिपोर्ट कार्ड के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक चार्जशीट तैयार करेगी। यह चार्जशीट बताएगी कि 'आप' ने दिल्ली चुनाव से पहले क्या वादे किए थे और कौन से वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया है। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अगुआई में हुई एक बैठक में इसकी रणनीति तैयार की है। चार्जशीट का मकसद 'आप' के तमाम दावों की पोल खोलना होगा।

आने वाले दो माह में दिल्ली के चुनाव होने हैं। इन चुनावों की रणनीति क्या हो। इसके लिए बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुआई में दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पार्टी चुनाव प्रभारी समेत पार्टी के सांसद व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। बैठक में दिल्ली की चुनाव रणनीति पर चर्चा की गई और यह तय किया कि दिल्ली भाजपा जल्द ही 'आप' के रिपोर्ट कार्ड की तर्ज पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट को पार्टी चार्जशीट का नाम देने जा रही है और आने वाले दो दिन में ही इस रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। इस चार्जशीट के माध्यम से 'आप' के तमाम दावों की पोल खोली जाएगी। यह चार्जशीट 27 दिसंबर को जारी होगी। इसके अतिरिक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जनवरी के पहले ही सप्ताह में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। पांच जनवरी को यह सम्मेलन होगा। इसे भाजपा की पंच परमेश्वर नीति के तहत जोड़ा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने बताया कि 'आप' ने चुनाव से ठीक पहले जनता से 70 वादे किए थे। इन वादों को दिल्ली सरकार पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे ही वादों में सबसे गंभीर मसला पर्यावरण का है। केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ पूर्वी व पश्चिमी कॉरिडोर बनाकर आम जनता को भीषण जाम से राहत दी है। वहीं, प्रदूषण को कम करने के लिए भी पहल की है। लेकिन दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की तरफ ध्यान नहीं दिया है।

झारखंड से सबक, स्थानीय मुद्दों पर जाएंगे

झारखंड के चुनाव में पार्टी को राष्ट्रीय मुद्दों का अधिक लाभ नहीं मिला है। सूत्र मानते है कि सत्ता पक्ष को स्थानीय मुद्दों पर घेरकर ही जनमत को जोड़ जा सकता है। इसी रणनीति के तहत भाजपा आने वाले दिनों में दिल्ली के स्थानीय मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में नजर आएगी। इन मुद्दों के आधार पर ही दिल्ली का चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के चुनाव के लिए 'आप' का मुफ्त कार्ड तोड़ना ही भाजपा के लिए सबसे बड़ी कूटनीति होगी। क्योंकि दिल्ली सरकार की इन योजनाओं का आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। ये योजनाएं ही आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने की तरफ इशारा कर रही हैं।

पांच साल में 100 फीसद क्षेत्रों में मिलेगा नल से पानी : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के 93 फीसद हिस्सों में नल से पानी पहुंचता है। आने वाले पांच साल में दिल्ली सरकार 100 फीसद क्षेत्र में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त यमुना नदी को भी साफ व स्वच्छ बनाने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को महरौली में भूमिगत जलाशय का उद्घाटन किया।

केजरीवाल ने कहा कि इस जलाशय की क्षमता 18 लाख लीटर है, इससे कई इलाकों में पानी की समस्या का समाधान होगा। इसकी मदद से किशनगढ़ व महरौली वालों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पांच साल पहले जब सरकार बनी थी उस समय 58 फीसद दिल्ली को ही नल से पानी आता था। इसके अतिरिक्त 40 फीसद क्षेत्र में टैंकर से पानी आपूर्ति की जाती थी। राजधानी में 70 साल में कोई भी सरकार जनता को नल से पानी नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पांच साल में युद्ध स्तर पर पाइप लाइन बिछाई है और अभी सात फीसद क्षेत्र में भी काम चल रहा है। इसे भी जल्द पूरा किया जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि टैंकर माफिया की आड़ में दिल्ली में पानी का गोरखधंधा चल रहा था। इससे पूर्व विधायकों को 12 लाख रुपए तक प्रतिमाह कमाई होती थी। पांच साल पहले आप जनता ने इमानदार सरकार बनाई थी और ये इसी का नतीजा है। अब हर घर में पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां चार दिन में या दो दिन में पानी आता है। अगले पांच साल में चौबीस घंटे नल से मिलेगा। किसी को भी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बाहर के राज्यों से पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं और भूजल संचयन की योजना को भी लागू कर रहे हैं। यमुना बड़ी गंदी है। इस नदी को पांच साल में साफ किया जाएगा।

नया स्पोर्ट्स कांपलेक्स शुरू

दिल्ली सरकार ने बुधवार को नजफगढ़ क्षेत्र में नए स्पोर्ट्स कांपलैक्स की शुरुआत की। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस स्टेडियम की शुरुआत की। यह स्टेडियम स्टेट ऑफ तकनीक से तैयार किया गया है और इस पर करीब 147 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्टेडियम 18.20 एकड़ में तैयार किया गया है।

पानी की गुणवत्ता को लेकर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में गंदे पेयजल के मुद्दे पर लोगों में असंतोष है और यह चिंता का विषय बना हुआ है। अटल जल योजना की शुरूआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने इन दिनों दिल्ली में देखा होगा कि पानी को लेकर कितनी जागरूकता है। जनता में गुणवत्ता को लेकर असंतोष भी है।

उन्होंने कहा कि हर तरफ इस बात की चिंता है कि दिल्ली में पीने का पानी गंदा है। यह चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को सीधे आप सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में भी पानी की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। दिल्ली में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आने वाले समय में 3.5 लाख करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए खर्च करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जांच में यह बात सामने आई कि राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल सुरक्षित नहीं है।

साहित्यकार विमल का श्रीलंका में सड़क हादसे में निधन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

साहित्यकार गंगा प्रसाद विमल और उनके दो परिजनों का दक्षिण श्रीलंका में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। 80 वर्षीय विमल परिवार के साथ श्रीलंका की निजी यात्रा पर गए थे। सड़क हादसे में विमल के साथ उनकी बेटी कनुप्रिया और नाती श्रेयस का भी निधन हो गया। उन्होंने बताया कि तीनों के पार्थिव शरीर बुधवार देर रात यहां पहुंचने की संभावना है।

विमल के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शोक प्रकट किया। श्रीलंका से आई खबर के अनुसार पुलिस ने बताया कि विमल अपने परिजनों के साथ दक्षिणी श्रीलंका में वैन से यात्रा कर रहे थे जो सोमवार रात सदर्न एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई। वैन दक्षिणी बंदरगाह शहर गाले से कोलंबो की ओर जा रही थी। पुलिस ने बताया कि तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 52 वर्षीय श्रीलंकाई वाहन चालक की भी मृत्यु हो गई। दुर्घटना में विमल के दामाद योगेश सहगल और नातिन ऐश्वर्या घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विमल के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया कि हिंदी के शीर्षस्थ रचनाकार डॉ. गंगा प्रसाद विमल, उनकी पुत्री व नाती की सड़क हादसे में अकस्मात मृत्यु की खबर अत्यंत दुःखद है। उत्तरकाशी में जन्मे विमल हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते थे'। निशंक ने ट्वीट किया, 'विमल के निधन से साहित्य जगत की अपूरणीय क्षति हुई है, मुझे भी व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। मैं ईश्वर से दिवंगत लोगों की आत्माओं की शांति की कामना करता हूं व दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।' जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान समेत विभिन्न संस्थानों में प्रमुख जिम्मेदारियां निभा चुके विमल लेखक और कवि होने के साथ ही बड़े समीक्षक तथा अनुवादक भी थे। विमल का जन्म 1939 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। उनके प्रसिद्ध कविता संग्रहों में 'बोधि-वृक्ष', 'इतना कुछ', 'सन्नाटे से मुठभेड़', 'मैं वहां हूं' और 'कुछ तो है' आदि हैं। 2013 में प्रकाशित उनका अंतिम उपन्यास 'मानुसखोर' है। विमल के कहानी संग्रह 'कोई शुरुआत', 'अतीत में कुछ', 'इधर-उधर', 'बाहर न भीतर' और 'खोई हुई थाती' का भी हिंदी साहित्य में अपना स्थान है।

विमल, उनकी पुत्री व नाती की सड़क हादसे में अकस्मात मृत्यु की खबर अत्यंत दुःखद है।

उन्होंने उपन्यास, नाटक, आलोचना भी लिखीं तो कई रचनाओं का संपादन कार्य भी किया। विमल को भारतीय भाषा पुरस्कार, संगीत अकादमी सम्मान समेत अनेक भारतीय पुरस्कारों और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से भी नवाजा गया। वाणी प्रकाशन के निदेशक अरुण माहेश्वरी ने कहा कि उनके निधन की खबर सुन कर हम स्तब्ध हैं। हादसा विदेश में होने के कारण हमें तीन दिन बाद पता चल पाया। यह मेरे लिए निजी क्षति है। वे मेरे अध्यापक थे। अगर उनके साहित्य की बात की जाए तो वे निर्विवाद व्यक्ति थे। वे किसी विवाद और फतवे से बाहर थे। साहित्य में उनकी दृष्टि मानवतावादी थी। उनका व्यवहार बच्चों जैसा था। केदारनाथ सिंह तो उन्हें देखते ही 'कहो, बच्चा' बोलते थे। जनवादी लेखक संघ के महासचिव मुरली मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि रचनाकार के रूप में वे अपनी विशिष्टता, सादगी तथा विद्वता के लिए जाने जाते थे, उन्हें हमारा सादर नमन।

सोनिया के सामने ही भिड़ गए चोपड़ा और आजाद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

दिल्ली की नई विधानसभा के गठन के लिए करीब डेढ़ महीने बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर जहां सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं, वहीं सूबे के कांग्रेसियों को आपस में ही दो-दो हाथ करने से फुरसत नहीं है। पार्टी के आला नेताओं में आपसी मतभेद का आलम यह है कि प्रदेश के कांग्रेसी मुखिया सुभाष चोपड़ा और पार्टी की प्रचार अभियान समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने ही आपस में भिड़ गए। सोनिया ने दोनों को समझा-बुझाकर एक साथ मिलकर काम करने की ताकीद की। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के बीच पैदा हुए विवाद को

- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं को समझाया
- पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी

सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी।

सूत्रों की मानें तो प्रदेश अध्यक्ष चोपड़ा व प्रचार अभियान समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद मंगलवार देर शाम दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। बताते हैं कि चोपड़ा ने गांधी से यह शिकायत की कि कीर्ति आजाद के समर्थन में दिल्ली में लगाए जा रहे पोस्टरों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद उनकी फोटो नहीं लगाई जा रही। इसके जवाब में आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष को बताया कि उन्होंने बहुत पहले एक गैर राजनीति पूर्वांचल क्रांति संघ का गठन किया था। उसी के तहत कुछ लोगों ने दिल्ली में कुछ पोस्टर लगाए हैं। उसमें चोपड़ा की फोटो जानबूझकर नहीं लगाने का कोई मतलब नहीं है। आजाद ने उल्टे चोपड़ा पर आरोप लगाया कि वे पोस्टर में उनकी फोटो लगाना तो दूर प्रदेश के कार्यक्रमों और पार्टी की बैठकों तक की खबर उन्हें नहीं देते।

कांग्रेस अध्यक्ष के सामने ही चोपड़ा ने आजाद से पूछा कि आप सही सही बताओ कि जब आप फोन करते हो तो मैं आपको बताता हूं अथवा नहीं कि कब कौन सा कार्यक्रम होगा। इस पर आजाद ने कहा कि क्या मैं रोज सुबह आपको फोन करके रोज का कार्यक्रम पूछूं? बताते हैं कि चोपड़ा ने आजाद को लेकर यह भी कहा कि वे दिल्ली में एक खास गुट के साथ जुड़ गए हैं। इस पर आजाद ने सोनिया गांधी से कहा कि मैं केवल कांग्रेस के गुट में हूं और किसी के गुट में नहीं हूं। प्रदेश कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच इस तल्ख संवाद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों को सख्त लहजे में ताकीद की कि वे आपस में मिलजुल कर काम करें और किसी भी सूरत में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने केसी वेणुगोपाल को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे इस विवाद को सुलझाएं। उन्होंने दोनों कांग्रेसी नेताओं से भी कहा कि आगे से कोई भी विवाद होने पर वे वेणुगोपाल से संपर्क करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर पूछने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चोपड़ा ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई है हालांकि उन्होंने किसी विवाद या राजनीतिक बातचीत से इनकार किया। कीर्ति आजाद ने भी माना कि चोपड़ा व अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ वे कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने गए थे। उन्होंने वहां हुए घटनाक्रम को लेकर कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया।

जेएनयू में पहली बार संस्कृत में आयोजित होगा सम्मेलन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पहली बार संस्कृत भाषा में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें सभी संभाषण और संचालन संस्कृत में होंगे। विश्वविद्यालय के संस्कृत व प्राच्य विद्या संस्थान की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन का विषय 'भारतीय ज्ञान परंपरा का स्रोत संस्कृत' रखा गया है। संस्थान के आचार्य व सम्मेलन निदेशक प्रो. रामनाथ झा ने बताया कि प्रज्ञा प्रवाह प्रतिष्ठान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी सम्मेलन में सहभागी होंगे।

सम्मेलन में गुरुकुल प्रभात आश्रम, मेरठ के कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद सरस्वती और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रो. आरसी सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। शुक्रवार के शुरू हो रहे सम्मेलन के पहले दिन सांची बौद्ध भारतीय विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. शशिप्रभा कुमार, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. पीयूष कांत दीक्षित, दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो. रमेश भारद्वाज, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष प्रो. वाचस्पति मिश्र और प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंदकुमार का संबोधन होगा। वहीं दूसरे दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अभिराजराजेंद्र मिश्र और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति प्रो. परमेरनारायण शास्त्री का संबोधन होगा।

कई नेताओं ने ली 'आप' की सदस्यता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बड़ा हो रहा है। बुधवार को दिल्ली के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ली। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी में शामिल हुए नए चेहरों को टोपी और पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया।

संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का परिवार लगातार विस्तार की दिशा में अग्रसर है। अलग-अलग राजनीतिक संगठनों के लोग अपनी-अपनी पार्टियों छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन सभी लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी संगठन को मजबूती मिल रही है। बुधवार को रोहतास नगर विधानसभा से वीरेंद्र कुमार शर्मा (अध्यक्ष, दिल्ली विद्यार्थी अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन), वेद प्रकाश शर्मा (अध्यक्ष, आदर्श मार्केट एसोसिएशन, 100 फुटा रॉड, शाहदरा), अंशुल कौशिक(पत्रकार), राजकुमार प्रजापति (पूर्व महासचिव, उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा, बीएसपी), ईश्वर गोयल (कार्यकारिणी सदस्य, आदर्श मार्केट एसोसिएशन शाहदरा के साथीगण पार्टी में शामिल हुए। मुखर्जी नगर क्षेत्र से राजिंदर कुमार जी (पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, सदर बाजार, बीएसपी), राजीव खेरा और डॉ रितु सिंह भी शामिल हुई।

खेल की प्रतिभाएं निखारेगी कमल क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता : तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बुधवार को कहा कि गंगा-जमुनी तहजीब की विरासत को आगे बढ़ाते हुए खेल प्रतिभाओं का विकास करना जरूरी है।

वे कमल क्लब प्रतियोगिता में शामिल हुए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यमुना चैलेंज ट्रॉफी का उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को सामने लाना है। गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक यमुना चैलेंज ट्रॉफी का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को खेल से जोड़कर समाज में समरसता का प्रवाह किया जाए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट देखने में जितना मजा आता है, उतना ही फायदा इस खेल को खेलने में होता है। ये एक ऐसा खेल है, जिसे खेलते रहने पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। यह कार्यक्रम नन्द नगरी आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तर पूर्वी जिला के अतिरिक्त उपायुक्त आनंद मिश्रा समेत भाजपा के अन्य नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अटल स्मृति स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की।

दिल्ली के चुनाव के लिए आयोग भी हुआ सक्रिय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। इसकी पहल के तहत बुधवार को आयोग ने दिल्ली के प्रमुख मॉल व जगहों पर चुनाव आयोग के सांता मैदान में उतरे। इसकी मदद से चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की और उन्हें यह भी समझाया कि ईवीएम से दिया गया हर मत सुरक्षित है। यह मत जिस पार्टी को डाला जाता है उसी प्रत्याशी को जाता है। दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि यह पहल आयोग ने 16 दिसंबर से शुरू की थी।

मौसम				
तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	12.7 डि.से.	12.7 डि.से.	11.1 डि.से.	13.4 डि.से.
न्यूनतम	6.0 डि.से.	6.0 डि.से.	6.0 डि.से.	6.0 डि.से.

कोचिंग सेंटरों के बंद होने की सूचना अफवाह : पुलिस

उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्या ने मामला दर्ज करने की बात बताई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय से सटे मुखर्जी नगर में तमाम कोचिंग सेंटरों को बंद किए जाने की खबरों को उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्या ने अफवाह बताते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस भ्रामक जानकारी के बारे में बुधवार को कहा कि मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटरों के बंद होने की खबर अफवाह मात्र है। इसे संपादित कर सोशल मीडिया में इससे संबंधित फर्जी खबरें साझा करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही हमने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से इस गलत खबर के वीडियोज को डिलीट करने की भी मांग की है।

बुधवार को उपायुक्त ने इस बाबत बताया कि वीडियो में कथित तौर पर यह दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी छात्रों से शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर होने के कारण 24 दिसंबर से दो जनवरी के बीच मुखर्जी नगर में न रहने के निर्देश दे रहा है। यह वीडियो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस के मुताबिक मुखर्जी नगर के थाना प्रभारी का एक 'फर्जी' नोटिस विद्यार्थियों के सोशल मीडिया ग्रुप्स में भेजा गया। इसमें दावा किया गया है कि इलाके में कोचिंग सेंटर और पेइंग गेस्ट (पीजी) बंद किए जा रहे हैं।

उपायुक्त आर्या ने कहा है कि हमने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी संदेशों के संबंध में एक मामला दर्ज किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वीडियो हटाने के लिए भी लिख रहे हैं क्योंकि इसमें कांटछांट की गई है। वायरल वीडियो में अधिकारी कथित तौर पर लोगों से कह रहा है कि मुखर्जी नगर में सभी पीजी, पुस्तकालय, कोचिंग सेंटर और रेस्तरां 24 दिसंबर से दो जनवरी तक बंद रहेंगे। उन्होंने छात्रों को टिकट बुक करने और सरदी की छुट्टी होने के कारण अपने घर जाने की सलाह दी है।

वीडियो में अधिकारी को लोगों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है, आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 लागू की गई और आगाह किया कि किसी तरह की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, आर्या ने कहा कि पुलिस ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया और इस वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। मुखर्जी नगर में पीजी और हॉस्टल बंद कराने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी संदेश भय व्याप्त करने के लिए फैलाए जा रहे हैं।

स्वराज पार्टी का आरोप, पुलिस जबरन बंद कर रही है कोचिंग सेंटर

स्वराज पार्टी का आरोप है कि मुखर्जी नगर में शिक्षकों और विद्यार्थियों को डरा धमकाकर दिल्ली पुलिस जबरन कोचिंग, पीजी और हास्टल बंद करवा रही है। बुधवार को युवा-हल्ला बोल की एक टीम ने मुखर्जी नगर पहुंचकर मामले का जायजा लिया और सभी पक्षों से बात की। पता चला कि दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर के प्रतिष्ठित शिक्षकों के साथ भी बदतमीजी की। पुलिस ने मुखर्जी नगर में आदेश दिया है कि 24 दिसंबर से दो जनवरी तक सब कुछ बंद रखा जाए। हैरत की बात है कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी अपने पुलिस की कार्रवाई से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं और इसे फर्जी संदेश करार दे रहे हैं।

किशोरी का अपहरण, नाबालिग हिरासत में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

शादी के लिए मजबूर कर 16 साल की किशोरी का अपहरण करने वाले एक आरोपी को नई दिल्ली जिला पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी नाबालिग और नशे का आदी भी है। इस बाबत बाराखंभा रोड थाना में मामला दर्ज किया गया था।

नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त ईश सिंघल ने बताया कि किशोरी की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया है। 20 नवंबर से किशोरी गायब थी। मां को संदेह था कि बंगाली मार्केट इलाके के किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी को अगवा किया है। पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को एक सूचना मिली कि किशोरी को सुल्तानपुरी-मंगोलपुरी जेजे क्लस्टर इलाके में छिपाकर रखा गया है। पुलिस ने जाल बिछाया और एक टीम को बताए ठिकाने पर तैनात किया गया। जैसे ही सूचना पुख्ता हुई, पुलिस ने आरोपी और किशोरी दोनों को दबोच लिया। आरोपी ने किशोरी को अपने चातुर्य और शानो शौकत भरा जीवन दिखाकर प्रभावित कर लिया था। वह किशोरी को शादी करने को मजबूर कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को बाल न्यायालय में पेश कर सेवा कुटीर भेज दिया है। किशोरी को उसके माता-पिता के हाथों सौंपते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

31 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड रहेगी जारी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 25 दिसंबर।

शीतलहर, कोहरे और वायु प्रदूषण की पड़ रही है मार

अधिकतम तापमान में सामान्य से नौ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई

पिछले 10 दिनों से कड़ाके की सरदी के बीच एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है, जब अधिकतम तापमान सामान्य रहा हो। दिन में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बुधवार को हल्की धूप निकलने पर भी शीतलहर से लोग कांपते रहे। अधिकतम तापमान में सामान्य से नौ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बेहद खराब श्रेणी में चल रहा है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक ऐसी ही स्थिति रहने और उसके बाद घटना कोहरा छाने की उम्मीद जताई है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सप्ताह कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान चार से छह डिग्री रहने की उम्मीद है। पिछले दिनों उच्च हिमालीय क्षेत्रों में हुए हिमपात के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमालय से आने वाली हवा हिमपात की ठंड भी ला रही है। साथ ही वातावरण में इस समय कम ऊंचाई वाले बादल छाए हुए हैं, जिससे सूरज की धूप भी पूरी तरह से नीचे नहीं आ रही है। इससे दिन के समय में भी मौसम गर्म नहीं हो पा रहा है। सप्ताहभर ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार पांच अत्याधिक ठंडे

फाइल फोटो

दिवस (सीवीयर कोल्ड डे) आ चुके हैं। 2014 में ऐसी कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा था। तब आठ और 2003 में नौ अत्याधिक ठंडे दिवस पड़े थे। 1997 में 17 दिन जकड़ने वाले ठंडे दिवस थे। ठंड और कोहरे के साथ वायु प्रदूषण के हालात भी बेहद खराब हैं। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 दर्ज किया। सेक्टर 125 में एक्यूआइ 380, सेक्टर-62 में 355 और सेक्टर- 1 में 402 दर्ज हुआ। अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण की ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है।

होटलों और बैंक्वेंट हॉल को देना चाहिए लाइसेंस : पवार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

होटल अर्पित पैलेस, रानी झांसी रोड और किराड़ी में आग लगने जैसी घटनाएं फिर न हों, इसके लिए सभी होटलों व बैक्वेंट हाल को लाइसेंस देने की वकालत करते हुए उत्तरी निगम में विपक्ष के नेता ने कहा कि निगम की अवैध यूनिपोल्स व विज्ञापनों पर कार्रवाई की जाए और निगम को आमदनी होने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही निगम भवनों, पार्किंग रेलिंग व पानी रहित मूत्रालय इत्यादि पर विज्ञापन के ठेके छोड़कर भी राजस्व बढ़ सकता है। सिविक सेंटर स्थित दक्षिणी निगम से बकाया किराए 1815.75 करोड़ रुपए की वसूली नहीं होने का कारण पता नहीं चल रहा।

2019-20 के संशोधित बजट अनुमानों और 2020-21 के बजट अनुमानों पर निगम की विशेष बैठक में विपक्ष के नेता सुरजीत सिंह पवार ने एक तरफ पिछले तीन सालों में निगम में सत्तारूढ़ भाजपा की झूठी घोषणाओं की कलई खोली। वहीं, विभिन्न विभागों से आय प्राप्त करने में उनकी नाकामयाबी उजागर कर दी। उत्तरी निगम आयुक्त के बजट प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विपक्ष के नेता ने माली हालत सुधारने के लिए निगम को कई सुझाव दिए।

पवार ने निगम के लेखा विभाग, सर्तकता विभाग व लेखा परीक्षण विभाग को भी आड़े हाथों लेते हुए विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया। प्रचलित खामियों पर निगम अधिकारियों को आइना दिखाया। सत्तारूढ़ भाजपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी 2017 में 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की रिहायशी संपत्तियों को 2017-18 से कर मुक्त करने की घोषणा, निगम वेबसाइट पर विज्ञापन देकर आय बढ़ाना, पेयजल के एटीएम लगाना, अभियांत्रिक विभाग की सालों से लंबित परियोजनाओं को अभी तक शुरू न कर पाना और आय प्राप्त न कर पाना निगम की विफलता की एक बानगी भर है। मिंटो रोड स्थित कप एंड सासर, मिंटो रोड बंगलों रोड़ स्टाफ क्वाटर्स की जगह व्यावसायिक निर्माण, नावेल्टी सिनेमा-पीली कोठी-नानी वाला बाग-रूप नगर-पुराना राजेंद्र नगर-यमुना बाजार हनुमान मंदिर के पीछे की जमीनों पर व्यावसायिक निर्माण, पार्किंग योजनाओं को लागू कर पार्किंग साइट्स पर निर्माण न कर पाना, बेला रोड पर डॉग होम बनाने की योजना के साथ आवारा कुत्तों, पशुओं व बंदरों पर नियंत्रण कर समस्या का निदान करना और प्रत्येक वार्ड में एक पैथोलॉजी लैब खोलना, एक नक्षत्र वाटिका, योग वाटिका, हर्बल पार्क का निर्माण, नरेला नर्सिंग होस्टल के खाली भवन को किराए पर देने जैसी घोषणाएं हवा हवाई साबित हुई है।

निगम मुख्यालय पर शिक्षकों का धरना जारी

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों को वेतन और एरिअर नहीं मिलने से खफा शिक्षकों का 17 दिसंबर से चला आ रहा आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ और शिक्षक संघ समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में निगम के सभी स्कूल के भारी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन के बाद भी निगम प्रशासन किसी भी मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पा रहा है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जातीं, उत्तरी निगम के खिलाफ मुख्यालय पर भीषण ठंड में भी यह धरना-प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा।

शौचालय ब्लॉक का उद्घाटन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन ने बुधवार को शालीमार बाग के कई ब्लाक में शौचालय ब्लॉक का उद्घाटन किया। यहां के बीक्यू मार्केट, एजी मार्केट, एडी मार्केट व बीएन वेस्ट एवर बैंक मार्केट में सभी टायलेट आधुनिक रूप में बनाए जाएंगे। महिलाओं, पुरुषों व दिव्यांग लोगों के लिए ये अलग-अलग होंगे। नेता सदन तिलक राज कटारिया ने कहा कि जनता से वार्ड-63 को उत्तरी निगम का सबसे बेहतर वार्ड बनाने के वादों को पूरा करते हुए एक आदर्श वार्ड बनाने की दिशा में उठाया गया यह कदम है। इसी वार्ड में अटल रसोई दस रुपए में सबसे पहले शुरू हुई थी।

उपमुख्यमंत्री ने अवैध प्लाटिंग के मामले में अधिकारियों को दिए निर्देश

फरीदाबाद, 25 दिसंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद के सेक्टर-55 में पूरानी ए-वन फैक्ट्री में अवैध रूप से की गई प्लाटिंग के मामले में अधिकरियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मामले में संलिप्त नगर निगम के अधिकारियों को आरोपपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री बुधवार की शाम को सेक्टर-12 स्थित कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क और परिवाद समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। चौटाला ने बैठक के दौरान फरीदाबाद निवासी चंद्रशेखर नागर के परिवाद की सुनवाई करते हुए नगर निगम अधिकारियों से जवाब तलब किया, लेकिन निगम के अधिकारी मामले में एक दूसरे पर टाल मटोल करते नजर आए। जिसपर उन्होंने फरीदाबाद के उपायुक्त को निर्देश दिए कि इस मामले में जिला के उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर जांच कारवाई जाए और औद्योगिक परिसर में अवैध रूप से प्लाटिंग करने के मामले में जवाबदेह अधिकारियों को चार्जशीट किया जाए। इसी तरह बैठक में सेक्टर-70 स्थित फेरोस मेगापोलिस सिटी का मामला भी सामने आया।

पुख्ता बंदोबस्त के बीच मनाया गया क्रिसमस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

क्रिसमस पर दिल्ली के गिरिजाघरों में मंगलवार देर रात से बुधवार शाम तक लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गोल डाकखाना के पास स्थित पवित्र गिरिजाघर में ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की शुभकामना दी। बुधवार को दिल्ली के सभी गिरिजाघरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इससे वहां यातायात जाम भी हुआ। उधर, जामिया में दक्षिणी-पूर्वी जिला के पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने भी एक कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चों के साथ इस पर्व को साक्षा किया।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार रात से ही क्रिसमस पर राजधानी के सभी ख्यात चर्चों के आसपास यातायात के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। दिल्ली में गोल डाकखाना, दस संसद मार्ग, और एक चर्च रोड स्थित चर्चों में प्रार्थना के लिए भारी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग जमा होते हैं। लोगों के आने से इन सभी इलाके में भारी भीड़ हो जाती है और यातायात जाम हो जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के इलाकों में सामान्य लोगों को परेशानी नहीं हो, अलबत्ता पुलिस ने गोल डाकखाना, अशोक

गिरजाघर में पहुंचे मुख्यमंत्री।

रोड, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, पटेल चौक, कनॉट प्लेस और बाबा खड़क सिंह मार्ग पर यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की। गोल डाकखाना पवित्र गिरिजाघर में आने वालों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए पंडित पंत मार्ग, जय सिंह रोड और चर्च रोड पर व्यवस्था की ताकि परेशानी न हो।

उधर हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन और हंगामे की वजह से चर्चा में आए जामिया नगर के नूरनगर में उम्दा सेंटर पर बच्चों के बीच मनाए जाने वाले क्रिसमस में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल पहुंचे। बिश्वाल ने सांता बने बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों को केक खिलाकर क्रिसमस की बधाई दी। इस मौके पर सेंटर के संचालक भी मौजूद रहे। राष्ट्रवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष अनिल भारती ने क्रिसमस की बधाई देते हुए लोगों से अपील की है कि वे सरकार के एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों पर हिंसक रूप अख्तियार नहीं करते हुए बातचीत का रास्ता अपनाएं। इस प्रकार के कानून बनने और फिर भरकाऊ दंगे और हंगामा से विदेश में रह रहे करोड़ों भारतीयों को अपमानित होना पड़ रहा है।

पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने भी बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस।

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में युवा जागरूकता सभा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 25 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में युवाओं ने बुधवार को सेक्टर-44 के स्टेलर अपार्टमेंट के पास जागरूकता सभा के कार्यक्रम का आयोजन किया। जहां नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को बताया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने बताया कि अनभिज्ञता में इस कानून को लेकर अराजकता फैलाई जा रही है। युवाओं को ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं, जिससे वे अज्ञानतावश हिंसक आंदोलन

करने पर आमादा हैं।

इस अवसर पर पुष्कर शर्मा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से देश के हिंदू व मुसलमान किसी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। यह कानून देश हित में है, जिसका फायदा सभी देशवासियों को मिलेगा। युवा कार्यकर्ता नितिन कुमार ने युवाओं से एकजुट होकर कानून का समर्थन करने की अपील की। इस अवसर पर अमित वशिष्ठ, मुकेश वाल्मीकि, सुमित कनौजिया, सुरेंद्र जाटव, दीपक मिश्रा, योगेश शर्मा, अयूब शेख, लोचन जाटव समेत बढ़ी संख्या में युवा मौजूद थे।

शिक्षकों ने डीयू कुलपति के अक्षयनिधि के लिए जारी पत्र को खारिज किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्योगी की ओर से पूर्व छात्रों को अक्षयनिधि के लिए 1000 करोड़ रुपए दान देने के लिए पत्र लिखा है। एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट (एएडी) ने इसे पूरी तरह से खारिज किया है।

> एएडी के राजेश झा ने कहा कि ना तो आइओई, ना ही ईसी द्वारा अक्षयनिधि को स्वीकृत किया गया है

एएडी के राजेश झा ने कहा कि यह निर्णय कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय के नियम कानून को अनदेखी कर तानाशाही रूप से काम करने का एक और उदाहरण है। ना तो उत्कृष्ट संस्थान (आइओई) ना ही अक्षयनिधि को कार्यकारी परिषद (ईसी) के द्वारा स्वीकृत किया गया है। अक्षयनिधि वित्तीय लेन-देन से संबद्ध है, इसलिए वित्तीय समिति से इसी स्वीकृत लेनी चाहिए थी। कुलपति हड़ताल कर रहे शिक्षकों की न्यायपूर्ण मांगों को सुनने की बजाय ऐसे पत्रों को भेज रहे है जो हमारे नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हम कुलपति से मांग करते है कि वह इस पत्र को वापस लें और उनसे अपील करते है कि विश्वविद्यालय को डीयू के नियम कानून के अनुसार चलाएं ना कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के फरमानों के हिसाब से चलाएं।

डीएम के अवकाश पत्र के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोनों नाबालिग छात्रों को मिली जमानत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 25 दिसंबर।

12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के चलते दो जनवरी तक मिली जमानत, तीन जनवरी को होना होगा पेश

डीएम बी. एन. सिंह के अवकाश पत्र के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों छात्रों को जमानत मिल गई है। आरोप है कि दोनों नाबालिग छात्रों ने डीएम के छुट्टी संबंधी आदेश पक्ष से छेड़छाड़ कर दोबारा ट्वीट कर दिया था। यह ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके वायरल होते ही स्कूलों की छुट्टी को लेकर असमंजस की स्थिति हो गई थी। न्यायालय ने दो जनवरी तक जमानत दी है, तीन जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक नाबालिग दोषी साबित होने पर अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। आइपीसी 419 धोखाधड़ी के लिए अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है। 420 के तहत सात साल की सजा हो सकता है। आइटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा का प्रावधान है।

फर्जी संदेश के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जिलाधिकारी को एक बयान जारी करना पड़ा था। मामले को लेकर थाना सेक्टर-20 पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में फर्जी संदेश तैयार कर वायरल करने वाले दो आरोपी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों नाबालिग छात्र सेक्टर-12 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। जिन्होंने मस्ती के लिए यह किया था। दोनों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए मंगलवार को बड़ी संख्या में स्कूल में पढ़ने वाले उनके साथी डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे और माफी करने की मांग की। नाबालिग छात्रों पर जांच अधिकारी ने चार धाराओं में से तीन (420, 419, 500) को छोड़ केवल आइटी की धारा 66 के तहत केस डायरी कोर्ट में पेश की। फेज टू स्थित नोएडा बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक ने किशोर न्यायालय बोर्ड को पत्र लिखकर गुरुवार से शुरू होने वाली प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठने देने की अनुमति मांगी थी। नाबालिगों के भविष्य को देखते हुए किशोर न्यायालय बोर्ड ने 2 जनवरी तक अंतरिम जमानत मंजूर की। 3 जनवरी को दोबारा न्यायालय में पेश होना होगा। मंगलवार को थाना सेक्टर- 20 के एसएचओ राजबीर सिंह चौहान ने बताया था कि दोनों छात्रों के खिलाफ धारा 419,420 और 566 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

जेएलएन स्टेडियम में शुरू हुआ पांच दिवसीय गली पकवान मेला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

मेले का आयोजन नासवी की ओर से एफएसएसआइ के सहयोग से किया जा रहा है

मेला 29 दिसंबर तक हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक लगेगा

दिल्ली के सर्द मौसम में अगर आप को सरसों का साग व मक्के की रोटी, कुल्हड़ जलेबी, हैदराबादी दम बिरयानी, महुआ फूल की खीर या असम की नारियल के दूध की चाय पीनी हो तो आपको जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम का रुख करना होगा। यहां पांच दिनों तक चलने वाले 11वें नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल की बुधवार को शुरुआत हुई। इस मेले का आयोजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) की ओर से एफएसएसआइ के सहयोग से किया जाता है।

देश के तमाम देसी पारंपरिक स्वाद को संजोए यह मेला 29 दिसंबर तक हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगा। इस बार यहां पर 130 स्टॉल लगाए गए हैं जिन पर 500 से अधिक कारीगर अपनी कला का नमुना पेश करेंगे। मेले का चारों दिशाओं की थीम पर बांटा गया है। इससे खाने के शौकीनों को अपने मनपसंद व्यंजन को ढूंढ़ने में दिक्कत नहीं होगी।

आमतौर पर सड़क किनारे मिलने वाले व्यंजनों को स्वास्थ्य के लिए सही नहीं माना जाता है लेकिन यहां पर लगने वाले हर स्टॉल पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए सभी कारीगरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है।

आज के कार्यक्रम

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : दो होमलैंड नामक प्रदर्शनी, सेंटर आर्ट गैलरी, कमलादेवी कांपलेक्स, 40 मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे।

www.readwhere.com

कमलनाथ के नेतृत्व में निकला सीएए के विरोध में पैदल मार्च

कहा : एनपीआर हम भी लाना चाहते हैं लेकिन नागरिकता पंजी को जोड़कर नहीं

भोपाल, 25 दिसंबर (भाषा)।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को फिर दोहराया कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के साथ क्रियान्यवन पर भी सवाल उठाया।

कमलनाथ ने कहा कि एनपीआर को हम भी लाना चाहते हैं लेकिन इसके साथ नागरिकता पंजी (एनआरसी) को जोड़कर नहीं।

सीएए के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के पैदल मार्च के समापन के बाद एनपीआर की घोषणा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, ''वो जो एनपीआर लाए, ये तो हम भी चाहते थे, पर उसके साथ कोई एनआरसी नहीं जोड़ा था जो ये जोड़कर ला रहे हैं। ये इनकी नीयत साबित करती है।' केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संसद में पहले ही बता चुके हैं कि पूरे देश में एनआरसी को लागू करेंगे।

उन्होंने कहा कि संसद में अपने 40 वर्षों के दौरान मैंने कभी सीएए और एनआरसी जैसे संविधान विरोधी कानून नहीं देखे। सवाल यह नहीं है कि क्या लिखा गया है (इन कानून में) बल्कि क्या नहीं लिखा गया है। सवाल इसके उपयोग का नहीं दुरुपयोग का है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र की समस्याएं, निवेश लाने की चुनौतियां, बेरोजगारी तथा आर्थिक मंदी सहित अनेक मुद्दे हैं लेकिन केंद्र इन गंभीर समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है।

कमलनाथ ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार प्रदेश में सीएए लागू नहीं करेगी। उन्होंने कहा, 'जो जनविरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी कानून हैं, वे मध्यप्रदेश में कभी लागू नहीं होंगे, जब तक कांग्रेस की सरकार है।'

पैदल मार्च शुरू होने के पहले रंगमहल चौराहे पर उपस्थित जनसमूह के सामने कमलनाथ ने देश के बुनियादी ढांचे के विरोधी सीएए कानून के खिलाफ अंत तक लड़ने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसके संविधान से है, जो विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ता है और देश की एकता सुनिश्चित करता है।

बोधगया के महाबोधि मंदिर में बुधवार को तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा।

देश के 130 करोड़ लोग हिंदू समाज के रूप में : भागवत

हैदराबाद, 25 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि संघ भारत की 130 करोड़ आबादी को हिंदू समाज के रूप में मानता है, चाहे उनका धर्म और संस्कृति कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति पर ध्यान दिए बिना, जो लोग राष्ट्रवादी भावना रखते हैं और भारत की संस्कृति और उसकी विरासत का सम्मान करते हैं, वे हिंदू हैं और आरएसएस देश के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाज हमारा है और संघ का उद्देश्य संगठित समाज का निर्माण करना है।

भागवत ने कहा, 'भारत माता का सपूत, चाहे वह कोई भी भाषा बोले, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, किसी स्वरूप में पूजा करता हो या किसी भी तरह की पूजा में विश्वास नहीं करता हो, एक हिंदू है। इस संबंध में, संघ के लिए भारत के सभी 130 करोड़ लोग हिंदू समाज है।' उन्होंने कहा कि आरएसएस सभी को स्वीकार करता है, उनके बारे में अच्छा सोचता है और उन्हें बेहतरी के लिए उच्च स्तर पर ले जाना चाहता है। भागवत तेलंगाना से आरएसएस सदस्यों के तीन दिवसीय 'विजय संकल्प शिविर' के तहत यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

सीएए का प्रभाव : असम में फीका रहा क्रिसमस का उत्सव

पादरियों ने कहा : माहौल के कारण पर्व का उत्साह नही

गुवाहाटी, 25 दिसंबर (भाषा)।

विवादास्पद संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में असम में प्रदर्शन को देखते हुए क्रिसमस पर रौनक नहीं है। निराशाजनक माहौल के बीच शांति और खुशी के लिए मंगलवार की रात राज्य भर में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। विभिन्न गिरजाघरों के पादरियों ने कहा कि राज्य की स्थिति और माहौल के कारण पर्व मनाने का उत्साह नहीं दिख रहा।

स्थानीय गिरजाघर के फादर थॉमस ने बताया कि प्रभु यीशु के पवित्र जन्म उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार हम महज क्रिसमस ट्री की सजावट के साथ पर्व मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरजाघर की सजावट के लिए रंग-बिरंगे प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई है। डिब्रूगढ़ में एक पादरी ने बताया कि राज्य के विभिन्न स्थानों के निवासियों ने मंगलवार को मध्य रात्रि में प्रार्थना के दौरान शांति की कामना की। क्रिसमस से जुड़े सामानों की बिक्री करने वाले एक दुकानदार मनोहर लाल ने कहा कि इस बार ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। सीएए प्रदर्शनों से पहले मैंने जो सामान मंगवाए थे वे वैसे ही पड़े हुए हैं और उनके खरीदार बहुत कम हैं।

जोरहाट में इस तरह के सजावट का सामान बेचने वाले हेमंत गोगोई ने कहा कि मुझे बुरा नहीं लग रहा कि मेरे सामान नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि सीएए के कारण राज्य में माहौल सही नहीं है और गुवाहाटी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पांच लोग मारे गए। हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने वाले राज्य के होटल इस बार कार्यक्रमों से दूर हैं। गुवाहाटी में एक बड़े होटल के प्रबंधक ने बताया कि राज्य की वर्तमान स्थिति होटलों में कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत नहीं देती।

बारपेटा में क्रिसमस के लिए सजावट के सामान बेचने वाले इनामुल अली ने कहा कि हम सीएए का विरोध करते हैं और अपने असमिया समुदाय, भाषा और संस्कृति के लिए अपनी आमदनी भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे हम बर्बाद हो जाएंगे। असम में हुए सबसे भीषण प्रदर्शनों के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई।

हम चीन की बंदूक की ताकत के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे : दलाई लामा

गया, 25 दिसंबर (भाषा)।

तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने चीन में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का बुधवार को आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चीन का कम्युनिस्ट शासन बंदूक की ताकत पर चल रहा है, जिसका तिब्बत के बौद्ध सच्चाई की शक्ति के साथ पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

दलाई लामा ने यहां बोध गया में महाबोधि मंदिर में यह बयान दिया। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर बुद्ध ने दो सहस्त्राब्दि पहले ज्ञान प्राप्त किया था। वह अपनी एक पखवाड़े तक चलने वाली वार्षिक यात्रा पर मंगलवार की रात बोध गया पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि तीन साल पहले हुए सर्वेक्षण में पता चला कि चीन में तिब्बती बौद्धों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। हमारे पास सच की ताकत है, जबकि चीन में कम्युनिस्ट शासन के पास बंदूक की ताकत है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा ने नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए 'प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली' और 'अहिंसा, करुणा व लोकतंत्र' के उसके गुण की तारीफ की।

दलाई लामा ने कहा कि सामाजिक प्राणी होने के नाते, हम करुणा के बिना नहीं रह सकते। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य गुण है। दुनिया अक्सर धर्म के नाम पर हिंसा की चपेट में रहती है। यह नहीं होना चाहिए और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में दलाई लामा ने कहा कि चीन पारंपरिक रूप से बौद्ध देश रहा है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की तरह बौद्धों की संख्या भी बड़ी है। उन्होंने कहा कि चीन में कई नागरिक तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं और उसके विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में बौद्ध शोधार्थी हैं।

दलाई लामा ने चीन की जनमुक्ति सेना के दमन के मद्देनजर अपना देश छोड़कर भागने के बाद 1959 में भारत में शरण ली थी। शहर में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वे यहां 14 दिन तक रुकेंगे। पिछले साल जनवरी में उनके दौरे के समय कम तीव्रता का बम धमाका हुआ था, जो उस स्थान के बेहद करीब हुआ था जहां कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रवचन दिए थे।

येदियुरप्पा की कार रोकने के प्रयास के लिए पांच गिरफ्तार

कन्नूर (केरल), 25 दिसंबर (भाषा)।

केरल में कन्नूर के पास स्थित पझायनगड़ी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को काले झंडे दिखाने और उनकी कार रोकने का प्रयास करने की घटना के सिलसिले में राज्य में सत्तारूढ़ माकपा और विपक्षी कांग्रेस के पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को कहा कि इनमें से तीन माकपा की छात्र इकाई स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) के जबकि दो युवा कांग्रेस से जुड़े हैं।

उन्होंने बताया कि पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

महिलाओं के गर्भाशय निकलवाने पर मुख्यमंत्री को पत्र

मुंबई, 25 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह मजदूरी बचाने के लिए गन्ना श्रमिक महिलाओं द्वारा गर्भाशय निकलवाने की घटनाओं के मामले में हस्तक्षेप करें। उन्होंने इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया। राउत का कहना है कि मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में गन्ना श्रमिक हैं जिनमें खासी संख्या महिलाओं की है।

मुख्यमंत्री को मंगलवार को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि माहवारी के दिनों में बड़ी संख्या में महिला मजदूर काम नहीं करती हैं। काम से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है। ऐसे में पैसों की हानि से बचने के लिए महिलाएं गर्भाशय ही निकलवा दे रही हैं, ताकि माहवारी न हो और उन्हें काम से छुट्टी न करनी पड़े। राउत का कहना है कि ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 30,000 है। गन्ने का सीजन छह महीने का होता है। इन महीनों में अगर गन्ना पेराई फैक्टरियां प्रति महीने चार दिन की मजदूरी देने को राजी हो जाएं तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। राउत ने पत्र में ठाकरे से अनुरोध किया कि वह मानवीय आधार पर मराठवाड़ा क्षेत्र की इन गन्ना महिला मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग को आदेश दें। राउत के पास पीडब्ल्यूडी, आदिवासी मामले, महिला व बाल विकास, कपड़ा, राहत व पुनर्वास मंत्रालय विभाग हैं।

मस्तिष्क ज्वर, बाढ़ और लालू परिवार में विवाद सुर्खियां बने

पटना, 25 दिसंबर (भाषा)।

लोकसभा चुनावों में विपक्ष की हार से बिहार में सत्तारूढ़ जद (एकी)-भाजपा गठबंधन जहां 2019 के पूर्वार्द्ध में मजबूत दिखा वहीं इसके बाद के महीने में इसे खासी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि व्यापक पैमाने पर फैले मस्तिष्क ज्वर में 200 बच्चों की मौत हो गई और अचानक आई बाढ़ के कारण राज्य की राजधानी टापू में बदल गई। विभिन्न कारकों से लोकसभा चुनावों में राजग को 40 में से 39 सीटें हासिल हुईं वहीं लालू प्रसाद के राजद को एक भी सीट नसीब नहीं हुई।

गैर राजग दल जिसने एक सीट हासिल की, वह है राजद की सहयोगी कांग्रेस लेकिन राज्य में अब यह पुरानी पार्टी भी मजबूत नहीं रह गई है। राजग को आश्चर्यजनक जीत हासिल हुई। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा नीत गठबंधन के बाहर के दल केवल 18 क्षेत्रों में बढ़त हासिल कर सके। विपक्ष की कमजोरी के अलावा राजग को अपने नेताओं के करिश्मे, वोटों के अंतरण और बालाकोट हवाई हमले के बाद देशभक्ति की भावना का फायदा मिला। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हवाई हमला कर आतंकवादियों के शिविर को तबाह किया था।

बिहार - 2019

बहरहाल, वर्ष के अंत में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर राज्य में आंदोलन हुए। इससे गठबंधन में तनाव दिखा। जद (एकी) ने संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक (सीएबी) के पक्ष में वोट दिया था लेकिन जद (एकी) प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनआरसी की कवायद का पूरे जोर-शोर से विरोध किया। इसी वर्ष उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को 11 न्यायाधीशों की एक पीठ ने खत्म कर दिया जिन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर आपत्ति जताई थी।

इस मामले में तभी सुलह हुआ जब न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एपी. शाही के साथ भारत के प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात की जिन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र वापस कर दिए। इस वर्ष की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में सेक्स स्कैंडल के मामले में धीमी प्रगति पर नाखुशी जाहिर करते हुए मामले को नई दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। अब साकेत की पॉक्सो अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है और जल्द ही फैसला आ सकता है।

लोकसभा चुनावों में हार का स्वाद चखने वाले विपक्ष ने हाल में संपन्न विधानसभा उपचुनावों में वापसी की। महागठबंधन में निराशा का माहौल तब दिखा जब मस्तिष्क ज्वर और बाढ़ जैसे मुद्दों पर वह सरकार को नहीं घेर सका। बाढ़ के कारण 13 जिलों में करीब 130 लोगों की मौत हो गई और करीब 90 लाख लोग विस्थापित हो गए, वहीं अक्तूबर में मूसलाधार बारिश से पटना और आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए। कई दिनों तक घरों में फंसे हजारों लोगों को बाहरन निकालना पड़ा। बिहार में 2020 में राजग के सत्ता में लौटने पर नई सरकार का मुखिया कौन बनेगा, इसको लेकर काफी समय तक माथापच्ची चलती रही और जब अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के नेता होंगे तब जाकर यह मुद्दा शांत हुआ। पूरे वर्ष कुमार के राजनीतिक कदम खबरों में बने रहे क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व से इनकार कर दिया था। उनकी पार्टी ने तीन तलाक विधेयक और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा को समाप्त करने वाले विधेयक पर संसद से बहिर्गमन किया।

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

PRINCE®
PIPING SYSTEMS

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

Our Company was incorporated as 'Prince Pipes and Fittings Private Limited' on November 13, 1987 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956. Thereafter, pursuant to Section 43A(1A) of the Companies Act, 1956, our Company became a deemed public limited company with effect from July 1, 1998. Further, pursuant to Section 43A(2A) of the Companies Act, 1956, our Company converted back into a private company on May 18, 2001. Subsequently, upon conversion into a public limited company pursuant to a special resolution of our Shareholders dated August 7, 2017, the name of our Company was changed to 'Prince Pipes and Fittings Limited', and a fresh certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu ("RoC") on August 11, 2017. For further details in relation to changes in the name and registered office of our Company, see the section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 176 of the prospectus dated December 23, 2019 ("Prospectus").

Registered Office: Plot No.1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Sattari, Honda, Goa 403 530, India;
Corporate Office: 8th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400 028, Maharashtra, India.
Contact Person: Pravin Jogani, Company Secretary and Compliance Officer; Telephone: +91 22 66022222; Facsimile: +91 22 66022220; E-mail: investor@princepipes.com; Website: www.princepipes.com
Corporate Identity Number: U26932GA1987PLC006287

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JAYANT SHAMJI CHHEDA, TARLA JAYANT CHHEDA, PARAG JAYANT CHHEDA, VIPUL JAYANT CHHEDA AND HEENA PARAG CHHEDA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 28,089,885 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 178 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 168 PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 5,000 MILLION* (THE "OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF 14,044,943 EQUITY SHARES BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION* (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 14,044,942 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION, INCLUDING 1,123,595 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 200 MILLION BY JAYANT SHAMJI CHHEDA, 7,865,168 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,400 MILLION BY TARLA JAYANT CHHEDA, 2,808,988 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 500 MILLION BY PARAG JAYANT CHHEDA AND 2,247,191 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 400 MILLION BY VIPUL JAYANT CHHEDA (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH OFFERS THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER CONSTITUTES 25.53% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.^
^SUBJECT TO FINALISATION OF THE BASIS OF ALLOTMENT.
*OUR COMPANY HAS, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), UNDERTAKEN A PRIVATE PLACEMENT OF 596,500 COMPULSORILY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES, WHICH HAVE BEEN CONVERTED INTO 5,965,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING TO ₹ 1,061.77 MILLION ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE SIZE OF THE FRESH ISSUE OF UP TO ₹ 3,561.77 MILLION WAS REDUCED BY ₹ 1,061.77 MILLION PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT AND ACCORDINGLY THE FRESH ISSUE WAS UP TO ₹ 2,500.00 MILLION.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH.
THE OFFER PRICE IS ₹ 178 PER EQUITY SHARE.
THE OFFER PRICE IS 17.80 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

BID/OFFER PROGRAMME
BID/OFFER OPENED ON WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019
BID/OFFER CLOSED ON FRIDAY, DECEMBER 20, 2019

NOTICE TO INVESTORS

With reference to the Prospectus filed with the RoC, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE", and together with BSE, the "Stock Exchanges"), investors should note the following:
This is with reference to the disclosure under "Outstanding Litigation and Material Developments - Complaints received from Montana and Radon" on page 349 of the Prospectus regarding an email dated December 21, 2019 ("E-mail") sent by RGM Legal, on behalf of their client (Montana Developers Private Limited ("Montana"/"Complainant") to SEBI, forwarding the complaint from Montana dated December 17, 2019 ("Complaint") to SEBI and copying the Stock Exchanges and our Company repeating and re-iterating the contents of the Complaint and all previous letters, complaints and correspondence sent by the Complainant and requesting appropriate action.
Please note that, on December 24, 2019, our Company received a notice ("RGM Notice") from RGM Legal informing us that Montana filed a writ petition ("Writ Petition") before the High Court of Judicature at Bombay ("Bombay High Court"), against SEBI, the Stock Exchanges, our Company and the Union of India through the MCA. The Writ Petition, among other things, reiterated the allegations made in, inter alia, the various complaints that are indicated in the Prospectus. Montana prayed for, inter alia, an appropriate writ to be issued directing SEBI to (i) take immediate cognizance of the representations made by Montana in the Complaint; (ii) take necessary action as required against our Company (iii) act in a time bound manner; (iv) put on hold any further permissions and any further steps to be taken regarding the Offer; (v) place necessary conditions/restrictions preventing access to public funds collected through the Offer by our Company; and (vi) to take such actions under law to secure public funds collected through the Offer pending the hearing and final disposal of the Writ Petition. Montana also prayed that the Bombay High Court provide interim and ad-interim reliefs to its specific prayers. As per the RGM Notice, the Writ Petition is scheduled for an urgent admission before the Bombay High Court on December 26, 2019. Accordingly, the Company will contest the allegations against it and take recourse to all legal means available to it.
This notice is being issued under Regulation 60(4) of the SEBI ICDR Regulations 2009.
All capitalized terms used in this notice shall, unless the context otherwise requires, have the same meanings as ascribed to such terms in the Prospectus.

For PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: December 25, 2019

Prince Pipes and Fittings Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its equity shares ("Equity Shares") and has filed the red herring prospectus dated December 11, 2019 ("RHP") and prospectus dated December 23, 2019 ("Prospectus") with the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu. The RHP is to be read with addendum-cum-corrigendum dated December 17, 2019 and addendum dated December 18, 2019. The RHP is available on the websites of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com as well as on the websites of the book running lead managers, i.e. JM Financial Limited at www.jmfl.com and Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfin.com. The Prospectus is available or will be made available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the book running lead managers, i.e. JM Financial Limited at www.jmfl.com and Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfin.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "Risk Factors" on page 17 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the draft red herring prospectus filed with SEBI for any investment decision.
The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or the laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States pursuant to Regulation S under the U.S. Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.
CONCEPT

नई दिल्ली

जनसत्ता

लोकतंत्र का रास्ता

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रही प्रत्यक्ष-परोक्ष तनातनी में कुछ सुधार होने के बजाय स्थिति और बिगड़ती जा रही है, तो इससे यही जाहिर होता है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद में कोई बड़ी कमी है। लेकिन मंगलवार को जैसी स्थिति पैदा हुई, वह न तो लोकतंत्र के लिए उचित है, न राजनीतिक उथल-पुथल से उपजी समस्या को दूर करने में उससे कोई मदद मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य के राज्यपाल और कुलाधिपति जगदीश धनखड़ जादवपुर विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेने गए थे, लेकिन वहां भारी संख्या में जमा प्रदर्शनकारियों ने उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया और आखिरकार उन्हें वापस लौटना पड़ा। दरअसल, वहां जमा बड़ी तादाद में विद्यार्थी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। विद्यार्थियों के मुताबिक उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि वे दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के हाथों से डिग्री नहीं लेंगे। हो सकता है कि संबंधित विद्यार्थी किसी खास मुद्दे पर विरोध स्वरूप राज्यपाल के हाथों डिग्री नहीं लेने की राय रखते हों और यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन एक निर्धारित कार्यक्रम में राज्यपाल को भाग लेने से रोकने को कितना उचित माना जाएगा?

यह बेवजह नहीं है कि राज्यपाल ने इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए साफ शब्दों में कहा कि यह घटना विश्वविद्यालय में कानून के राज की गंभीरता से समझौता किए जाने का उदाहरण है। किसी मुद्दे पर विरोध जताना या प्रदर्शन करने के अधिकार के समांतर अगर कोई समूह कानून और शासन को ताक पर रख देता है तो निश्चित रूप से यह एक गंभीर स्थिति है। यह राज्य सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं पैदा होने दे। लेकिन अगर वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों के विरोध की वजह से राज्यपाल को लौटना पड़ा तो यह अपने आप में वहां की ड्यूटी के लिए जवाबदेह पुलिसकर्मियों की नाकामी है। आखिर पुलिस जादवपुर विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों के बीच से राज्यपाल को परिसर में सुरक्षित ले जाने में कैसे नाकाम रही? अगर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं थी, तो इसका कारण क्या था? इसके अलावा, खबरों के मुताबिक अगर कुलाधिपति या राज्यपाल ने कुलपति को नियम-पुस्तिका के अनुसार चलने और दीक्षांत समारोह के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे, तो उसका पालन करने को लेकर लापरवाही की वजह क्या हो सकती है? इस मामले में नियम-कायदे क्या कहते हैं?

विडंबना यह है कि राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच आपसी बयानबाजी से उपजी तनातनी का असर सामान्य गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। हाल में राज्य सरकार ने एक नए नियम के तहत कुलाधिपति और राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच प्रत्यक्ष संवाद का माध्यम उच्च शिक्षा विभाग के जरिए तय कर दिया। इसी तरह के मतभेद की पृष्ठभूमि में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल पर राज्य में समांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया था। लेकिन बात शायद तब ज्यादा बढ़ गई जब सीएए के खिलाफ रैली आयोजित करने और उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाग लेने पर राज्यपाल ने एक ट्वीट के जरिए आपत्ति जताई। जहां तक नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर विरोध जताने का सवाल है, तो देश के अलग-अलग हिस्से में इस मसले पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इस पर व्यापक बहस भी चल रही है। लेकिन शासन के सामान्य कामकाज को सहजता से चलने देने से किसे दिक्कत हो सकती है? आखिर इन कामों का अंतिम लाभ आम जनता को ही मिलता है।

पाक की मुश्किल

आतंकवाद रोकने और आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़े कदम उठाने को लेकर पाकिस्तान का संकट गहराता जा रहा है। अगर उसने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीए) की ओर से निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया तो अगले साल फरवरी तक उसे काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पहले से आर्थिक संकटों का सामना कर रहे मुल्क के सामने कंगाली जैसे हालात बन सकते हैं। दो दिन पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने जारी एक रिपोर्ट में इस बात की आशंका व्यक्त की है कि अगर एफएटीए पाकिस्तान को काली सूची में डाल देता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। आइएमएफ को इस बात का डर है कि उसने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जो कर्ज दे रखा है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका क्या होगा? एफएटीए की कार्रवाई पाकिस्तान को महंगी इसलिए पड़ेगी कि काली सूची में डाले जाने के बाद पाकिस्तान में बाहरी निवेश को जोरदार झटका लग सकता है। जाहिर है, किसी आतंकी देश में कोई अपनी पूंजी क्यों लगाएगा?

आतंकवाद को लेकर पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान पर शिकंजा तेजी से कसा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की पहले से ही यह संभव हुआ है। एफएटीए इन्हीं देशों की पहल पर बना संगठन है जो दुनिया के उन मुल्कों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाता है जो अपनी जमीन से आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं और आतंकवाद संगठनों को पालते-पोसते हैं। पाकिस्तान के बारे में तो सारी दुनिया एकमत है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है। यह बात खुद उसका सबसे पुराना हमदर्द और मददगार देश अमेरिका कहता आया है। भारत पिछले तीन दशक से पाकिस्तान के आंतक की मार झेल रहा है। एफएटीए पाकिस्तान से इसलामिक स्टेट, अलकायदा, जमात-उद-दावा, लश्करे तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को लेकर चेतावनी देता रहा है, लेकिन हकीकत में अब तक ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा है। इस साल अगस्त में भी एफएटीए के एशिया प्रशांत समूह ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी जारी की थी।

पाकिस्तान को 2012 से 2015 के दौरान भी एफएटीएफ की निगरानी सूची में रखा गया था। लेकिन उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे यह पता चलता कि वह आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। आतंकवाद का रास्ता देश को कंगाली के रास्ते पर ले जाना वाला है, यह पाकिस्तानी हुक्मरानों को सोचना चाहिए। विश्व बैंक भी पाकिस्तान को चेता चुका है। पाकिस्तानी रुपए में गिरावट का दौर जारी है। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा का भंडार पहले से ही पैंदे में जा चुका है। पाकिस्तानी मुद्रा के अवमूल्यन ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। तेल, गैस और सीएनजी की किल्लत से न सिर्फ लोग परेशान हैं, उद्योग-धंधे तक ठप पड़े गए हैं। सरकार गैस और तेल के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। दूसरी ओर देश में बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया गया और कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए तो उससे देश में हालात बनेंगे, वे आज के मुकाबले कहीं ज्यादा भयावह होंगे। पाकिस्तान के पास अब भी वक्त है कि वह एफएटीए के मुताबिक चले। फैसला उसे ही करना है कि आतंकवाद को चुने या अमन को।

कल्पमेधा

अपनी प्रसिद्धि और स्मृति के लिए
मैं दूसरों की दया और कृपा
पर निर्भर हूं।
- बेकन

बिजली घरों से फैलता अंधेरा

अखिलेश आर्येंदु

बिजली घरों से निकलने वाली काली राख से हजारों एकड़ भूमि बंजर होती जा रही है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है और आसपास की उपजाऊ जमीन भी इसके असर से बंजर होती जा रही है। इतना ही नहीं, आंधी और तूफान आने पर यह राख हवा में मिल कर सांस, त्वचा और आंख के रोग पैदा कर रही है।

देश में जितनी बिजली बनाई जाती है, उसमें से साठ फीसद जीवाश्म कोयले से बनती है। बाकी छब्बीस फीसद बिजली का उत्पादन पानी से और चौदह फीसद बिजली उत्पादन अन्य तरीकों से होता है, जिसमें यूरेनियम और थोरियम से बनने वाली बिजली महज दो फीसद है। जाहिर है, देश में कोयले से चलने वाले बिजली घर ही ज्यादा हैं और इनसे सबसे ज्यादा अपशिष्ट निकलते हैं, जिसमें काली राख की भरमार होती है। चिंता की बात यह है कि सरकार की नजर में इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए बिजली घरों के आसपास करोड़ों टन काली राख फैली रहती है और यह पर्यावरण को ही नहीं, भूमि और जल को भी प्रदूषित कर रही है।

कोयले से चलने वाले बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्टों को ठिकाने लगाने की न तो भारत सरकार के पास कोई योजना है, न राज्य सरकारों के पास। बिजली मंत्रालय का मानना है कि यह ऐसा व्यर्थ का पदार्थ है जिसका किसी भी रूप में कोई उपयोग नहीं हो सकता। ताज्जुब की बात यह है कि आज वैज्ञानिकों ने धरती पर हर चीज का उपयोग किसी न किसी रूप में करने का तरीका ईजाद कर लिया है, लेकिन बिजली बनाने के दौरान कोयले से निकलने वाले इस अपशिष्ट के कोई बेहतर उपयोग का विकल्प आज तक नहीं खोजा जा सका है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपयोग नहीं है। इसका उपयोग है, लेकिन सरकार इस तरफ गौर ही नहीं करती। इस वजह से इसके बेहतर उपयोग के बारे में कोई अनुसंधान भी नहीं हुआ है। दुनिया के विकसित कहे जाने वाले देशों ने कार्बन को दफनाने तक की समस्या का निदान खोज लिया है, जो कभी असंभव माना जाता था। ग्रीन हाउस की समस्या से निजात पाने की विधि खोज ली गई है, लेकिन भारत में करोड़ों टन कोयले के अपशिष्ट के इस्तेमाल का रास्ता आज तक नहीं निकल पाया है।

बिजली घरों से निकलने वाली काली राख से हजारों एकड़ भूमि बंजर होती जा रही है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है और आसपास की उपजाऊ जमीन भी इसके असर से बंजर होती जा रही है। इतना ही नहीं, आंधी और तूफान आने पर यह राख हवा में मिल कर सांस, त्वचा और आंख के रोग पैदा कर रही है। चिंता की बात यह है कि इससे सांस संबंधी अनेक रोग पैदा होते हैं और इसके संपर्क में लगातार काम करने वाले मजदूरों की असमय में मौत हो जाती है। तो क्या कोयले के इस अपशिष्ट से इसके आसपास रहने वाले लोगों को कई तरह की समस्याएं नहीं होती होंगी? जमीन और हवा के अलावा इस अपशिष्ट से बिजली घरों के आसपास जल स्रोत ही नहीं नहर, तालाब और कुए तक जहरीले होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोयले से निकलने वाला हर अपशिष्ट चाहे वह गैस हो या राख, इससे मानव शरीर, मस्तिष्क और मन पर प्रतिकूल असर डालते ही हैं। इसलिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोयले की राख से कोई समस्या इंसान को सीधे तौर पर नहीं हो सकती है।

दिल्ली और फरीदाबाद में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हवा में घुले जहर के कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। देश-विदेश के बड़े-बड़े वैज्ञानिक 'प्रदूषण मुक्त दिल्ली' बनाने में जुटे हैं, लेकिन यह समस्या अभी काबू में नहीं आ पाई है। दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं बताया जाता है, लेकिन कोयले के निकलने वाले अपशिष्ट से दिल्ली की आबोहवा कितनी प्रदूषित है, इस पर वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् कुछ कहते नजर नहीं आते। पॉलिथिन, यमुना का गंदे नाले में तब्दील होने और रेत माफियों द्वारा अवैध तरीके से किए जा रहे खनन पर्यावरण की समस्या पैदा करते हैं और इनके खिलाफ आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली घरों से उत्सर्जित होने वाली राख को लेकर कोई चिंतित नजर नहीं आता।

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से उत्पन्न समस्याओं पर भारत से कहीं ज्यादा विदेशों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तिहत्तर फीसद योगदान ऊर्जा का होता

है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बिजली और ताप आधारित उपक्रमों की हिस्सेदारी 24.6 फीसद है और परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी महज दस फीसद है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत पांचवे स्थान पर है और इसके बढ़ने की रफ्तार काफी ज्यादा है। आने वाले पांच वर्षों में यह रफ्तार बढ़ कर पांच गुना तक पहुंच सकती है। जरूरत इस बात की है कि बिजली घरों के ईंधन कोयले और इसके अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण पर भी गहराई से ध्यान दिया जाए और इसके उपयोग के लिए कोई मुकम्मल रास्ता तलाशा जाए।

भारत में परमाणु रिएक्टरों से भी बिजली बनाई जा रही है, लेकिन अभी देश में इसका उत्पादन महज दो फीसद है। परमाणु रिएक्टरों से कुल बीस हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है, जबकि उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए बिजली की जरूरत इससे कई गुनी ज्यादा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा परमाणु बिजली घर लगाए जाने की जरूरत है। लेकिन परमाणु बिजली घरों को लेकर देश में एक मत नहीं है। ऐसे में सरकार को ले-देकर कोयले या पानी से बिजली पैदा करने का विकल्प झंझट रहित लगता है। पर समस्या यह है कि कोयला और पानी भी उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं जितनी कि जरूरत है।

सवाल है कि कोयले के इस अपशिष्ट का निदान क्या है? सरकार या एनजीओ की नजर में यह बड़ी समस्या भले न हो, लेकिन है यह एक बड़ी और गंभीर समस्या। आज भले ही इस पर गौर न किया जा रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार और पर्यावरणविदों को इस तरफ ध्यान देना ही होगा और इससे पैदा होने वाली समस्या के निजात के लिए कोई मुकम्मल समाधान खोजना ही होगा। देश भर में कोयले से चलने वाले जितने भी बिजली घर हैं, उनसे वर्ष भर में कम से कम सौ करोड़ टन कोयले का अपशिष्ट निकलता होगा। बिजली घरों के पास इसके निपटान के लिए न तो कोई सरकारी नियम और आदेश है, न बिजली घरों के पास कोई विकल्प। हालांकि सार्वजनिक रूप से मुफ्त में इसे उठा ले जाने का विज्ञापन भले ही वक्त-दर-वक्त निकलते रहते हैं। दूसरा सवाल इसके उपयोग से जुड़ा है। आमतौर पर कोयले के इस अपशिष्ट का उपयोग सीमेंट बनाने वाली कंपनिया करती हैं या कभी-कभार सड़क निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इससे समस्या पूरी तरह हल नहीं हो पाती। भारी मात्रा में राख पड़ी रह जाती है। सरकार भले ही इसे बेकार मान कर इस तरफ गौर न करे, लेकिन इसका उपयोग कोलतार की सड़क बनाने में बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दूरदराज के गांवों में जहां पहुंचने के कोई साधन नहीं है, या जहां की मिट्टी इस लायक नहीं है कि पैदल वहां पहुंचा जा सके, वहां इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गमलों में और गड्ढे पाटने में भी इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इससे जहां प्रदूषण की समस्या हल होगी, वहीं हजारों एकड़ भूमि जो इस अपशिष्ट के कारण किसी काम में नहीं आ रही है, काम में आने लगेगी।

विमर्श के ठिकाने

अतुल चतुर्वेदी

दुनिया मेरे आगे

चाय की थड़ियों को विमर्श का नया केंद्र या आधुनिक चौपाल कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। छोटी-बड़ी चाय की ये थड़ियां दरअसल मिलने-मिलाने, दो पल बतियाने का सस्ता ठिकाना है। इसे हम अपनी प्रेमिका से गुफ्तगू करने या अभिसार के नितांत निजी क्षणों के रूप में तो उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन संक्षिप्त मुलाकात करने, कुछ बातों के आदान-प्रदान के बहाने मिलने के प्राचीन पनघटों की तरह तो उपयोग कर ही सकते हैं। अधिकतर ऐसे शहरों में जहां कामगार आबादी ज्यादा है या जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का वातावरण है, वहां ये चाय की गुमटियां बहुतायत में पाई जाती हैं। इनके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।

थड़ी की कड़क अदरक वाली चाय का स्वाद ही अलहदा है। वह स्वाद नजाकत और तमाम तामझाम के साथ दूध, शक्कर, चायपत्ती डाल कर चाय बनाने वाले ब्रिटिश अंदाज में नहीं आ सकता। चाय बनाने की यह ठेठ खांटी शैली ही चाय को सर्वहारा तक जोड़ पाई है और उसका सफर ऊंचे होटलों, महलों से निकल कर आम जन तक पहुंचा है। चाय के ये ठिकाने दिन-रात फल-फूल रहे हैं। यहां पर तीखी राजनीतिक बहसें होती हैं, गंभीर साहित्यिक चर्चाएं होती हैं, दफ्तरों का 'एक दूसरे की शिकायत करें' कार्यक्रम आयोजित होता है और संबंध सुधार कार्यक्रम के तहत नई बिसात भी बिछाई जाती है। चाय की इन थड़ियों पर विद्यार्थी और सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारी से लेकर मजदूर और पार्टी कार्यकर्ता तक थकान मिटाने, ऊर्जा हासिल करने और भड़ास निकालने भी आते हैं।

किसी जमाने में बड़े और नामचीन शहरों में कॉफी हाउस होते थे। इलाहाबाद, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली की शामें इससे ही आबाद होती थीं। कलाकारों, पत्रकारों, साहित्यकारों के ये प्रिय ठिकाने थे, जहां खुल कर संवाद होता था, नई योजनाएं जन्म लेती थीं और तीक्ष्ण बहसें भी आकार लेती थीं। आज वे कॉफी हाउस लुप्तप्राय हैं। उनकी जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कॉफी रेस्तरां की श्रृंखलाएं डाल ली हैं, जहां निजता है, रम्य वातावरण है, लेकिन वैसा जनतंत्र और खुलापन नहीं है। असल में निजीकरण ने मनुष्य को एकाकी छोड़ दिया है, जहां उसे अवकाश तो है, लेकिन संवाद के रास्ते बंद हो गए हैं। वह अलग-थलग पड़ गया है। इन ठिकानों के बंद होने का अभिशाप हम भुगत रहे हैं। हमारी चेतना कुंद हो गई है, संवेदनाओं को काठ मार गया है। बस फेसबुक पर किसी के निधन के मौके पर 'आरआइपी' लिख कर कर्तव्यों की इतिश्री की जा रही है। जब बातचीत ही नहीं होगी, तर्क-वितर्क नहीं होंगे तो दूसरे के विचारों को सुनने-समझने और मनन करने की गुंजाइश ही कहां बचेगी? ऐसे में हम एक अंधानुकरणवादी पिछलग्गू समाज में बदलते जा रहे हैं जो अपने मत के आग्रह की पूंछ पकड़ कर पूरा जीवन पार कर लेता है। न वह अपने कुएं से बाहर झांकना चाहता है, न सोचना-समझना।

हम एक बंद समाज में बदलते जा रहे हैं, कई थोथी आधुनिकताओं के छद्म दावे के बावजूद। चाय की इन छोटी दुकानों ने गांव की चौपाल के ध्वंस रूप की जगह स्थान बना लिया है। शहर की हलचल, घटनाक्रमों की ताजा खबर यहां उपलब्ध है। प्रश्नोत्तरी या जरूरी टिप्पणियों को लोग साझा भी कर रहे हैं और अच्छे या खराब शिक्षक की समीक्षा भी हो रही है। हल्का-फुल्का मजाक और चुटकुले भी तैर रहे हैं और प्रेम प्रसंगों की कानाबाती भी। मेरा शहर कोचिंग के लिए विख्यात है और लाखों विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। ये चाय की थड़ियां एक तरह से उनके आश्रय स्थल हैं, थकान के बाद थोड़ा आराम करने के ठिकाने हैं। बल्कि नीरसता के सघन कार्यक्रम की ऊब से कुछ पल चुरा कर वे नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बाबू चाय वाला, मंगल चाय वाला... जैसे कई नाम हैं जो विद्यार्थियों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। ये कोई मशहूर ब्रांड के नाम नहीं हैं, लेकिन इनकी चाय की तासीर और जायका जुबान पर चढ़ चुका है। इसमें से एक चाय वाले ने तो अपने व्यापार को विस्तार देते हुए शहर के दो-तीन क्षेत्रों में अलग अलग शाखाएं भी शुरू कर दी हैं।

चाय की इन दुकानों पर बैठने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। कोई शिगूफेबाजी नहीं है, सर्विस टैक्स या जीएसटी का व्यर्थ संकट नहीं है। उधार, नकद, खाते- सब चलते हैं। अपने बेटे से मैंने एक दिन पूछा कि तुम थड़ियों पर चाय पीने क्यों जाते हो, जबकि घर में इतनी अच्छी चाय मिलती है। उसने जवाब दिया कि वहां चाय के साथ जो चर्चा का आनंद है, अखबारों का वाचन है, अलग-अलग लोगों की बातचीत सुन कर समृद्ध होने का सुख है, वह घर में कहां है! घर में तो औपचारिक वातावरण रहता है। मैं निरुत्तर था।

चाय की गुमटियों में धड़कते, नव आकार लेते भारत को पता नहीं हम शहरी चकाचौंध के चलते महसूस कर भी पा रहे हैं या नहीं, लेकिन विमर्श के ये नए मुकाम कम महत्त्वपूर्ण नहीं। किसी समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए तो बेशक शोधपूर्ण हैं।

नागरिकता पर खर्च

बीते कुछ दिनों से देश में जगह-जगह पर नागरिकता कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को गैर संवैधानिक बता कर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सरकार का तर्क यह है कि ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं, वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कानून संवैधानिक और सामाजिक तौर पर गलत है। गौरतलब है कि किसी कानून के तीन पहलू होते हैं। पहला कानूनी, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक पहलू। देश में जगह-जगह पर पहला और दूसरा पक्ष नजर आ रहा है, लेकिन तीसरा यानी आर्थिक पक्ष विरोध के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है।

हाल ही में असम में एनआरसी लागू किया गया था। लगभग तीन करोड़ की जनसंख्या में तकरीबन उन्नीस लाख लोग ऐसे पाए गए, जिनके पास भारतीय होने के कागजात नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें असम में इस पर कुल खर्च लगभग बारह सौ बीस करोड़ रुपए हुआ। मतलब एक व्यक्ति पर एनआरसी का औसतन सरकारी खर्च चार सौ रुपए है। भारत की जनसंख्या लगभग एक सौ पच्चीस करोड़ है। अगर इसे पूरे भारत मे लागू किया जाता है तो कुल खर्च लगभग लगभग पचास हजार करोड़ होगा जो सरकारी कोष पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। क्या इस आर्थिक संकट के दौर में यह लागू करना सही होगा? क्या यह सही होगा जब भारत में बेरोजगारी दर शीर्ष पर है? क्या भारत में रहने वाले लोगों पर संसाधनों में कमी की जाएगी?

जिनके पास नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त कागजात नहीं है, उन्हें रखने लिए कई डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें फिलहाल सिर्फ तीन हजार लोग रह सकते हैं। क्या उन्नीस लाख लोगों को रखने से आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा? किसी भी कानून का सिर्फ सामाजिक और कानूनी पक्ष के आधार पर समर्थन देना कहां तक सही है? किसी भी कानून का आर्थिक पक्ष सरकार को सामने रखना चाहिए, ताकि इससे सरकार पर बोझ न पड़े। यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत अभी एक गहन आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

● *विश्वजीत शुक्ला, सिंगरा खुर्द, झारखंड*

युवा का हाल

कई बार बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना है कि युवा इस देश के भविष्य हैं। विगत कुछ दिनों से देश के हालात को देख कर कहा जा सकता है कि देश का भविष्य खतरे में है। राजधानी दिल्ली जैसे शहरों में विद्यार्थी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आखिर इसका दोषी कौन है? सरकार या जनता? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण ही क्यों करती है, जिससे जनता हिंसा पर उतारू हो जाए?

दूसरी ओर, जनता भी नीतियों का विरोध हिंसात्मक तरीके से क्यों करती है? क्या यही एक रास्ता है? हिंसा से समाज का अपना ही घाटा है। दूसरी ओर, विद्यार्थियों पर हमले की खबर भी उभर कर आती है। आखिर क्यों एक विद्यार्थी सरकार और जनता के बीच की लड़ाई में पिसता नजर आ रहा है? आखिर उन मासूमों का क्या दोष जो भारत के उच्च केंद्रीय संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर रहें हैं। उन रोती-बिलखती मासूम आंखों से एक ही सवाल उभर कर आता है कि क्या हम सरकार पर से अपना भरोसा खत्म कर दें? इसी बीच कुछ पुलिस हमलों की खबर भी उभर आती है। आखिर ऐसे हालात में मनुष्य करे भी तो क्या करे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए।

सवाल यह नहीं है कि देश में ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति ही पैदा क्यों हो रही है। अब हम पुलिस से ऐसी अपेक्षा कैसे करें कि वह अपना व्यवहार बदल ले। आंदोलन को रोकने की कोशिश में वह आज लोगों को मार कर अधमरा कर दे रही है। क्या इस हिंसा का कोई विकल्प नहीं है? क्या उन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं? सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए कि अगर कोई उससे सवाल करे तो जवाब देने में उसे शर्मिंदगी महसूस न हो।

● *आयुष द्विवेदी, दिल्ली विवि*

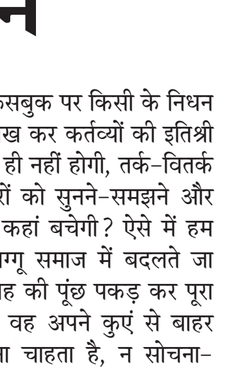

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कानून के हाथ

उन्नाव में बलात्कार के चर्चित मामले में आखिर न्याय ने अपना काम किया। लोगों का भरोसा बरकरार रहा। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी मानते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जीवन की अंतिम सांस तक वे जेल में रहेंगे। निस्संदेह अदालत के इस फैसले से न केवल आम जनमानस का न्याय पर भरोसा कायम रहा है, बल्कि यह भी दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। अपराध और अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून उससे बड़ा है। देश में आधी आबादी को लेकर इस वक्त जो सुरक्षा और संरक्षा के मसले पर जो भय और आक्रोश का माहौल बना है, उसमें यह फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा।

समाजशास्त्रीय अनुभव कहते हैं कि सेंगर ने सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व वाले पद पर रहते हुए जो आपराधिक हरकत की, वह किसी भी सूरत में माफी लायक नहीं है। सेंगर ने बतौर विधायक की भूमिका में होने के बावजूद नाबालिग पीड़िता का बलात्कार किया। आरोपों के पुष्ट होने के बावजूद वह विधायक कैसे बना रहा? क्या उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था? उसकी ऐसी हरकत से समाज को क्या संदेश मिला होगा? मेरी राय में बलात्कार और अपराधी की पहचान के बाद इस अपराध में फैसले की समय-सीमा अनिवार्य हो। केस से जुड़े पुलिस अफसर, वकील और जजों की जवाबदेही तय हो, क्योंकि कई बार देरी से हुआ न्याय इतना बेमानी साबित हो जाता है कि न्याय सुनने और उसे महसूस करने के लिए पीड़िता या उसका परिवार जिंदा भी नहीं रहता है।

● *हर्ष वर्द्धन, कदमकुआं, पटना*

शिक्षा के मूल्य

शिक्षा की बात जब हम करते हैं तो सर्वप्रथम यह सोचा जाए कि शिक्षा किसलिए दी जाए। अगर शिक्षा को व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो 'शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाती है।' शिक्षा का वास्तव में यही है। इसके साथ ही समाज को भी प्रगतिशील मूल्यों के साथ जोड़ना शिक्षा है। शिक्षा ये कभी नहीं कहती है कि अगर आप शिक्षित हो गए हैं तो दूसरों को नीचा दिखाएं। बल्कि शिक्षा जाति, धर्म, मजहब और पंथ के बीच विभिन्न प्रकार के भेदों से मुक्त करती है। इसलिए भारत के महान शिक्षा दार्शनिक अरविंदो ने शिक्षा के चार महत्त्व को बताया है, जिसमें चित्त, बुद्धि, मनस और ध्यान को बताया है। शिक्षा मनुष्य में विश्वास को जन्म देती है, न कि घमंड को। इसलिए शिक्षा के मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने के साथ ही आपके व्यवहार में भी परिलक्षित करने में सहायक होता है, जिससे एक प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है।

● *शैलेश मिश्र, बीएचयू, वाराणसी*

www.readwhere.com

खेल कार्यक्रम

आइस हॉकी	26 दिसंबर से
एटीपी कप (टेनिस)	3-12 जनवरी
डकार रैली	5-17 जनवरी
एएफसी अंडर-23 चैंपियनशिप	8-26 जनवरी

जन्मदिन

दीपक ठाकुर	28 दिसंबर
रानी रामपाल	29 दिसंबर
रजत चौहान	30 दिसंबर
राजीव तोमर	31 दिसंबर
पूजा ढांढा	1 जनवरी

पैसे तो खर्चे पर संतुलन नहीं बना पाए

संदीप भूषण

आइपीएल के 13वें सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी संपन्न हो गई है। यहां अधिकतम 73 खिलाड़ियों की बोली लगाई जा सकती थी और पांच घंटे चली नीलामी प्रक्रिया में 62 खिलाड़ी फ्रेंचाइजियों की पसंद बने। इनमें से 33 भारतीयों की किस्मत चमकी तो 29 विदेशी खिलाड़ियों को भी प्रमियर लीग का हिस्सा बनने का मौका मिला।

फ्रेंचाइजियों ने इन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च किए। इस सत्र की नीलामी में आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। एक तरफ जहां तेज गेंदबाज पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ में खरीदकर रेकार्ड बनाया वहीं हमवतन ग्लेन मैक्सवेल भी 10.75 करोड़ रुपए की बोली के साथ अपने पुराने फ्रेंचाइजी में लौटे। लीग के 11वें सत्र में दिल्ली के लिए धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी क्रिस मौरिस को भी 10 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने अपनी टीम में शामिल किया। इस लीग में एक बार फिर कुछ ऐसे भारतीय नाम शामिल हुए जिन्हें यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वहीं प्रवीन तांबे का बिकना भी किसी रेकार्ड से कम नहीं। आइपीएल के 13वें सत्र में नीलामी से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट

संतुलन नहीं बना पाई आरसीबी

कोलकाता में होने वाली आइपीएल की नीलामी को लेकर काफी समय से चर्चा थी। हर फ्रेंचाइजी अपने रिलीज किए गए खिलाड़ियों की जगह बेहतरीन क्रिकेटर शामिल करने की चाह में यहां शिरकत कर रहे थे। सबने जमकर बोली भी लगाई। हालांकि इसके बाद भी यह कहना कि सभी टीमों के पास संतुलित अंतिम एकादश है, बेईमानी होगी। सबसे पहले बात आरसीबी की होनी चाहिए। यह ऐसी टीम है जिसकी कमान खुद विराट कोहली संभाल रहे हैं। विराट दुनिया के उम्दा क्रिकेटरों में शुमार हैं लेकिन अपनी टीम को कभी खिताब नहीं दिला पाए। उनकी फ्रेंचाइजी ने इसी कमी को पूरा करने के लिए 10 करोड़ की बोली लगाकर हरफनमौला क्रिस मौरिस को खरीदा। इस अफ्रीकी खिलाड़ी पर पैसा लुटाने का क्या मतलब है यह तो लीग के शुरू होने के बाद ही समझ आएगा लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से वे फॉर्म से बाहर हैं। उन्होंने पिछले 10 टी-20 मुकाबलों में सिर्फ नौ विकेट लिए और 102 रन बनाए। बंगलुरु ने लगातार अनफिट रह रहे तेज गेंदबाज डेल स्टेन को भी दो करोड़ में खरीदा। स्टेन पिछले सीजन में सिर्फ दो मैच ही खेल सके थे। तब उन्होंने चार विकेट लिए थे। उससे पहले 2016 में एक मैच में कोई विकेट नहीं लिया। 2015 में छह मैच में तीन विकेट लिए थे।

हैदराबाद ने मजबूत की बल्लेबाजी

मजबूत गेंदबाजी इकाई के लिए मशहूर हैदराबाद ने इस नीलामी में अपने बल्लेबाजी क्रम को मजबूत बनाने की कोशिश की है। उसने मध्यक्रम को बेहतर करने के लिए प्रियम गर्ग और विराट सिंह के साथ शॉन मार्श को टीम में शामिल किया है। वहीं डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, जॉनी बेयरस्टो उसके शीर्ष क्रम को मजबूत और आक्रामक बनाते हैं। कोलकाता और पंजाब ने अपनी टीम में 9-9 खिलाड़ियों को शामिल किया है। किफायती खरीदारी के लिए जानी जाने वाली राजस्थान की टीम ने सबसे ज्यादा 11 खिलाड़ी खरीदे। उसने भी अपनी टीम में ज्यादातर हरफनमौलाओं को मौका दिया ताकि हर परिस्थिति में जीत उनकी झोली में आए।

महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई ने 5.50 करोड़ में इंग्लैंड के युवा हरफनमौला सैम कुरैन को खरीदा है। साथ ही उसने पीयूष चावला, आर साई किशोर और जोश हेजलवुड को टीम में शामिल किया। कुरैन को ड्वेन ब्रावो के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।

सबसे ज्यादा खिलाड़ी महाराष्ट्र से

नीलामी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनकी संख्या 24 थी जिसमें से छह इस आइपीएल में खेलेंगे। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है जहां से 19 खिलाड़ी इस नीलामी का हिस्सा थे। इसमें से तीन खिलाड़ी को फ्रेंचाइजियों ने चुना। दिल्ली के 14 खिलाडियों पर कोलकाता में बोली लगी लेकिन बिके सिर्फ दो। वहीं राजस्थान के 10 में तीन, तमिलनाडु के 10 में तीन, उत्तर प्रदेश के नौ में से तीन, झारखंड के सात में से दो, हरियाणा के छह में से एक, केरल के पांच में से एक, पंजाब के सात में दो, जम्मू कश्मीर के तीन में एक, नगालैंड के दो में एक, तेलंगाना के चार में एक खिलाड़ी को फ्रेंचाइजियों ने खरीदा। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक भी खिलाड़ी नहीं बिका।

आइपीएल

आइपीएल-2008
खिलाड़ी- एमएस धोनी
टीम- चेन्नई सुपर किंग्स
कीमत-1.5 मिलियन यूएसडी

आइपीएल 2012
खिलाड़ी- रवींद्र जडेजा
टीम- चेन्नई सुपर किंग्स
कीमत-2 मिलियन यूएसडी

आइपीएल-2011
खिलाड़ी- गौतम गंभीर
टीम- केकेआर
कीमत-2.4 मिलियन यूएसडी

आइपीएल 2014
खिलाड़ी- युवराज सिंह
टीम- आरसीबी
कीमत-14 करोड़

आइपीएल-2015
खिलाड़ी- युवराज सिंह
टीम- दिल्ली
कीमत- 16 करोड़

बंगलुरु ने लगातार अनफिट रह रहे तेज गेंदबाज डेल स्टेन को भी दो करोड़ में खरीदा। स्टेन पिछले सीजन में सिर्फ दो मैच ही खेल सके थे। तब उन्होंने चार विकेट लिए थे। उससे पहले 2016 में एक मैच में कोई विकेट नहीं लिया। 2015 में छह मैच में तीन विकेट लिए थे।

हैदराबाद ने मध्यक्रम को बेहतर करने के लिए प्रियम गर्ग और विराट सिंह के साथ शॉन मार्श को टीम में शामिल किया है। वहीं डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, जॉनी बेयरस्टो उसके शीर्ष क्रम को मजबूत और आक्रामक बनाते हैं। कोलकाता और पंजाब ने अपनी टीम में 9-9 खिलाड़ियों को शामिल किया है।

आश्चर्यजनक बोलियां

नीलामी में कई ऐसी बोलियां लगी जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसमें सबसे पहला नाम प्रवीन तांबे का है। उन्हें 48 साल की उम्र में कोलकाता ने खरीदा वहीं इस बोली प्रक्रिया में अफगानिस्तान के नूर अहमद भी शामिल हुए जिनकी उम्र लगभग 15 साल है। क्रिकेट के मैदान पर विकेट चटकाने के बाद सलामी दागने वाले कैरेबियाई खिलाड़ी शेल्डन कोटरेल को बेस प्राइस से 17 गुना अधिक कीमत मिली। उन्हें पंजाब ने 8.5 करोड़ में खरीदा। अंडर-19 टीम के कप्तान प्रियम को भी 1.9 करोड़ मिले। वहीं चौकाने वाला नाम रवि विश्नोई का भी रहा जिन्हें पंजाब ने दो करोड़ में खरीदा। 17 साल के यशस्वी जायसवाल पर भी 2.4 करोड़ की बोली लगी। वहीं हरफनमौला वरुण चक्रवर्ती को चार करोड़ मिले। विराट सिंह को 1.9 करोड़ रुपए मिले।

प्रवीन तांबे

पैट कमिंस

ग्लेन मैक्सवेल

क्रिस मौरिस

जनसत्ता के पाक्षिक खेल पेज के लिए लेख भेजें
Khel.jansatta@expressindia.com

शुरुआत

आइलीग मुकाबले से पहले शुभंकर से मिलते रीयल कश्मीर के मुख्य कोच डेविड रॉबर्टसन।

क्रिकेट में तकनीक के इस्तेमाल की हो समीक्षा

मनीष कुमार जोशी

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा का रन आउट होना विवादास्पद रहा। मैदानी अंपायर ने इसे नॉटआउट करार दिया तो वहीं रिप्ले के दौरान दिखाया गया कि वे आउट थे। यह भी बताया गया कि कैरेबियाई टीम के कप्तान को उनके वीडियो एनालिटिक का इशारा भी आया था जिसके बाद उन्होंने डीआरएस की मांग की। इसके बाद जडेजा को आउट करार दिया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर कोहली ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डीआरएस का निर्णय लेने में मैदान के बाहर से मदद लेना जायज नहीं है।

दरअसल, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार डीआरएस लेने से पहले मैदान के बाहर के व्यक्ति से मदद लेने को लेकर विवाद हो चुके हैं। जडेजा के मामले ने इस प्रक्रिया के इस्तेमाल करने को लेकर फिर ठंडे पड़े बहस को हवा दे दी है। जानकारों ने डीआरएस के इस्तेमाल के तरीके की समीक्षा की बात उठाई है। इस तकनीक के उपयोग के बने हुए नियम-कानून अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। जब कैमरा अंपायर ने देख लिया था कि जडेजा आउट हैं तो उन्हें मैदानी अंपायर को बताने का अधिकार था या नहीं, इसे लेकर डीआरएस नियमों में क्या उल्लेख है इसकी स्पष्टता भी नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर पूरी दुनिया खिलाड़ी को टीवी पर आउट होते देखती है और मैदानी अंपायर उसे नॉटआउट करार देता है तो मामले में कहीं न कहीं नियमों की अस्पष्टता जाहिर होती है। हम अभी भी तकनीक का किस सीमा तक उपयोग करना है यह तय नहीं कर पाए हैं।

यह मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी कई बार डीआरएस से संबंधित विवाद हो चुके हैं। विश्वकप के दौरान वेस्ट इंडीज के विरुद्ध ही रोहित शर्मा के आउट होने की अपील पर डीआरएस लिया गया। इसमें यह तय करना था कि गेंद रोहित के बैट से लगी है या पैड से। कैमरा अंपायर के पास स्पष्ट फुटेज नहीं थे जिससे यह तय हो सके कि गेंद कहां लगी है। इस हालत में हमेशा ही संदेह का लाभ बल्लेबाज को मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहित को आउट करार दिया गया। तब वे शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इस फैसले के बाद डीआरएस और कैमरा अंपायर की जमकर आलोचना हुई।

अब इस बात को समझना होगा कि हमने सटीक फैसले के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना तो शुरू कर दिया लेकिन यह कई बार विवाद का कारण बन रहा है। क्रिकेट ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर खेलों में तकनीक को जगह दी गई है। हालांकि क्रिकेट में तकनीक के इस्तेमाल के साथ उसके नियम भी बनाए गए लेकिन यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। इस कारण न केवल विवाद खड़े होते हैं, कई बार टीम को एक फैसले के कारण हार का सामना भी करना पड़ता है। अंत में इस जेंटलमैन खेल को शर्मशार होना पड़ता है। खेल में तकनीक का प्रयोग विवाद समाप्त करने के लिए शुरू हुआ लेकिन यह विवाद का कारण बनने लगा।

सवाल

जब तीसरे अंपायर की शुरुआत हुई थी तो तब के महान अंपायर डिकी बर्ड ने कहा था कि यह मैदानी अंपायरों के अधिकार खत्म करेगा। अब लगभग वैसा ही हो रहा है। मैदानी अंपायर के अधिकार लगभग खत्म हो गए हैं। मैदानी अंपायर अब तकनीक के भरोसे हो गए हैं।

सानिया की वापसी से दूर होगा सूनापन

राजेश राय

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की कोर्ट में वापसी से भारतीय टेनिस जगत में छाया सूनापन समाप्त होगा। सानिया दो साल से अधिक समय से खेल से दूर हैं और भारत में कोई ऐसी महिला खिलाड़ी नहीं है जो उनकी जगह ले सके। वे आखिरी बार 2017 के चाइना ओपन में खेली थी। उसके बाद से मातृत्व अवकाश पर थीं। इस दौरान भारतीय टेनिस जगत को उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सानिया ही एकमात्र ऐसी भारतीय खिलाड़ी थीं जिनके दम पर देश को महिला टेनिस में पहचान मिलती थी।

33 साल की सानिया बेटे की मां बनी हैं और टेनिस कोर्ट में वापसी के लिए वे अमेरिका की लीजेंड टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका और अपने ही देश की महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम से प्रेरणा ले सकती हैं। सेरेना और मैरी कॉम दोनों ने मां बनने के बाद खेल में सफल वापसी की और खिताब जीते। सानिया की भी इच्छा है कि वे तोक्यो ओलंपिक में खेलें लेकिन इसके लिए उन्हें कोर्ट पर अपनी वापसी को सार्थक साबित करना होगा। सेरेना और मैरी कॉम की तरह सानिया भी ऐसा कर सकती हैं और खिताबी सफलताएं हासिल कर सकती हैं।

मौजूदा समय में टेनिस में 33 साल की उम्र संन्यास की उम्र नहीं मानी जाती है। सेरेना और उनकी बड़ी बहन वीनस 37 साल से अधिक उम्र की होने के बावजूद खेल रही हैं। सानिया को सिर्फ इतना ही देखना है कि उनकी फिटनेस का स्तर ऊंचा बना रहे क्योंकि टेनिस एक ऐसा खेल है जहां कोर्ट पर खिलाड़ी को लगातार भागना है और उसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती।

सानिया को अखिल भारतीय टेनिस संघ की चयन समिति ने फेड कप के एशिया ओसनिया जोन ग्रुप 'ए' के मुकाबले के लिए घोषित भारतीय टीम में शामिल किया है। फेड कप के लिए छह सदस्यीय भारतीय टीम में अंकिता रैना, रिया भाटिया, ऋतुजा भोसले, करमन कौर थांडी और सानिया मिर्जा को शामिल किया गया है जबकि सौजन्य बावीशेट्टी इस टीम की रिजर्व खिलाड़ी हैं। सानिया फेड कप टीम में चार साल बाद लौटी हैं और उनके पास यह दिखाने का शानदार मौका रहेगा कि वह इस उम्र में अन्य कई खिलाड़ियों से बेहतर हैं। सानिया आखिरी बार 2016 में फेड कप में खेली थीं।

अपने करिअर में 41 युगल खिताब जीत चुकी सानिया ने 2017 में जब टेनिस से ब्रेक लिया था तब उस सत्र में उन्होंने 488,568 डॉलर की कमाई की थी। उनके करिअर का सर्वश्रेष्ठ साल 2015 रहा जिसमें उन्होंने 10 खिताब जीते और 1,566,203 डॉलर की कमाई की थी।

कयास

कई शानदार खिलाड़ी हैं जो मां बनीं और इसके बाद उन्होंने वापसी की। मैं भी ऐसा कर सकती हूं। मां बनना गर्व की बात है लेकिन इस दौरान आपके शरीर को अपने बेबी के लिए काफी कुछ सहना पड़ता है। मैं मानती हूं कि ऐसे में वापसी करना आसान नहीं होता। मैं यह भी मानती हूं कि यह वापसी रोमांचक होगी। -सानिया मिर्जा।

www.readwhere.com

विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए एक महीने का प्रशिक्षण होगा अनिवार्य

सुशील राघव
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

- शिक्षकों के प्रशिक्षक के लिए यूजीसी शुरू करेगा 'गुरु दक्षता' कार्यक्रम
- नियुक्त होने के बाद छह महीने के अंदर पूरा करना होगा यह प्रशिक्षण
- इस कार्यक्रम को देश भर में यूजीसी के 66 एचआरडीसी आयोजित करेंगे

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए एक महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य होने जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसके लिए 'गुरु दक्षता' कार्यक्रम तैयार किया है जिसकी जल्द ही शुरुआत की जाएगी।

यूजीसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन ने बताया कि स्कूली शिक्षा में आने वाले शिक्षकों को तैयार करने के लिए हमारे देश में कई तरह के पाठ्यक्रम (बीएड आदि) मौजूद हैं। वहीं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षक नियुक्त होने के लिए नेट/सेट या पीएचडी पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान में इन शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। इस वजह से शिक्षकों को विद्यार्थियों से संचार करने, पाठ को ठीक ढंग से पढ़ाने, प्रश्नपत्र तैयार करने, मूल्यांकन करने आदि में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इन परेशानियों को दूर करने और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में इजाफे के लिए यूजीसी ने नए नियुक्त होने वाले सभी शिक्षकों को एक महीने का प्रशिक्षण करना अनिवार्य किया है। शिक्षक को नियुक्ति के छह महीने के अंदर यह प्रशिक्षण लेना होगा। इसके लिए 'गुरु दक्षता' कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम यूजीसी के मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी) के माध्यम से आयोजित होंगे। देश में 66 एचआरडीसी मौजूद हैं।

डॉक्टर पटवर्धन ने बताया कि इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है जिसके तहत प्रशिक्षकों को भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जल्द ही अगले चरण के तहत इन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण के दौरान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को शिक्षण के प्रति उत्साह, कक्षा में शिक्षक-विद्यार्थी संबंध, पाठ्यचर्या तैयार करने, पढ़ाई ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को शामिल करने, परीक्षा कार्यप्रणाली (प्रश्नपत्र तैयार करना, मूल्यांकन करना आदि), नवाचार एवं रचनात्मकता को सम्मान देना, प्रशासनिक एवं नेतृत्व, खुद को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को जल्द ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से देश भर के विश्वविद्यालयों और उनके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के लिए जारी किया जाएगा।

उत्तराखंड में रामकृष्ण मिशन के मठों में क्रिसमस मना

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 25 दिसंबर।

उत्तराखंड में रामकृष्ण मिशन के सभी मठों में क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। देहरादून के रामकृष्ण आश्रम, अल्मोड़ा के स्वामी विवेकानंद आश्रम, हरिद्वार कनखल के रामकृष्ण परमहंस के मंदिर में क्रिसमस ट्री को बिजली की लड़ियों और फूलों से सजाया गया। ईसा मसीह और मदर मेरी के फोटो को फूलों से सजाया गया और मोमबत्तियां जलाई गईं।

श्री रामकृष्ण मिशन मठ के सचिव स्वामी नित्य शुद्धानंद महाराज ने कहा कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध साधक थे और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म समभाव को मानने वाले थे। इसलिए उन्होंने मानवता की साक्षात मूर्ति ईसा मसीह के जन्मदिन को बड़े दिन के रूप में रामकृष्ण मिशन के मठों में मनाने की परंपरा शुरू की जो वर्षों से चली आ रही है। इस अवसर पर स्वामी मंजू महाराज, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. समीर चौधरी, स्वामी दयाधिपानंद महाराज, डॉ. शिवकुमार आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों को चॉकलेट और टोपियां बांटी गईं।

पूरे देश में क्रिसमस की धूम, बाजारों में रौनक

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

क्रिसमस की धूम पूरे देश में रही और इस अवसर पर घर, गिरजाघर और सार्वजनिक स्थान रौशन रहे और 'जिंगल बेल' हर जगह गुंजायमान रहा। बहरहाल असम में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में पर्व फीका रहा जहां प्रदर्शन के दौरान कम से कम पांच व्यक्तियों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सैकड़ों लोग गिरजाघरों, मॉल और शॉपिंग सेंटरों में क्रिसमस मनाने पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि ईसा मसीह की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, 'हम प्रभु यीशु के विचारों को पूरे उत्साह से याद करते हैं। उन्होंने सेवा और दया की भावना को मूर्त रूप दिया और अपना पूरा जीवन मानवता के दुख दर्द को खत्म करने में लगा दिया।'

भारी यातायात की संभावना के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने मंगलवार को परामर्श जारी कर लोगों से मशहूर गिरजाघर वाले रास्तों पर नहीं जाने की सलाह दी। असम के गिरजाघर के पादरी फादर थॉमस ने कहा, 'हमारे प्रभु यीशु का पवित्र जन्मदिवस मनाया जाना है। लेकिन इस बार हम हम महज क्रिसमस ट्री की सजावट के साथ यह उत्सव मना रहे हैं।' डिब्रूगढ़ में अन्य पादरी ने बताया कि राज्य के विभिन्न स्थानों के निवासियों ने मंगलवार की मध्य रात्रि प्रार्थना में हिस्सा लिया।

क्रिसमस से जुड़े सामानों की बिक्री करने वाले दुकानदार मनोहर लाल ने कहा, 'इस बार ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। सीएए प्रदर्शनों से पहले मैंने जो सामान मंगवाए थे, वे वैसे ही पड़े हुए हैं और उनके खरीदार बहुत कम हैं।' जोरहाट में इस तरह के सजावट का सामान बेचने वाले हेमंत गोगोई ने कहा, 'मुझे बुरा नहीं लग रहा कि मेरे सामान नहीं बिक रहे हैं क्योंकि सीएए के कारण राज्य में माहौल सही नहीं है और गुवाहाटी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पांच लोग मारे गए।'

यूपी के डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

पेज 1 का बाकी

के संबंध में अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिसे संज्ञान में लिया गया है। शिकायत 23 दिसंबर को दर्ज की गई और इसके बाद एनएचआरसी ने उप्र के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी कर चार हफ्तों में एक रिपोर्ट मांगी है।' शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में राज्य प्राधिकारों द्वारा मानवाधिकार हनन की कई घटनाएं हुई हैं। आयोग को सौंपी गई शिकायत के मुताबिक, 'युवक मारे जा रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं और पुलिस खुद सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार का भी हनन किया जा रहा।' शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि पिछले कुछ दिनों में समूचे उत्तर प्रदेश से कई मौतों, ज्यादातर युवकों की मौतें की कई खबरें आईं जो मुख्य रूप से पुलिस कार्रवाई के दौरान लगी गोलियों के चलते हुई।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों ने गोली नहीं चलाई, जबकि खबरों से प्रदर्शित हो रहा है कि पुलिसकर्मी लोगों पर गोली चला रहे हैं जो पुलिस के दावे के ठीक उलट है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारी कई लोगों की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं और उन्होंने मुसलिम लोगों की दुकानें सील कर मुसलिम आबादी को निशाना बनाया।

सोनिया और राहुल से मिले सोरेन, शपथग्रहण में आने के लिए न्योता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

- प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी देंगे निमंत्रण
- कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष पद सहित मिल सकते हैं चार मंत्री पद

झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें 29 दिसंबर को होने वाले शपथग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। समझा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया से मिलकर सोरेन ने सूबे के नए मंत्रिमंडल में कांग्रेस सहित अन्य सहयोगी दलों के बीच सत्ता के बंटवारे के फार्मूले पर भी उनकी सहमति हासिल कर ली है। कांग्रेस के खाते में विधानसभा अध्यक्ष पद सहित चार मंत्री पद आ सकते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष गांधी से मुलाकात के बाद सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि वे सोनिया गांधी व राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण देने आए थे। राहुल गांधी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है जबकि सोनिया गांधी ने भी आने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण देंगे। पंश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इन नेताओं को भी उन्होंने निमंत्रण भेजा है।

सोरेन ने कहा कि मंगलवार शाम को ही उन्होंने गठबंधन के अपने साथी दलों के साथ मिलकर सूबे की राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का अपना दवा पेश किया था और राज्यपाल ने भी उन्हें 29 दिसंबर को शपथ लेने को कहा है। सोरेन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सभी गठबंधन दलों के बीच बहुत ही आसानी से सत्ता में साझेदारी तय हो जाएगी और यह गठबंधन सरकार पूरे पांच साल चलेगी और राज्य के लोगों ने जिस बदलाव के लिए जनादेश दिया है उसे बदलाव के सपने को साकार करेगी।

इससे पहले सोरेन कांग्रेस के महासचिव आपीएन सिंह, अजय शर्मा व उमंग सिंघार के साथ निजी विमान से रांची से दिल्ली पहुंचे। सोरेने ने मंगलवार शाम ही फोन पर बात कर कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था। सूत्रों की मानें तो सत्ता के बंटवारे के लिए जो फार्मूला तय किया जा रहा है उसके तहत कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष पद और चार मंत्री पद मिल सकता है। पार्टी ने झारखंड में इस बार 16 सीटों पर विजय दर्ज की है। इनमें आठ विधायक पहली बार चुने गए हैं। जाहिर है कि इनमें से किसी को फिलहाल मंत्री नहीं बनाया जाएगा। जो पुराने आठ विधायक हैं उनको ही महत्त्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। इस क्रम में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव आदि प्रमुख नेताओं को मंत्री पद से नवाजे जाने के आसार हैं।

राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री मनोनीत किया

रांची, 25 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन के विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री मनोनीत कर राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रवक्ता अभिषेक प्रसाद ने इस आशय की जानकारी दी। सोरेन के 29 दिसंबर, रविवार दोपहर एक बजे यहां मोरहाबादी मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है।

इससे पूर्व मंगलवार को सोरेन ने रात्रि पौने नौ बजे झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह, राजद नेता तेजस्वी यादव और बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो के विधायकों समेत 50 विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण के लिए 29 दिसंबर को दोपहर एक बजे का समय दिया था।

सोरेन मंगलवार रात्रि में पूर्व निर्धारित आठ बजे की बजाय लगभग पौने नौ बजे राजभवन पहुंचे और उनके साथ वहां सरकार का समर्थन कर रहे लगभग सभी 50 विधायकों के साथ राजद के नेता लालू के पुत्र तेजस्वी यादव, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह और कांग्रेस हाईकमान द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। झामुमो के प्रवक्ता व महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हेमंत और उनके अन्य सहयोगियों का शपथग्रहण समारोह राष्ट्रीय स्तर का होगा और इसमें देश के विपक्षी दलों के तमाम शीर्ष नेताओं और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि सोरेन के शपथग्रहण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी में से से एक जरूर शामिल होगा। झारखंड विधानसभा चुनावों में 81 सीटों में से झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को 47 सीटें मिली हैं।

केंद्र ने सुशासन सूचकांक की शुरुआत की

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

देश में सुशासन की स्थिति के आकलन के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को सुशासन सूचकांक (जीजीआइ) की शुरुआत की।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस सूचकांक का मकसद सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में सुशासन की स्थिति की तुलना के लिए जरूरी आंकड़ा मुहैया कराकर परिणाम उन्मुखी दृष्टिकोण और प्रशासन की तरफ बढ़ना है। इसके साथ, शासन को बेहतर करने के लिए नीतियां तैयार करना और उपयुक्त रणनीति लागू करना है। बयान में कहा गया कि संकेतकों को चुनते समय विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है। जैसे कि यह समझने और आकलन में आसान होना चाहिए, नागरिक केंद्रित और नतीजे देने वाला हो, परिणाम बेहतर हो रहा हो और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू हो। इसके अलावा कई अन्य चीजें भी इसमें शामिल हैं। सुशासन सूचकांक राज्यों में सुशासन की स्थिति और राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समान साधन है। जीजीआई में 10 क्षेत्रों पर विचार किया जाएगा। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सुविधाएं, आर्थिक सुशासन, समाज कल्याण व विकास, न्यायिक व जन सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित प्रशासन शामिल हैं। सुशासन के इन 10 क्षेत्रों का आगे कुल 50 संकेतकों पर आकलन किया जाएगा। इन संकेतकों को मूल्य की गणना करने के लिए शासन क्षेत्र के तहत अलग-अलग भारांक दिए गए हैं। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन समूहों में बांटा गया है। बड़े राज्य, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश।

रोहतांग सुरंग का नामकरण 'अटल सुरंग'

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

सरकार ने बुधवार को रोहतांग दर्रे के नीचे बनी लेह और मनाली को जोड़ने वाली सामरिक सुरंग का नामकरण 'अटल सुरंग' करने की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर यह घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मनाली को लेह से जोड़ने वाली, रोहतांग सुरंग, अब अटल सुरंग के नाम से जानी जाएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने रोहतांग दर्रे के तहत सुरंग का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया है। यह पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने इस सामरिक सुरंग के निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय किया था । सिंह ने कहा कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) सुरंग का निर्माण कर रही है और निर्माण कार्य 2020 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरंग पूरी होने पर सभी मौसम में लाहौल और स्पीति घाटी के सुदूर के क्षेत्रों में संपर्क सुगम होगा और इससे मनाली एवं लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीतिक महत्व की सुरंग बनाए जाने का ऐतिहासिक फैसला तीन जून 2000 को लिया गया था जब वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे।

दिल्ली सहित उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में हाड़ कंपाने वाली ठंड

पेज 1 का बाकी

कई अन्य स्थानों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। पंजाब में फरीदकोट सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री से. दर्ज किया गया। दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री से. दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाया रहा। अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ समेत दोनों राज्यों के अधिकतर स्थानों में एक सप्ताह से दिन का तापमान भी सामान्य से छह से नौ डिग्री कम रह रहा है और यह 11 से 14 डिग्री से. के बीच दर्ज किया जा रहा है।

सीबीआइ ने यमुना एक्सप्रेसवे घोटाले की जांच शुरू की

पेज 1 का बाकी

तहत सबसे पहले किसानों से जमीन खरीदी और बाद में इसकी खरीद के चार से छह महीनों के भीतर इसे यीडा को बेच दिया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। यीडा ने अपनी आंतरिक जांच में सरकारी खजाने को 126 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन प्राथमिकी में 85.49 करोड़ रुपए के भुगतान का जिक्र किया गया है। गुप्ता 2013-15 के दौरान सीईओ थे। वह यीडा में अतिरिक्त सीईओ और डिप्टी सीईओ के पद पर भी रहे थे। भूमि 2013-2015 के दौरान उस समय खरीदी गई थी जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 24 जुलाई को इसकी जांच सीबीआइ से कराने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने 15 महीनों के बाद 24 अक्तूबर को इसकी जांच सीबीआइ को सौंप दी थी।

'अटल जल योजना' शुरू.

पेज 1 का बाकी

की जरूरत होती है और जहां ऐसी फसलें उगाई जाती हैं, वहां देखा गया है कि भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसानों को वर्षा जल संरक्षण और वैकल्पिक फसलों को अपनाने व सूक्ष्म सिंचाई की ओर बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए।

हटेंगी असम राइफल्स और सेना की टुकड़ियां

पेज 1 का बाकी

सुधार हुआ है और पिछले कुछ दिनों से इन राज्यों में हिंसा या सार्वजनिक प्रदर्शन की कोई घटना नहीं घटी है, इसलिए अतिरिक्त सैन्यकर्मियों की वहां तैनाती का अब कोई मतलब नहीं है।

एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने के बाद वहां भेजी गई अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों को वापस बुला लिया था। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय सुरक्षा समीक्षा के बाद कश्मीर से 7200 जवानों की तुरंत वापसी का आदेश दिया। अर्द्धसैनिक बलों के कुल 72 कंपनियों को देश भर में अपने स्थानों पर लौटने को कहा गया।

पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना के जेसीओ शहीद

पेज 1 का बाकी

निवासी महिला नसीमा (23) की बाद में मौत हो गई।भारतीय सेना ने इस संघर्षविराम उल्लंघन का माकूल जवाब दिया है। कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की तरफ काफी नुकसान हुआ है। प्रवक्ता के मुताबिक, विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। हाजीपीर के अलावा पाकिस्तानी सैनिकों ने बारामूला में कई सैन्य ठिकानों और रिहाइशी इलाकों को निशाना बनाते हुए छोटे हथियारों से हमला किया। कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों ने मंगलवार पूरी रात गोलाबारी की। इसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से चंदवा और हीरानगर सेक्टर में मंगलवार रात गोलियां दागी गईं और मोर्टार के गोले दागे गए।

इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से रातभर लगातार गोलाबारी होती रही। पाकिस्तान की ओर से की जा रही इस कायराना हरकत को देखते हुए हीरानगर में कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। उन लोगों ने आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को दोटूक जवाब देना चाहिए।इससे पहले मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों में अलग-अलग अभियानों में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी और जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस टीम इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है। इसी महीने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी बैट टीम के हमले की बड़ी साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो को मार गिराया था।

संपत्ति नुकसान पर रामपुर में 25 लाख की वसूली का नोटिस

पेज 1 का बाकी

हुआ है, लेकिन अंतिम आकलन में यह आंकड़ा 25 लाख रुपए पहुंच गया।

जिलाधिकारी आंजनेय सिंह ने कहा कि 28 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी पहचान विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के लिए की गई है। उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें विफल रहने पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे धनराशि वसूलने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान शनिवार को यहां 22 वर्ष के एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। कई स्थानीय व्यक्ति और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और पुलिस की एक मोटर साइकिल सहित छह वाहनों को आग लगा दी गई थी।

पुलिस ने बताया कि रामपुर में हिंसा के सिलसिले में अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 150 से अधिक की पहचान की गई है। संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कम से कम 17 लोग मारे गए थे और चल-अचल संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी। अधिकतर संपत्ति को नुकसान आगजनी में हुई थी।

संशोधित नागरिकता कानून और पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रस्तावित क्रियान्वयन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

सचिन की सुरक्षा घटी, आदित्य ठाकरे की बढ़ी

पेज 1 का बाकी

समिति ने सुरक्षा की समीक्षा की थी जिसके बाद विभिन्न लोगों पर खतरे का आकलन करते हुए उन्हें दी सुरक्षा में बदलाव किए गए। अधिकारी ने बताया कि समिति ने हाल की बैठक में तेंदुलकर और आदित्य ठाकरे के अलावा 90 से अधिक लोगों को दी गई सुरक्षा की समीक्षा की थी।

भारत रत्न से सम्मानित तेंदुलकर को अब तक 'एक्स' श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। इस श्रेणी के तहत एक पुलिसकर्मी 46 वर्षीय क्रिकेटर की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहता था। उनसे यह सुरक्षा तो वापस ले ली गई है लेकिन अब वह जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब है कि उनकी सुरक्षा में और पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। अब तक वर्ली के 29 वर्षीय विधायक को 'वाई प्लस' श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को 'जेड प्लस' श्रेणी की सुरक्षा और उनके भतीजे अजीत पवार को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे की सुरक्षा 'वाई प्लस' से बढ़ाकर 'जेड' श्रेणी की कर दी गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक की सुरक्षा 'जेड प्लस' से घटाकर 'एक्स' श्रेणी की कर दी गई। भाजपा के पूर्व मंत्रियों एकनाथ खड़से और राम शिंदे की सुरक्षा भी घटाई गई है। जानेमाने अधिवक्ता उज्ज्वल निकम की सुरक्षा 'जेड प्लस' से घटाकर 'वाई' श्रेणी कर दी गई। उन्हें सुरक्षा दस्ता दिया जाएगा। राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके कई लोगों की सुरक्षा भी आने वाले वक्त में घटाई जाएगी।

खुद से पूछें कि क्या उनका रास्ता सही था

पेज 1 का बाकी

था? उनकी प्रवृत्ति योग्य थी?' उन्होंने कहा, 'जो कुछ जलाया गया, बर्बाद किया गया क्या वह उनके बच्चों के काम आने वाला नहीं था?' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो सामान्य नागरिक जख्मी हुए, जो पुलिसवाले जख्मी हुए, उनके और उनके परिवारवालों के प्रति सोचें कि क्या बीतती होगी। झूठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों को, सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है, इसको सुरक्षित रखना, साफ-सुथरा रखना भी नागरिकों का ही दायित्व है। हक और दायित्व को हमें साथ-साथ याद रखना है।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विरासत में मिली समस्याओं को सुलझा रही है। उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 कितनी पुरानी बीमारी थी। कितनी कठिन लगती थी, हमें विरासत में मिली थी। हमारा दायित्व था कि कठिन से कठिन चीजों को सुलझाने का भरसक प्रयास करें। सब कुछ बहुत आराम से हुआ। सबकी धारणाएं चूर-चूर हो गईं। राम जन्मभूमि के इतने पुराने मामले का शांतिपूर्ण समाधान हुआ। अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता की गरिमा देने का रास्ता, ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस से निकाला गया है।'

इससे पहले उन्होंने लोकभवन परिसर में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज्यादा जोर अधिकारों पर दिया है, लेकिन अब हम आजादी के 75 साल पूरे होने की ओर बढ़ रहे हैं। समय की मांग है कि अब हम अपने कर्तव्यों पर भी उतना ही बल दें। सरकार का दायित्व है कि वह पांच साल नहीं बल्कि पांच पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए काम करने की आदत बनाए। उत्तर प्रदेश सरकार इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारा प्रयास रहा है कि सरकार से सत्ता सुख को निकालकर सेवा के संस्कार गढ़े जाएं। यह तभी संभव है जब आम आदमी के जीवन में सरकार का दखल कम से कम रखने की कोशिश हो। हमारा प्रयास है कि सरकार अटकाने, उलझाने के बजाय सुलझाने का माध्यम बने।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

सीएए : कर्नाटक सरकार ने अनुग्रह राशि देने की घोषणा वापस ली

बंगलुरु, 25 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए दो लोगों के परिजन को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की राज्य सरकार की घोषणा वापस ली जाती है।

मुख्यमंत्री ने दक्षिण कन्नड़ जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि पुलिस गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजन को अनुग्रह राशि देने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि अपराधियों को अनुग्रह राशि देना अपने आप में अक्षम्य अपराध है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया था, लेकिन अब हमने इसे वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री केरल से मंगलवार रात को लौटे और उन्होंने रात से लेकर सुबह तक अधिकारियों के साथ कई बैठके कीं। कहा कि उन्होंने पुलिस को 19 दिसंबर को दंगा करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि यह (मंगलुरु दंगा) षड्यंत्र था। लोगों ने पुलिस थाने के शस्त्रागार में घुसने की कोशिश की। हम किसी को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने निराधार आरोप लगाने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जब दिमाग नहीं काम करता है तब विपक्षी सदस्य इसी प्रकार की बात करते हैं। पूछे जाने पर कि विपक्ष मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बसवराज बोम्मई पर पुलिस गोलीबारी का आरोप मढ़ रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि बात के स्पष्ट साक्ष्य हैं कि आगजनी और लूट में उनका (दंगाइयों) हाथ है।

'प्रशासन केंद्रीकृत होना चाहिए, विकास विकेंद्रित'

अमरावती, 25 दिसंबर (भाषा)।

आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां बनाने की मुख्यमत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की योजना से असहमति जताते हुए उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडु ने बुधवार को कहा कि प्रशासन को केंद्रीकृत होना चाहिए, जबकि विकास विकेंद्रित होना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्य सचिवालय, हाई कोर्ट और विधानसभा एक जगह पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में राज्य सरकार को ही निर्णय करना है। नायडु ने अतुकुरु में अपने परिवार द्वारा संचालित स्वर्ण भारत ट्रस्ट में अनौपचारिक वार्ता में कहा कि मैं अपने 42 वर्षों के राजनीतिक अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहा हूं। इसे राजनीति या विवाद के नजरिए से न देखिए। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने संकेत दिया था कि दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर राज्य की तीन राजधानियां हो सकती हैं, जहां कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम में होगी, विधायी राजधानी अमरावती में होगी और न्यायिक राजधानी कुरनूल में होगी।

इसके बाद खासतौर से अमरावती क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां किसानों ने राजधानी के निर्माण के लिए अपनी 33,000 एकड़ उर्वर कृषि भूमि दी है। अब वे राज्य सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं।

किसानों ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति से भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि वह ध्यान दें कि राजधानी कहीं और न बने। नायडू ने कहा कि राज्य के दो हिस्सों में विभाजित होने के बाद, जब मैं केंद्रीय मंत्री था, मैंने यह कोशिश की कि विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह विकास विकेंद्रित होना चाहिए, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी प्रशासनिक कार्य एक जगह पर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उनसे पूछा तो वह इसी के पक्ष में राय देंगे। इसके साथ ही नायडू ने प्राथमिक शिक्षा में मातृ भाषा को प्रमुखता देने की बात कही।

सीएए विरोधी प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहने पर नागरिकों ने पुलिस का सम्मान किया

ठाणे, 25 दिसंबर (भाषा)।

मुंबई के नजदीक भिवंडी के निवासियों ने बुधवार को एक पुलिस अधिकारी का सम्मान किया। पिछले हफ्ते संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ एक बड़े विरोध-प्रदर्शन को सही तरीके से संभालने के लिए नागरिकों ने उन्हें सम्मानित किया। पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे का महाराष्ट्र की परंपरा के मुताबिक शॉल एवं श्रीफल (नारियल) देकर सम्मान किया गया।

ठाणे जिले में पावरलूम उद्योग का केंद्र भिवंडी सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थान माना जाता है और वहां 1970 और 1980 के दशकों में बड़े हिंदू-मुसलिम दंगे हो चुके हैं। पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद करीब एक लाख लोग सड़कों पर आ गए और सीएए व प्रस्तावित देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद यह समाप्त हो गया। बुधवार को हुए सम्मान समारोह में काफी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। उनमें से कुछ ने शिंदे और पुलिस बल की प्रशंसा की।

शिंदे ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस की सोशल मीडिया पर भी प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने गहन सुरक्षा व्यवस्था की थी और भीड़ पर नजर रखने तथा उसका प्रबंधन करने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें पूरा सहयोग किया जाएगा। शिंदे ने शांति बनाए रखने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया।

निवेशकों से 93 लाख की ठगी, दो पर मामला दर्ज

ठाणे, 25 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में दो लोगों पर करीब 35 निवेशकों से 93 लाख रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज हुआ है। इन पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को निवेश पर अच्छी राशि वापस दिलाने के बहाने ठगी की।

पुलिस के अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुमताज आलम शेख और मोहम्मद अयूब हुसैन निवेश कंपनी रिदाज इंडिया प्रॉपर्टीज के जरिए काम करते थे। इसका कार्यालय शहर के कपूरबावड़ी में है। हुसैन इस कंपनी का मालिक है जबकि शेख उसका प्रबंधक है। उन्होंने बताया, '2015 से दोनों, लोगों से जमीन, निर्माण, घर, कंपनी और बागवानी आदि योजनाओं में इस वादे के साथ निवेश कराते थे कि वह बाद में मोटी धनराशि वापस करेंगे।'

यमुना एक्सप्रेस-वे घोटाला

मथुरा की 57 हेक्टेयर जमीन खरीदी में हुई हेराफेरी

आशीष दुबे
ग्रेटर नोएडा, 25 दिसंबर।

मुख्य आरोपी पीसी गुप्ता को जून 2018 में दतिया से किया था गिरफ्तार, 15 महीने बाद सीबीआइ जांच करने को हुई तैयार

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) जमीन खरीद घोटाले में नामजद पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता समेत 21 अन्य में से 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार होने वाले सात अधिकारी यीडा में तैनात रहे हैं। घोटाला सपा शासन काल में 2013-15 के बीच मथुरा के सात गांवों में खरीदी गई जमीन 57.15 एकड़ को लेकर हुआ है। इस मामले में आरोपी एवं तत्कालीन एसीईओ सतीश कुमार को गत दिनों ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा टू पुलिस ने ओमीक्रॉन-1 स्थिथ सीजर सोसायटी से गिरफ्तार किया था।

165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में मथुरा के सात गांव मौदोर, सेउपट्टी बांगर, सेउपट्टी खादर, कलौना बांगर, कलोना खादर, सौतीपुरा बांगर, नौहझील और नौहझील बांगर में 2014 में 57.15 हेक्टेयर जमीन को समझौते के आधार पर खरीदा था। इस जमीन के यीडा के खरीदने से करीब चार महीने पहले इस जमीन को 19 व्यक्तियों व कंपनियों ने किसानों से खरीदा था। जबकि यीडा को यह जमीन खरीद मूल्य से दोगुने भाव पर बेची।

बाद में यीडा के अध्यक्ष रहे डॉ. प्रभात कुमार ने इस मामले की जांच कराई, जिसमें पता चला कि किसानों से जमीन खरीदने वाली मुखौटा कंपनियां थी। पीसी गुप्ता के रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं। अधिकांश ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, दिल्ली व मेरठ स्थित इन कंपनियों को चालाकी से भुगतान 30-30 लाख रुपए के छोटे टुकड़ों में चेक दिए गए। खास बात यह है कि इस भूमि की आज भी कोई उपयोगिता नहीं हो सकी है। आज भी यह जमीन अनुपयोगी और प्राधिकरण दर पर उपलब्ध है।

घोटाले में शामिल रहे आरोपियों में सात यीडा में तैनात रहे हैं। इसमें गुप्ता और डीसीईओ सतीश कुमार के अलावा विशेष कार्याधिकारी वीपी सिंह, तहसीलदार सुरेश चंद्र व रणवीर सिंह, नायब तहसील दार चमन सिंह, प्रबंधक परियोजना अतुल कुमार, प्रबंधक नियोजन बृजेश कुमार और लेखपाल पंकज कुमार शामिल हैं। जमीन की खरीद फरोख्त में गुप्ता के भतीजे स्वदेश गुप्ता व देवेश गुप्ता के नाम सामने आए हैं।

गुप्ता को 22 जून 2018 को मध्यप्रदेश के दतिया से गिरफ्तार किया गया था। रिमांड पर 10 दिन की पूछताछ के बाद मेरठ की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। यीडा निरीक्षक की जांच में अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं। इस मामले में सीबीआइ इंस्पेक्टर की भी गिरफ्तारी हुई है। उसे गाजियाबाद में आरोपियों को मदद पहुंचाने की एवज में रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा गया था।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

SYNDICATE BANK
C-34, 3rd Floor DDA Office Cum Shopping Complex, Opp Moolchand Hospital Lajpat Nagar Delhi-110024 Email : samb.delhi@syndicatebank.co.in

STRESSED ASSET MANAGEMENT BRANCH, DELHI
E- AUCTION SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002
*Sale of immovable/movable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as the Act).

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular that the under mentioned property mortgaged to Syndicate Bank, the possession of which had been taken by the Authorised Officer of the Bank under S. 13(4) of the Act will be sold by E- Auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and applicable interest, charges and costs etc as detailed below.

सम्पत्ति का विवरण

[illegible]

33. The particulars specified in the Description of property have been stated to the best of information of the Bank and the Bank will not be responsible for any error, misstatement or omission.
34. For further details contact Authorized Officer, Syndicate Bank, Stressed Asset Management Branch, C-34, IIIrd Floor, DDA Building cum Shopping Complex, Opp. Moolchand Hospital, Lajpat Nagar, New Delhi - 110024 Phone No. 011-24330599, 42258146, Email id: samb.delhi@syndicatebank.co.in

IMPORTANT INSTRUCTIONS
महत्वपूर्ण निर्देश
Bidding in the final minutes and seconds should be avoided in the bidders own interest. Neither Syndicate Bank nor Service Provider will be responsible for any failure/lapse (Power failure, Internet failure etc.) on the part of the vendor. In order to prevent such contingent situation bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as backup power supply etc required so that they are able to prevent such situation and continue to participate in the auction successfully. As per the new inter-operability guidelines released by the Controller of Certifying Authorities (CCA), the Secured Socket Layer (SSL) certificate for a e-procurement application is generated on a new algorithm, SHA2. Also, the Digital Certificate that will be applicable for these platforms have to be SHA2 algorithm compliant. For the same, the users have to ensure that they have Windows XP (SP3)/Windows Vista/Windows 7 installed in their respective PC/Laptop. In case of Windows XP service pack-3, if you get any issue you can install the SSL patch, which is available at our download section of our e-Auction Portal.
This is also a notice to the borrower/guarantor of the above said loan about holding of this sale on the above mentioned date/if their outstanding dues are not repaid in full.

Place: New Delhi
Date: 23.12.2019

For The Syndicate Bank
Authorised Officer

www.readwhere.com

फॉर्म नं. यूआरसी-2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) और कंपनीज़ (पंजीकृत करने के लिए अधिकृत) नियमों, 2014 के नियम 4 (1) के अनुवर्ती]

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा पंद्रह दिनों के बाद परन्तु तीस दिन से पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कानपुर को एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें मै. मिमहंस, एक साझेदारी फर्म कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत हो सकती है।
2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य नीचे अनुसार हैं:
   (i) मै. मिमहंस, एक साझेदारी फर्म, स्थित 281 और 283, मंगल पांडे नगर, विपरीत सीसीएस विश्वविद्यालय मेरठ, 250004 सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ नाम और शैली के तहत संबंधित व्यवसाय चलाने और अधिग्रहण हेतु जो ऐसे नियमों और शर्तों पर फर्म को परस्पर सहमति हो सकती है। कंपनी द्वारा इस तरह के अधिग्रहण के बाद उक्त फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा;
   (ii) बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों और अन्य सभी संबंधित गतिविधियों के उपचार के लिए अस्पताल के अधिग्रहण, स्थापना, चलाने और बनाए रखने के लिए व्यवसाय को आगे बढ़ाना;
   (iii) सभी प्रकार की दवाइयों, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, दवाओं, आदि और ऐसी सभी संबंधित गतिविधियों के निर्माण, आयात, निर्यात, थोक और/या खुदरा व्यापार करने के लिए व्यवसाय को आगे बढाना।
3 प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और असोसिएशन के आर्टिकल की प्रति का निरीक्षण कार्यालय स्थित 281 और 283, मंगल पांडे नगर, विपरीत सीसीएस विश्वविद्यालय मेरठ, 250004 में किया जा सकता है।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड -122050 में रजिस्ट्रार को लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करा सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजनी है।

आवेदकों के नामः 1. डॉ. अरूण शर्मा
2. डॉ. अर्चना शर्मा

दिनांकः 24 दिसंबर, 2019

ब्रिज एंड रूफ कॉ. (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No.: U27310WB1920GOI003601
दूसरा तल, जेवीएल प्लाजा, नं. 626, अन्ना सलाई, टेनामपेट, चेन्नई-600018

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी)

निम्नलिखित कार्य के लिये निर्धारित अर्हक मानदंड को पूरा करने वाली प्रतिष्ठित, साधन-सम्पन्न तथा अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में मद दर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं:

क्रम सं.	कार्य का विवरण तथा एनआइटी नं.	बी व आर वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज	बोली प्रस्तुत करने की नियत तिथि
1.	महाराष्ट्र राज्य के पलघर कलस्टर में 7 वर्षों के लिये एलईडी स्ट्रीट लाईट्स की मरम्मत और रखरखाव। एनआईटी नं.: बी व आर/ एमडीएस/ 71086/ एनआईटी- एलईडी रिपेयर एंड मेंटीनेन्स/ 02/ 1423, दिनांक 24.12.2019	24.12.2019	02.01.2020

इच्छुक साधन-सम्पन्न ठेकेदार कॉ. वेबसाईट **http://www.bridgeroof.co.in** से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। शुद्धिपत्र/ परिशोधन, यदि कोई होगा, केवल कॉ. वेबसाईटः **http://www.bridgeroof.co.in** में डाला जाएगा।

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
CIN No:- L74899DL1984PLC019097
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi - 110085
Ph: 91-11-46800600, 46800700; Fax No: 91-11-46800692
E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

NOTICE

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

FOLIO NO.	NAME OF HOLDER/ JOINT HOLDER	CERT. NO(S).	DISTINCTIVE NOS.	NO. OF SHARES	FACE VALUE OF SHARES (In ₹)
RNE0001073	Rakesh Kumar	100329	562026-564025	2000	1.00
	JT1: Anurag Arora	103429	60352116-60354115	2000	1.00
	JT2: Amit Arora	221116	248081737-248085736	4000	1.00

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with KFIN Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad -500032 or with the Company at its registered office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi – 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.

For **Relaxo Footwears Limited**
Sd/-
Vikas Kumar Tak
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 25th December, 2019

PROBATE
IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(TESTAMENTARY INTESTATE JURISDICTION)
CITATION U/s 283, INDIAN SUCCESSION ACT, 1925
In the matter of TEST CASE No. 88/2019
BHAVISH SINGH DAVAR ...PETITIONER
V/S
THE STATE AND ORS. ...RESPONDENTS

To,
All Concerned,
In the matter of estate of **Late Ms. Nira Davar, Wife of Mr. G.S. Davar, R/o A-1, Ground Floor, Greater Kailash-1, New Delhi-110048.**
Whereas **Bhavish Singh Davar, S/o Mr. Praneet Singh Davar, R/o A-1, Greater Kailash-1, New Delhi-110048 has filed a petition under Sections 278 and 232 read with Section 371 and 300 of the Indian Succession Act, 1925 for grant of Letters of Administration in respect of Will dated 15.02.2017 of Ms. Nira Davar, deceased.**
And whereas the aforesaid case is fixed for hearing before this **Hon'ble court on 14.04.2020 at 10.30 A.M.** This citation is issued, in terms of Section 283 of the said Act to all persons claiming to have any interest in the properties of the said deceased to come to this Court, file objections, if any and take part in the proceedings on the date specified above for the grant of Letters of Administration.
Given under my hand and the seal of this Court, in terms of the order dated 26th day of November, 2019.

Assistant Registrar(O)
for REGISTRAR GENERAL
RB

एलसीबी नोएडा शाखा
बी-117, प्रथम तल, सेक्टर-18, नोएडा, उ.प्र.-201301

अचल सम्पत्ति कब्जा लेने की सूचना
[नियम-नियम 4 (2ए) के अनुसार]

1. मै. प्राईम इंडिया
पंजी. कार्यालयः डी-199, 1 ला तल, नर्मदा अपार्टमेन्ट्स, अलकनंद, नई दिल्ली-110019
2. श्री प्रभनूर सिंह
पार्टनर, मै. प्राईम इंडिया बी-35, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092
3. सुश्री प्रभजोत कौर, पार्टनर, मै. प्राईम इंडिया
डी-199, 1 ला तल, नर्मदा अपार्टमेन्ट्स, अलकनंद, नई दिल्ली-110019

आपके द्वारा प्राप्त ऋण के मामले में जो 30.09.2019 को रु. 1,64,13,537 (रुपये एक करोड़ चौसंठ लाख तेरह हजार पांच सौ सैंतीस मात्र) की शेष बकाया राशि के साथ एनपीए हो चुकी है, के लिये हमने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना तिथि 5.10.2019 जारी किया था जिसके द्वारा आपको सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ ब्याज, लागत आदि लौटाने का निर्देश दिया था। उक्त सूचना में हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि आप 60 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार कब्जा कर लिया जायेगा। हमारे पत्र तिथि 7.11.2019 से हमने यह भी सूचित किया था कि ए-58, सेक्टर-80, नोएडा में पड़ी शेष स्टॉक्स भिवाड़ी, राजस्थान में शिफ्ट कर दी गई है।
चूंकि आप इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का 20 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है तथा उक्त अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार पंचनामा तथा इन्वेन्टरी तैयार किया गया है जो इसके साथ संलग्न है।
आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 4 (2 ए) के अनुपालन में जारी की जा रही है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
कवाच सिक्युरिटी यार्ड, नीलम चौक के निकट, यूआईडी क्वार्टस के समीप, भिवाडी, राजस्थान में वर्तमान में पड़ी स्टॉक एवं मशीनरीज।

तिथिः 20.12.2019 प्राधिकृ अधिकारी
स्थानः नोएडा सिंडीकेट बैंक

फार्म संख्या आईएनसी-26
[कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष
कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) साथ में पठित कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के मामले में
एवं
बीएसए इंडिया फूड इंग्रेडिएंटस प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 298, मंदाकिनी इन्क्लेव नई दिल्ली-110019 में स्थित है, के मामले में
एवं
पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली से राजस्थान राज्य में परिवर्तन के मामले में

कम्पनीज अधिनियन, 2013 की धारा 13 के अर्तगत एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचना प्रदान की जाती हैं कि 11 जुलाई, 2019 को सम्पन्न सदस्यों की वार्षिक साधारण बैठक/विशेष सामान्य साधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव में कम्पनी के मेमोरन्डम ऑफ एसोसियेशन में बदलाव पारित करते हुए ताकि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "नई दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में स्थानांतरित किया जा सके, हेतु केन्द्रीय सरकार से पुष्टिकरण हेतु आवेदन प्रस्तावित है।
किसी भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र में दाखिल कर अथवा कारण को पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा शपथपत्र की एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली - 110003 को इस सूचना प्रकाशन के 14 (चौदह) दिनों के भीतर प्रस्तुत करें और एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके यहाँ पर उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय 298, मंदाकिनी इन्क्लेव नई दिल्ली-110019 को प्रेषित करें।

बीएसए इंडिया फूड इंग्रेडिएंटस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से उनके लिए
हस्ता०/-
रामप्रसाद पांडुरंगन
निदेशक
तिथि : 26/12/2019
स्थान : नई दिल्ली

तेल व गैस क्षेत्रों के विवादों के समाधान के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

सरकार ने तेल एवं गैस क्षेत्रों के विवादों के समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विवादों की वजह से इस क्षेत्र में निवेश प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञ समिति के जरिए तेल व गैस क्षेत्र की खोज और उत्पादन से संबंधित विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सकेगा और इसके लिए लंबी न्यायिक प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं होगी। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 'प्रबु' बाहरी व्यक्तियों-विशेषज्ञों' की विवाद समाधान समिति में पूर्व पेट्रोलियम सचिव जीसी चतुर्वेदी, आयल इंडिया लि. के पूर्व प्रमुख विकास सी बोरा और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक सतीश पई को शामिल किया गया है।

समिति का कार्यकाल तीन साल का होगा और किसी विवाद के समाधान तीन महीने में करने का प्रयास किया जाएगा। भारत का तेल व गैस क्षेत्र विवादों से लगातार प्रभावित रहा है। लागत वसूली से लेकर उत्पादन लक्ष्य सभी चीजों पर विवाद पैदा होता है। कंपनियों के साथ-साथ सरकार को भी विवादों के निपटान के लिए महंगी मध्यस्थता प्रक्रिया और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है।

नीति आयोग के सदस्य ने कहा जीएसटी की केवल दो दरें हों

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि माल व सेवा कर (जीएसटी) के तहत सिर्फ दो स्लैब होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में बार-बार बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। जरूरत होने पर जीएसटी की दरों में वार्षिक आधार पर बदलाव किया जाना चाहिए।

जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। सभी अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो गए। उस समय से जीएसटी की दरों में कई बार बदलाव किया जा चुका है। अभी जीएसटी के तहत चार स्लैब- 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद हैं। कई उत्पाद ऐसे हैं जिनपर जीएसटी नहीं लगता। वहीं पांचे ऐसे उत्पाद हैं जिनपर जीएसटी के अलावा उपकर भी लगता है।

रमेश चंद ने कहा कि जब भी कोई बड़ा कराधान सुधार लाया जाता है, तो शुरुआत में इसमें समस्या आती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर देशों में जीएसटी को स्थिर होने में समय लगा। नीति आयोग के सदस्य चंद कृषि क्षेत्र को देखते हैं। उन्होंने जीएसटी की दरों में बार-बार बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे समस्याएं पैदा होती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुआई वाली जीएसटी परिषद वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर तय करती है। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी परिषद के सदस्य हैं। जहां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने की मांग बार-बार उठती है वहीं कर के स्लैब घटाने की बात भी की जाती है।

चंद ने कहा कि हरेक क्षेत्र द्वारा जीएसटी की दर कम करने की मांग प्रवृत्ति बन गई है। मेरा मानना है कि जीएसटी के मुद्दे दरों को कम करने से कहीं बड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम बार-बार दरों में बदलाव नहीं कर सकते। हमें अधिक दरें नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ दो दरें होनी चाहिए। चंद ने कहा कि हमें अपना ध्यान नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से राजस्व संग्रह बढ़ाने पर लगाना चाहिए, बजाय दरों में बार-बार बदलाव करने के। उन्होंने कहा कि अगर दरों में बदलाव करने की जरूरत है तो भी, तो यह वार्षिक आधार पर होना चाहिए।

चंद कृषि अर्थशास्त्री भी हैं। प्रसंस्कृत खाद्य मसलन डेयरी उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटाने की मांग पर चंद ने कहा कि इसे उत्पादों पर पांच फीसद की दर 'काफी-काफी उचित' है।

कंपनियों के अधिग्रहण, विलय सौदों में पूरे साल रही सुस्ती

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय कारोबारी जगत पर 2019 के दौरान कर्ज उतारने के भारी दबाव के बीच विलय व अधिग्रहण सौदों में सुस्ती रही।

वैश्विक व्यापार युद्ध के वातावरण में विदेशी कंपनियों ने अधिग्रहण की योजनाओं से हाथ खींचे रखा। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगर आर्थिक सुधारों ने असर दिखाना शुरू किया तो विलय व अधिग्रहण गतिविधियों में नए साल से तेजी आ सकती है। कंपनी संचालन में खामियों और धन की भारी कमी की वजह से भी 2019 में घरेलू अधिग्रहण गतिविधियां प्रभावित हुईं जबकि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध समेत अन्य विभिन्न कारकों से वैश्विक स्तर पर भी सौदे प्रभावित हुए।

एनटीपीसी 2022 तक 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी की योजना 2022 तक 10 गीगावॉट (10,000 मेगावॉट) सौर बिजली क्षमता जोड़ने की है। एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश मुख्य रूप से ग्रीन बांड के जरिए वित्तपोषित किया जाएगा। अभी एनटीपीसी की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 920 मेगावॉट की है। इसमें मुख्य रूप से सौर बिजली क्षमता शामिल है।

एनटीपीसी ने 2032 तक 130 गीगावॉट (1.30 लाख मेगावॉट) क्षमता की कंपनी बनने के लिए दीर्घावधि की योजना बनाई है। इसमें से 30 फीसद क्षमता अक्षय ऊर्जा की होगी। सूत्र ने कहा कि कंपनी इस वित्त वर्ष के अंत तक 2,300 मेगावॉट सौर ऊर्जा के लिए निविदा निकालने का काम पूरा कर लेगी। उसके बाद कंपनी की योजना 2020-21 और 2021-22 में चार-चार गीगावॉट की क्षमता और जोड़ने की है।

'वैश्विक पोत पुनर्चक्रण कारोबार में हिस्सेदारी 60 फीसद पहुंचेगी'

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

नया कानून आने के बाद भारत वैश्विक पोत पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) कारोबार में 60 फीसद हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख लाल मंडाविया ने एजंसी से इंटरव्यू में कहा कि भारत युद्धपोत और अन्य जहाजों के लिए प्रमुख रिसाइक्लिंग गंतव्य के रूप में उभर सकता है।

मंडाविया ने उम्मीद जताई कि पोत रिसाइक्लिंग गतिविधियों की देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी बढ़कर 2.2 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगी, जो मौजूदा स्तर से दोगुना होगी। मंडाविया ने कहा कि गुजरात का अलांग दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यह देश में जहाजों की रिसाइक्लिंग की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए तैयार है।

अभी भारत वैश्विक स्तर पर दुनिया में वार्षिक आधार पर नष्ट किए जाने वाले 1,000 जहाजों में से 300 को रिसाइकल करता है। इस बारे में वैश्विक संधि का अनुमोदन नहीं किए जाने की वजह से जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे अभी अपने जहाजों को रिसाइक्लिंग के लिए भारत नहीं भेजते हैं। हालांकि, सरकार मानता है कि पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 से इस परिदृश्य में बदलाव आएगा। इस कानून ने हांगकांग संधि को अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत जहाजों की पर्यावरणनुकूल पुनर्चक्रण प्रक्रिया और पोत कारखाने में काम करने वालों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान है।

मंत्री ने कहा- अमेरिका और कुछ अन्य देश अभी अपने जहाजों को भारत में पुनर्चक्रण के लिए नहीं भेजते, लेकिन अब हमने हांगकांग संधि को अनुमोदित कर लिया है।

म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए अच्छा रहा 2019

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) में इस साल यानी 2019 में चार लाख करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से निवेशकों का भरोसा कायम करने के लिए उठाए गए कदमों और ऋण योजनाओं में मजबूत प्रवाह से म्यूचुअल फंड उद्योग की यह रफ्तार अगले साल भी जारी रहेगी।

ऋण आधारित योजनाओं में भारी निवेश की वजह से 2019 म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक अच्छा वर्ष साबित हुआ है। बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से इक्विटी कोषों में इस साल निवेश का प्रवाह घटा है। एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनएस वेंकटेश ने कहा कि 2020 में यह उद्योग 17 से 18 फीसद की दर से वृद्धि दर्ज करेगा। शेयर बाजारों में सुधार की उम्मीद के बीच इक्विटी कोषों में निवेश का प्रवाह सुधरेगा।

एम्फी के आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां या एयूएम 2019 में 18 फीसद यानी 4.2 लाख करोड़ रुपए बढ़कर नवंबर के अंत तक 27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गईं। यह इसका सर्वकालिक उच्चस्तर है। दिसंबर, 2018 के अंत तक म्यूचुअल फंड कंपनियों का एयूएम 22.86 लाख करोड़ रुपए था। 2019 लगातार सातवां साल रहा है जबकि म्यूचुअल फंड उद्योग का एयूएम बढ़ा है। नवंबर, 2009 में उद्योग का एयूएम 8.22 लाख करोड़ रुपए था, जो नवंबर, 2019 तक 27 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी दस साल में एयूएम तीन गुना हो गया है।

इस साल इक्विटी से संबंधित योजनाओं में निवेश का प्रवाह 70,000 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले साल के 1.3 लाख करोड़ रुपए की तुलना में काफी कम है। नवंबर में इन योजनाओं में निवेश 41 माह के निचले स्तर यानी 1,312 करोड़ रुपए रहा।

सार्वजनिक सूचना
फार्म नं. आईएनसी-25ए
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

समक्ष केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कंपलेक्स, नई दिल्ली-110003
कंपनी अधिनियम 2013 धारा 14 कंपनी अधिनियम 2013 की कंपनी (निगमित) नियमावली, 2014 के नियम 41 के संबंध में
एवं
गुप्ता शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड
CIN : U74899DL1993PLC054289
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 204, सिद्धार्थ बिल्डिंग 96, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019
....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 11 दिसम्बर 2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।
यदि कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है, अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कंपलेक्स, नई दिल्ली 110003 के पास इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि के 14 दिनों के भीतर भेज या पहुंचा सकता है तथा इसके समर्थन में एक शपथ पत्र भी संलग्न होना चाहिए जिसमें वह अपने हित का ब्योरा और विरोध का कारण बताए, साथ ही साथ आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर एक प्रति भी भेजें।

कृते एवं ओर से
गुप्ता शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड
हस्ता/-
मधेश चन्द गुप्ता (?)
निदेशक
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 23.12.2019 डीआईएन : 00376403

राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण, इलाहाबाद में (मूल क्षेत्राधिकार)
कंपनी आवेदन संख्या २०१९ का ४९७
जो सम्बंधित है कंपनी आवेदन नम्बर २०१९ का ७९ से कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३० से २४० (यथा सीमा तक लागू) के मामले में
तथा
भाईजी पोर्टफोलियो लिमिटेड .....आवेदक / अन्तरक कंपनी - ०१
तथा
भाईजी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ....आवेदक / अन्तरक कंपनी - ०२
सभी कंपनी अधिनियम १९५६ के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत है दोनों कंपनियों का पंजीकृत कार्यालय **५-डी ऊपरी ग्राउंड फ्लोर, अंसल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-२०१०१० है**
आवेदन की सार्वजनिक सूचना
भाईजी पोर्टफोलियो लिमिटेड आवेदक/अन्तरक कंपनी ०१ के साथ भाईजी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड आवेदक/अन्तरक कंपनी - ०२ के समामेलन की योजना के लिए आन्तिरिक कंपनियों तथा अंतरिती कंपनी के सन्दर्भ में राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण, इलाहाबाद के स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ के धारा २३० - २३२ के अंतर्गत ऊपर निर्मित आवेदक कंपनियों द्वारा ९ दिसम्बर, २०१९ को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे ९ दिसम्बर, २०१९ को एडमिट किया गया है तथा अब उक्त आवेदन पर माननीय सदस्य न्याय/पीठ के माननीय सदस्य द्वारा ९ जनवरी २०२० को सुनवाई निर्धारित की गई है आवेदन का समर्थन अथवा विरोध करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने आशय के सूचना इस तरह भेजे के वह आवेदन की अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व आवेदकों के अधिवक्ता के पास पहुंचाया जाए। यदि उन्हें आवेदनों का विरुद्ध करना है तो सूचना के साथ, साथ आपत्ति के कारणों अथवा शपथ पत्र की एक प्रति अवश्य संलग्न करना उसके लिए एक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता/-
दिनांक : 24-12-2019 तन्मय साथ (?)
स्थान : गाजियाबाद (अधिवक्ता)
आवेदक के सलाहकार
२३/१९ सी - वाधी - चिंतामणि रोड
इलाहाबाद - २११००२, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
पत्रांक 194-95/सात-17 दिनांक शाहजहांपुर 25.12.2019

री-टेण्डर

दिनांक 13.12.2019 कम्प्यूटरों के आमंत्रित टेण्डर को पुनः दि. 28.12.2019 तक आमंत्रित किया जाता है।

हस्ता./-
निदेशक
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,
शाहजहॉपुर।

पंजीकृत कार्यालयः सॉलिटेर कार्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 4, छठा तल, चाकला, अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई-400093, टेली. नं.: 022-66572700, वेबसाइटः www.sicomindia.com

सार्वजनिक नीलामी सूचना तिथि 03 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से फाइनेंशियल एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) तथा जनसत्ता (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित '[illegible] लिमिटेड' की गिरवी परिसम्पत्तियों के लिये समय-सीमा में [illegible]
कृपया ध्यान दें कि 3 जनवरी, 2020 को 3.00 बजे अप. में [illegible] सार्वजनिक नीलामी की समय सीमा 6 जनवरी, 2020 के 3.00 बजे [illegible] दी गई है जो मुम्बई में सिकॉम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी।
बिक्री के अन्य सभी सामान्य नियम एवं शर्तें तथा स्विस चैलेंज [illegible] शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

तिथिः 26 दिसम्बर, 2019 हस्ता./-
स्थानः मुम्बई प्राधिकृत अधिकारी

दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत बिक्री सूचना
ई-नीलामी बिक्री सूचना
फ्री कल्चर एप्पैरल्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापकः अशोक कुमार जुनेजा (आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-18/10286)
ई-मेलः **freeculture.liquidator@gmail.com**, मो.नं. +91-9810532462
नीलामी की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 10 जनवरी, 2020 को 12.00 बजे दोप. से 4.00 बजे अप.

नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार परिसमापक के कब्जे में ''जैसा है जहाँ है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'', ''जो कुछ भी वहाँ है आधार'' तथा ''उपचार-रहित आधार'' पर निम्न परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये एतद्द्वारा इच्छुक व्यक्तियों/भागीदारों से प्रस्ताव आमंत्रित है जो 7 जनवरी, 2020 के 5.00 बजे अप. तक ई-नीलामी प्लेटफार्म http://ncltauction.auctiontiger.net पर ऑनलाइन जमा की जायेगी।

अचल परिसम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	बोली वृद्धि मूल्य	ई-नीलामी तिथि एवं समय (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
ट्रेडमार्क्स (ब्रैण्ड नाम, डोमैन नाम) (Frecultr.com) सभी संबंधित ब्रैण्ड नाम तथा लोगो, पोप अप ई-मेल आईडी ज, सभी लोगो, सभी आइपीआर राइट्स, सभी ब्रैण्ड गुडविल राइट्स तथा सभी सोसल मीडिया राइट्स	262500/- (रुपए दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र)	25000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र)	10,000/- (रुपए दस हजार मात्र)	10, जनवरी, 2020 12 बजे दोपहर से 4 बजे अप.	7 जनवरी, 2020

1. इच्छुक बोलीदाताओं को ''फ्री कल्चर एप्पैरल्स प्रा.लि.- परिसमापन के अधीन'' की खाता, खाता नं. 022505004557, आईसीआईसीआई बैंक, शाखाः लाजपत नगर, दिल्ली, आईएफएससी कोड ICICI0000225 के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक के दिल्ली में भुगतान योग्य डीडी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा।
2. परिसम्पत्तियों के विवरण, ऑन लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा तथा अंडरटैकिंग फार्म, ऑन लाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्कः श्री तिलक मराठा एवं श्री पुष्पित मारू, + 91-6351896834/ 079 61200 580/ 554/ 594/ 598, ई-मेलः Tilak@auctiontiger.net/ pushpit@auctiontiger.net/ support@auctiontiger.net

हस्ता./-
अशोक कुमार जुनेजा
(फ्री कल्चर अप्पैरल्स प्रा.लि. (परिसमापन में) के परिसमापक
IBBI पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00117/2017-18/10286
पताः 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
ई-मेलः **freeculture.liquidator@gmail.com**

तिथिः 26.12.2019
स्थानः दिल्ली

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.
कॉर्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा)
फोनः 0124-4212530/31/32, ई-मेल : customercare@shubham.co वेबसाइट : www.shubham.co

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लि. (यहां के बाद शुभम के नाम से विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित ब्याज तथा उस पर ब्याज के लिये शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्र. सं.	ऋण सं./ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों का नाम	माँग सूचना राशि	माँग सूचना तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति	एफिक्शेसन की तिथि
1.	DEL_1508_043411, श्री अनिल कुमार सिंह, सन्ध्या सिंह	रु. 7,18,646/-	22.05.2017	फ्लैट नं. 403, ऊपरी तल (बैक साइड), खसरा नं. 1146, प्लॉट नं. बी-23, हिण्डन विहार, बरौला, सेक-42, नोएडा-201301	20.12.2019
2.	0DEL1705000005005874, मुजम्मिल राना, मेहनाज	रु. 25,35,108/-	29.08.2019	फ्लैट नं. 12, प्रथम तल, खसरा नं. 735डी, 128/6, ग्राम किर्लोकरी, दिल्ली दक्षिण दिल्ली-110014	20.12.2019
3.	0MDG1607000005001176, विम्पी लूथरा, अयेतुल्ला एसएम	रु. 10,74,878/-	29.08.2019	मकान सं. 229, खसरा नं. 332, फ्लैट नं. ई-32, दूसरा तल, नेव सराय, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110062	20.12.2019
4.	DEL_1505_040103, सुमित कुमार, अतरकली	रु. 8,07,142/-	16.09.2019	खसरा नं. 1085/2121, पंचवटी कॉलोनी, ग्राम-बेहटा हाजीपुर लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102	20.12.2019
5.	KHI_1505_038565, नरेश कुमार, मिथलेश कुमारी	रु. 7,58,689/-	19.08.2016	खसरा नं. 13 मिन, ग्राम-गढ़ी चौखंडी, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतमबुध नगर (उ.प्र.)-203207	04.01.2017
6.	SHB_1412_031131, श्री उस्मान, मोह. मकसूद सिद्दिकी	रु. 11,79,638/-	19.08.2016	प्लॉट नं. सी-47/1, खसरा नं. 638 मिन, ग्राम-परसौण्डा, अली प्रेम गार्डन कॉलोनी, परगणा-लोनी, तहसील एंव जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102	20.12.2019

स्थान : गुड़गांव प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 24.12.2019 शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांस कम्पनी लि.

ब्रिज एंड रूफ कॉ. (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No.: U27310WB1920GOI003601
दूसरा तल, जेवीएल प्लाजा, नं. 626, अन्ना सलाई, टेनामपेट, चेन्नई-600018

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी)

निम्नलिखित कार्य के लिये निर्धारित अर्हक मानदंड को पूरा करने वाली प्रतिष्ठित, साधन-सम्पन्न तथा अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में मद दर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं:

क्रम सं.	कार्य का विवरण तथा एनआइटी नं.	बी एंड आर वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज	बोली प्रस्तुत करने की नियत तिथि
1.	राज्य नोडल एजेंसी (एसएनएज) की ओर से एसएमएसएल हेतु ई ऑफ- ग्रिड और डीसेंट्रलाइज्ड सोलर पीवी एप्लिकेशन स्कीम के अंतर्गत असम में सोलर एलईडी स्ट्रीट लाईट्स का डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति, लगाना, परीक्षण तथा चालू करने के साथ संपूर्ण सिस्टम की वारंटी व इसकी 5 वर्षों की एएमसी। एनआइटी नं.: बी व आर/ एमडीएस/ 71108/ ईईएसएल/ एसएसएलएस/ असम/ एनआईटी/ 02/ 1424, दिनांक 24.12.2019	24.12.2019	02.01.2020

इच्छुक साधन-सम्पन्न ठेकेदार कॉ. वेबसाईट **http://www.bridgeroof.co.in** से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। शुद्धिपत्र/ परिशोधन, यदि कोई हो, केवल कॉ. वेबसाईटः **http://www.bridgeroof.co.in** में डाला जाएगा।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (परियोजना), सी.एल. जोन का कार्यालय
सिंधोरा कलां, शक्ति नगर, नई दिल्ली-110052 टेली. नं.011-23654558
सं.ईईपीआर/टीसी/सीएलजेड/2019-20/10 दिनांकः 24.12.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र.सं.	उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चरण	प्रारंभ तारीख	समाप्ति समय
1.	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध का प्रारंभ	30.12.2019	अपराह्न 17.30 बजे
2.	निविदा दस्तावेज जारी करने का प्रारंभ	30.12.2019	अपराह्न 17.31 बजे
3.	निविदा दस्तावेज हेतु अनुरोध का अंत	08.01.2020	अपराह्न 17.00 बजे
4.	निविदा दस्तावेज जारी करने का अंत	08.01.2020	अपराह्न 17.30 बजे
5.	निविदा दस्तावेज समाप्ति की तारीख एवं समय	10.01.2020	अपराह्न 12.00 बजे
6.	लागत खोलने की तारीख एवं समय	10.01.2020	अपराह्न 12.15 बजे

कमिश्नर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अधिशासी अभियंता (परियोजना), सिविल लाइन जोन द्वारा निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु (सामान्य विंग) के साथ पंजीकृत अनुमोदित एवं पात्र संविदाकारों से सीलबंद प्रतिशत दर निविदाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट **https://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER** पर आमंत्रित की जाती हैं। ***इच्छुक संविदाकारों से मूल्य बोली में सकारात्मक रूप से अपनी फर्म के नाम का उल्लेख करने का अनुरोध किया जाता है, यदि मूल्य बोली में नाम का उल्लेख नहीं किया गया होगा तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।***

क्र.सं.:1, कार्य का नामः वार्ड सं.14एन/सीएलजेड में टैगोर पार्क में आर.एम.सी. उपलब्ध करवाकर सड़कों और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण/सुधार। **एफटीसी सं.19/66/XL-VIII-S (d)/PC-066 लेखा शीर्षः** XL-VIII-S(d) **निविदा राशिः** 1,28,69,529/- रु. **धरोहर राशिः** 2,57,400/- रु.

क्र.सं.:2, कार्य का नामः वार्ड सं.14एन/सीएलजेड में टैगोर पार्क एक्सटेंशन में आर.एम.सी. उपलब्ध करवाकर सड़कों और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण/सुधार। **एफटीसी सं.19/66/XL-VIII-S (d)/PC-066 लेखा शीर्षः** XL-VIII-S(d) **निविदा राशिः** 80,63,557/- रु. **धरोहर राशिः** 1,61,300/- रु.

सभी मदों हेतु निविदा लागत 1000/- रुपए है। मद सं. 1 हेतु कार्य पूरा करने का समय 09 महीने और मद सं. 2 हेतु 06 महीने है। सभी मदों हेतु दरें मान्य रहने की अवधि छः महीने है।

Sd/-
R.O. No. 197/North/DMC/2019-20 **Executive Engineer (Pr.) CLZ**

www.readwhere.com

खबर कोना

क्रिसमस की पूर्व संध्या पर डिनर के लिए पाम बीच पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप।

दुबई में सड़क दुर्घटना में दो भारतीय छात्रों की मौत

दुबई, 25 दिसंबर (भाषा)।

दुबई में क्रिसमस के दिन बुधवार को तड़के एक सड़क दुर्घटना में दो भारतीय छात्रों की मौत हो गई। खलीज टाइम्स की खबर के अनुसार रोहित कृष्णकुमार (19) और शरत कुमार (21) एक क्रिसमस पार्टी से लौट रहे थे और रास्ते में सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों पीड़ित केरल के रहने वाले थे। कृष्णकुमार ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा था जबकि शरत अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। दोनों अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने दुबई आए थे। नों ने स्कूली शिक्षा दुबई में ली थी।

सीमा के निकट ईरानी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त

तेहरान, 25 दिसंबर (एपी)।

आजरबैजान के साथ सीमा के निकट ईरान के उत्तरी क्षेत्र में बुधवार को एक ईरानी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए बताया कि पायलट की स्थिति का तत्काल पता नहीं चल पाया है। टीवी रिपोर्ट के अनुसार सबलान पर्वतीय क्षेत्र में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और तीन हेलीकॉप्टरों के जरिए पायलट की तलाश की जा रही है। इस लड़ाकू विमान की हाल में ही मरम्मत की गई थी। पायलट विमान का उड़ान परीक्षण कर रहा था और विमान ने उत्तरपश्चिम ईरान में तबरेज एयरबेस से उड़ान भरी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

नई प्रणाली अंतरिक्ष के कबाड़ का ठीक-ठीक पता लगाएगी

बीजिंग, 25 दिसंबर (भाषा)।

चीन के अनुसंधानकर्ताओं ने धरती की कक्षा में मौजूद अंतरिक्षीय कबाड़ का सही-सही पता लगाने की प्रणाली में सुधार किया है जिससे अंतरिक्षयान अभ्यासों के लिए सुरक्षित मार्ग तय करने का प्रभावी तरीका उपलब्ध हो सकेगा।

वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के कबाड़ की पहचान करने की प्रणालियां पहले भी विकसित की हैं लेकिन वे उनके छोटे-छोटे टुकड़ों का तेजी से पता लगाने में उतनी कारगर नहीं होती। लेजर रेंज वाले टेलीस्कोप के लिए अल्गोरिद्म के एक अनूठे सेट ने अंतरिक्षीय कबाड़ का सही-सही पता लगाने की सफलता दर में सुधार किया है। लेजर रेंज वाली प्रौद्योगिकी वस्तुओं से लेजर प्रतिबिंब को उनकी दूरी मापने के लिए इस्तेमाल करती है।अंतिरक्षीय कबाड़ की सतह से आने वाली प्रतिध्वनि बहुत कमजोर होती है जिससे सटीकता घटती है। पूर्व के तरीकों में कबाड़ का सही-सही पता लगाने में लेजर रेंजिंग में सुधार किया था लेकिन एक किलोमीटर तक।

हांगकांग : पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर झड़प

हांगकांग, 25 दिसंबर (एएफपी)।

हांगकांग में पुलिस और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों का असर बुधवार को क्रिसमस के त्योहार पर भी देखने को मिला। चीन समर्थक नेता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने त्योहार के उत्साह को फीका कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मॉलों और शहर के कई जिलों में प्रदर्शन किए, उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

मोंग कोक में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले छोड़े। इस इलाके में पिछले छह महीनों में अक्सर झड़पें देखने को मिली हैं। स्थानीय टीवी पर प्रसारित खबरों के मुताबिक दो मॉलों में पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़पें हुईं। कई युवा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।

हालांकि, बुधवार को हुई झड़पें क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हुई झड़पों की तुलना में कम देर तक चली। हांगकांग की चीन समर्थक नेता केरी लाम ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हुए प्रदर्शनों की बुधवार को फेसबुक पोस्ट में निंदा करते हुए उन्हें लापरवाह और स्वार्थी दंगाई कहा। हांगकांग में ईसाई आबादी की अच्छी खासी आबादी है लेकिन इस बार क्रिसमस का त्योहार फीका रहा।

बुर्किना फासो में आतंकी हमले में 35 की मौत

औगाडौगू, 25 दिसंबर (एएफपी)।

उत्तरी बुर्किना फासो में मंगलवार को आतंकवादी हमले में 35 नागरिक मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश में पिछले पांच वर्ष में यह सबसे घातक हमला है। सेना ने बताया कि सैन्य अड्डे और सौउम प्रांत के अरबिंदा शहर में हुए दो हमलों में सात सैनिक और 80 जिहादी भी मारे गए।

माली और नाइजर सीमा से लगे बुर्किना फासो में लगातार जिहादी हमले होते रहते हैं। ऐसे हमलों में 2015 की शुरुआत से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।

आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा, 'आतंकवादियों के एक बड़े गुट ने सैन्य अड्डे और अरबिंदा में आम नागरिकों पर एक साथ हमला किया।'

बुर्किना फासो के राष्ट्रपति रोश मार्क काबोर ने ट्वीट किया, 'बर्बर हमले में 35 नागरिक मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं।' उन्होंने साथ ही रक्षा एवं सुरक्षा बलों की वीरता और प्रतिबद्धता की सराहना भी की। संचार मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता रेमीस डंडजिनौ ने बाद में बताया कि 31 महिलाएं मारी गई हैं और करीब 20 सैनिक घायल हुए हैं।

राष्ट्रपति ने 48 घंटे के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सेना ने बताया कि मोटरसाइकिलों पर सवार जिहादियों ने सुबह हमला किया जो कई घंटों तक चला। बाद में, वायु सेना की मदद से सशस्त्र सेना ने आतंकवादियों को खदेड़ दिया।

किसी समूह ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह अक्सर यहां जिहादी हमलों को अंजाम देते रहते हैं।

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में 6.3 तीव्रता का भूकम्प

पोर्ट हार्डी (कनाडा), 25 दिसंबर (एपी)।

ब्रिटिश कोलंबिया में तट के निकट मंगलवार को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वे ने बताया कि भूकंप रात आठ बजकर 36 मिनट पर आया और इसका केंद्र पोर्ट हार्डी के पश्चिम में 182 किमी की दूरी पर और 10 किमी की गहराई पर था। अलास्का में राष्ट्रीय सुनामी केंद्र ने बताया कि सुनामी की आशंका नहीं है। सोमवार को ब्रिटिश कोलंबिया में 4.8 से 6.0 तीव्रता के भूकंप के पांच झटके आए थे।

इंडोनेशिया बस दुर्घटना में 8 बच्चों समेत 28 की मौत

जकार्ता, 25 दिसंबर (एएफपी)।

इंडोनेशिया में घातक बस दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या 28 पहुंच गई है जिसमें आठ बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बचाव दल नदी में लोगों की खोज कर रहा है। पुलिस के अनुसार दक्षिणी सुमात्रा प्रांत में सोमवार को बस 150 मीटर गहरी घाटी में गिर कर नदी में चली गई थी।

स्थानीय पुलिस प्रमुख डॉली गुमारा ने बुधवार को कहा कि नदी में मंगलवार को एक और शव मिला था जिसके बाद हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 28 हो गया था। गुमारा ने कहा कि मृतकों में आठ बच्चे शामिल हैं।

गुमारा ने बुधवार को कहा, 'हमने मरने वाले 27 लोगों की पहचान कर ली है और एक शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आज जिसका शव मिला वह एक महिला है।' एक स्थानीय बचाव दल ने कहा कि उसने कम से कम 13 लोगों को बचा लिया है और बाकी लोगों की खोज जारी है।

अमेरिका में भारतीयों ने सीएए, एनआरसी के समर्थन में निकाली रैलियां

वाशिंगटन, 25 दिसंबर (भाषा)।

बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी नागरिक संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के समर्थन में सामने आए हैं और वे इस विवादित कानून के बारे में 'गलत सूचनाओं और मिथकों को दूर' करने के लिए अमेरिका के कई शहरों में रैलियां कर रहे हैं।

संसद में जब से नागरिकता विधेयक पारित हुआ है तब से भारत में प्रदर्शन चल रहे हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के साथ ही इस विधेयक ने कानून की शक्ल अख्तियार कर ली है। रैली के आयोजकों ने बताया कि इन रैलियों का उद्देश्य कानून के बारे में 'गलत सूचनाओं और मिथकों को दूर करना' और साथ ही घृणा और झूठ के दुष्प्रचार का विरोध करना है।

उन्होंने बताया कि भारतीय-अमेरिकियों ने दिसंबर में सिएटल, 22 दिसंबर को ऑस्टिन तथा 20 दिसंबर को ह्यूस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने सीएए समर्थक रैलियां कीं। डबलिन, ओहियो और उत्तर कैरोलिना में 22 दिसंबर को रैलियां की गईं। आयोजकों ने बताया कि डलास, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन डीसी, अटलांटा, सैन जोस और अन्य स्थानों पर भी आगामी सप्ताहों में कई अन्य प्रदर्शन करने की योजना है। डबलिन ओहियो रैली के एक आयोजक विनीत गोयल ने कहा, 'हमने सीएए एवं एनआरसी के बारे में इस्लामिक और वामपंथी संगठनों में फैले भय को दूर करने के लिए यह रैली आयोजित की। साथ ही इस डर को भी दूर करने के लिए रैली की कि सीएए के साथ एनआरसी मुसलिमों को भारत से निकालने के लिए लाया जा रहा है।'

सिएटल रैली की एक आयोजक अर्चना सुनील ने कहा कि सीएए और एनआरसी के विरोधियों के पास गलत सूचनाएं हैं और वे तथ्यों पर बात नहीं करना चाहते या तथ्यों को सुनना नहीं चाहते। उत्तर कैरोलिना के रालेघ में रैली में 70 से अधिक प्रतिष्ठित डॉक्टरों और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने मांग की कि भारत में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को सख्त सजा दी जाए और इन गतिविधियों के पीछे के सरगनाओं को बख्शा न जाए।

तूफान 'फनफोन' ने फिलिपीन में मचाई तबाही

मनीला, 25 दिसंबर (एएफपी)।

मध्य फिलिपीन में क्रिसमस के मौके पर तूफान 'फनफोन' ने तबाही मचा दी, जिससे कैथोलिक बहुल देश के लाखों लोगों के क्रिसमस के जश्न पर विराम लग गया। यह तूफान यहां मंगलवार को पहुंचा था। तूफान के कारण बुधवार को हजारों लोग फंस गए या उन्हें ऊंचाई पर बने राहत शिविरों पर ले जाया गया।

तूफान 'फनफोन' से मकान तबाह हो गए, पेड़ धाराशायी हो गए और देश के सर्वाधिक तूफान प्रभावित शहर अंधेरे में डूब गए। अभी, किसी की मौत की पुष्टि नहीं की गई है। बचाव कर्मियों का कहना है कि अभी तक वे तूफान से अलग-थलग पड़ चुके इलाकों में पहुंच नहीं पाए हैं, जहां बाढ़ का पानी भरा है।

तूफान 'फनफोन' 2013 में यहां आए तूफान 'हैयान' से कम शक्तिशाली है, लेकिन यह उसके ही मार्ग पर चल रहा है।

पोप ने क्रिसमस के दिया 'बिना शर्त प्रेम' का संदेश

वेटिकन सिटी, 25 दिसंबर (एएफपी)।

पोप फ्रांसिस देश के 1.3 अरब कैथोलिक लोगों के लिए बुधवार को क्रिसमस के मौके पर 'बिना शर्त प्रेम' के संदेश के साथ सामने आए और कहा, 'भगवान हम सभी को प्रेम करते हैं, हममें से जो सबसे बुरा है उससे भी।' वेटिकन में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आधी रात में होने वाली विशप की सभा के लिए एकत्र हुए लोगों से उन्होंने कहा, 'आपके विचार भले ही विकृत हो गए हों, आपने भले ही चीजों को बुरी तरह गड़बड़ कर दिया हो, लेकिन ईश्वर अब भी आपसे प्रेम करते हैं।'

'शर्तरहित प्रेम' पर जोर ऐसे साल में दिया जा रहा है जिसमें पोप रोमन कैथोलिक चर्च में बच्चों के यौन उत्पीड़न को लेकर साधी गई चुप्पी को तोड़ने के लिए आगे आए हैं।

रूस में हेलिकॉप्टर की आपात लैंडिंग में 15 लोग घायल

मॉस्को, 25 दिसंबर (एपी)।

साइबेरिया में बुधवार की सुबह विषम परिस्थितियों में यात्री विमान की आपात लैंडिंग के दौरान 15 लोग घायल हो गए। रूस के आपात अधिकारियों ने यह जानकारी दी। देश के आपात मंत्रालय की स्थानीय शाखा के अधिकारियों ने बताया कि एमआई-8 हेलीकॉप्टर बेयकिट गांव से उड़ान भरने के फौरन बाद बर्फीले तूफान में घिर गया।

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
For the Attention of the Creditors of M/s Growthways Trading Private Limited

	RELEVANT PARTICULARS	
1	Name of corporate debtor	M/s GROWTHWAYS TRADING PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	05/04/2011
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana under Companies Act, 1956
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U52300DL2011PTC217015
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	First Floor, Kamal Cinema Building, Block A&B, South West Delhi, Delhi-110029
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	24/12/2019 NCLT Order CP (IB) NO-1443(ND)/2019 dated 17/12/2019. (Certified copy of Order received on 24/12/2019)
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	21/06/2020 (180 Days from the date of commencement of CIRP)
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Sunil Kumar Agrawal** **Registration No:** IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-2018-10222
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**Address:** E-29, South Extension-II, New Delhi- 110049 **Email:** aggarwalsk21@yahoo.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Address:** 904, GF, Sector- 7C, Faridabad- 121006 **Email:** irpgrowthways2019@gmail.com aggarwalsk21@yahoo.com
11	Last date for submission of claims	07/01/2020
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NA
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NA
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	**Web link:** https://ibbi.gov.in/downloadform.html **Physical Address:** NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (NCLT) Delhi, Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M/s Growthways Trading Private Limited from date 24.12.2019 vide order CP (IB) NO - 1443/(ND)/2019 dated 17/12/2019 (Certified copy of the Order received on dated 24/12/2019).

The creditors of M/s Growthways Trading Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 07/01/2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12 (N/A), shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class in Form CA.

The submission of claims is to be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The claim with proof is to be submitted in following specified forms along with documentary proof in support of claim.

Form B: Claim by Operational Creditors except workmen & employees.
Form C: Claim by Financial Creditors.
Form CA: Claim by Financial Creditors in a class.
Form D: Claim by workmen or an employee.
Form E: Claim submitted by an authorized representative of workmen or an employee.
Form F: Claim by Creditors (other than Financial Creditors and Operational Creditors)
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 25/12/2019
Place: New Delhi
Sunil Kumar Agrawal
Interim Resolution Professional
Regn. No: IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-2018-10222

प्ररूप संख्या आईएनसी-25क
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और
जेपी स्पिनटैक्स लिमिटेड
(CIN:U18101DL1984PLC019725)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **एफ-5/1/2662, सदर थाना रोड़, सदर बाजार, दिल्ली-110006** में स्थित है, के मामले में,
.......**आवेदक**

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक **09 दिसम्बर 2019** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति शपथनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकृत पते पर **एफ-5/1/2662, सदर थाना रोड़, सदर बाजार, दिल्ली-110006** में भी भेज दें।

कृते **जेपी स्पिनटैक्स लिमिटेड**
श्री पाल जैन (निदेशक)
DIN:00903367
तिथि : 25.12.2019
स्थान : दिल्ली

फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
सोलो मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टता	
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	सोलो मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	07 अप्रैल, 1995
3.	वह प्राधिकार, जिसके अधीन कारपोरेट ऋणी निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	कम्पनी के रजिस्ट्रार, एनसीटी के दिल्ली और हरियाणा
4.	कारपोरेट पहचान सं. / कारपोरेट ऋणी का सीमित दायित्व पहचान संख्यांक	U74899DL1995PTC037306
5.	कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पीयू-108, पीतमपुरा दिल्ली-110034, इंडिया
6.	कारपोरेट ऋणी की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख	आदेश की तिथि- 17 दिसम्बर, 2019 आदेश प्राप्ति की तिथि- 24 दिसम्बर, 2019
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने की अनुमानित तारीख	13 जून, 2020 (17 दिसम्बर 2019 से 180 दिन) अर्थात आदेश की तिथि
8	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	**नाम:** श्री तरुण जग्गी **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00113/2017-18/10220
9.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ई-मेल	**पता:** ए-1/292, भूतल, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058, इंडिया **ईमेल:** tarunjaggi@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और ई-मेल	**पता:** ए-1/292, भूतल, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058, इंडिया **ईमेल:** Solometal-CIRP@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	06 जनवरी, 2020
12.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा अभिनिश्चित धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हैं।	पता नहीं
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने के लिए अभिनिश्चित दिवाला व्यावसायिकों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(ए) सुसंगत प्ररूप और (बी) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे यहां उपलब्ध हैं:	ए) वेबलिंक https://ibbi.gov.in/home/downloads बी) भौतिक पता: लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 17 दिसम्बर, 2019 को सोलो मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

सोलो मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों को आइटम 10 के सामने दिए गए परिसमापक के पते पर 06 जनवरी, 2020 तक या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रमाण के साथ अपने दावों को जमा करना होगा। अन्य सभी लेनदार प्रमाण के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के सामने सूचीबद्ध किसी वर्ग का कोई वित्तीय लेनदार प्रविष्टि सं. 13 के सामने सूचीबद्ध दिवाला व्यावसायिकों में से उस वर्ग (वर्ग निर्दिष्ट) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसन्द प्ररूप गक में उपदर्शित करेगा।

दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर जुर्माना देना होगा।

एसडी/-
श्री तरुण जग्गी
IBBI/IPA-001/IP-P00113/2017-18/10220
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 दिसम्बर, 2019

SICOM LIMITED
पंजीकृत कार्यालय: सॉलिटेर कार्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 4, गुरु हरगोविन्दजी रोड, (अन्धेरी- घाटकोपर लिंक रोड) चाकला, अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई-400093, **टेली. नं.:** (022) 66572700 **वेबसाईट:** www.sicomindia.com

सार्वजनिक नीलामी सूचना - प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बोली के लिये आमंत्रण

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सिकॉम लि. (सिकॉम) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये प्रस्ताव/बोलियाँ आमंत्रित हैं तथा मुम्बई में सिकॉम के पंजीकृत कार्यालय में 29 जनवरी, 2020 को 3.00 बजे अप. में सार्वजनिक नीलामी द्वारा रु. 52.71 करोड़ (31.10.2019 को) की सिकॉम के बकाये की वसूली के लिये "जैसा है जहां है, जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है", "उपचार-रहित आधार" तथा "बिना किसी वारंटीज तथा क्षतिपूर्ति" के बिक्री के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार स्विश चैलेंज पद्धति में यह बिक्री की जायेगी।

अचल सम्पत्तियों का विवरण:

ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम	30.10.2019 को बकाया	मार्टगैजर का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ उपलब्ध प्रस्ताव	धरोहर राशि	निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
ऋणधारक का नाम- बोधिसत्व इस्टेट्स प्रा.लि. गारन्टर का नाम- श्री संजय चन्द्रा तथा श्री अजय चन्द्रा	मूलधन- रु. 21.07 करोड़ ब्याजः रु. 31.64 करोड़ कुल- रु. 52.71 करोड़	यूनीटेक सर्विस अपार्टमेन्ट्स लिमिटेड	ग्राम बादशाहपुर, सेक्टर 69 एवं 70, गुड़गाँव में स्थित यूनीटेक सर्विस अपार्टमेन्ट्स के स्वामित्व में भूमि माप 11.5248 एकड़ (सामान्य नियमों एवं शर्तों में अनुसूची देखें)	रु. 30.30 करोड़	रु. 3.03 करोड़	10 जनवरी, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप.	29 जनवरी, 2020 को 3.00 बजे अप. में मुम्बई में सिकॉम के पंजीकृत कार्यालय में

नीलामी के नियम एवं शर्तें:
1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाता/प्रस्तावक को सिकॉम लिमिटेड के पक्ष में देय, मुम्बई में भुगतान होने योग्य अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा रु. 3.03 करोड़ की धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा। जिस प्रस्ताव के साथ नियमों एवं शर्तों की स्वीकृत प्रति तथा ईएमडी संलग्न नहीं की जायेगी अथवा ऊपर निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त की गई प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। तथा उसे अवैध निविदा माना जायेगा तथा तदनुसार निरस्त कर दिया जायेगा। एक बार की गई बोली निरस्त अथवा वापस नहीं ली जा सकती है।
2. ऊपर वर्णित सम्पत्ति की नीलामी बिक्री स्विश चैलेंज पद्धत्ति अथवा बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी जिसकी एक अलग प्रति बोलीदाता सिकॉम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय से अथवा सिकॉम की आधिकारिक वेबसाईट (www.sicomindia.com) से प्राप्त कर सकते हैं। यदि बोलीदाता स्विश चैलेंज पद्धत्ति के नियमों एवं शर्तों तथा बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों की प्रति नहीं भी प्राप्त करते हैं तो भी माना जायेगा कि बोलीदाता ने उसे प्राप्त, अवलोकन, समीक्षा तथा स्वीकार कर लिया है।
3. प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समयः 29 जनवरी, 2020 के 2.00 बजे अप. तक सिकॉम के पंजीकृत कार्यालय, मुम्बई में।
4. सिकॉम को उसका कोई भी कारण बताए बिना बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा नीलामी को स्थगित या रद्द करने का अधिकार है।
5. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्तियों पर कोई अधिभार नहीं है। पुनः नीलामी सूचना में निर्दिष्ट विस्तार तथा माप ए.ओ., सिकॉम की सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के अनुसार दी गई है तथा एओ किसी त्रुटि, गलत-बयानी तथा कमी के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे तथा वास्तविक विस्तार एवं व्यास में अंतर हो सकता है। बोलीदाता किसी भी चार्ज, लिएन, करों अथवा किसी अन्य बकाये सहित सभी दृष्टियों से स्वयं को संतुष्ट कर लें। बोलीदाता को पुनः सलाह दी जाती है कि उक्त सम्पत्ति के संदर्भ में अपना स्वयं ड्यू डिलिजेन्स कर लें। बिक्री के अधीन सम्पत्ति से संबंधित किसी चार्ज, लिएन, अधिभार, सम्पत्ति कर अथवा किसी भी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये के लिये एओ उत्तरदायी नहीं होंगे। बोलीदाता अद्यतन तथा आगे बकाया होने वाले सभी सांविधिक देयताओं/करों/रखरखाव शुल्क/बिजली/पानी के शुल्कों आदि को सुनिश्चित कर लें जिसका वहन सफल बोलीदाता को करना होगा। सिकॉम अथवा एओ उस पर सूचना देने का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं।
6. आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए के अंतर्गत आयकर के लिये बिक्री राशि के 1% (एक प्रतिशत) की राशि का क्रेता/सफल बोलीदाता को भुगतान करना होगा। उस आयकर का भुगतान क्रेता/सफल बोलीदाता को सिकॉम के पास क्रेता/सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य के ऊपर एवं अधिक करना होगा तथा सिकॉम उससे बिना किसी प्रकार की कटौती से रहित प्रस्तावित/बोली मूल्य प्राप्त करेगा।
7. यह बिक्री हाथ में विद्यमान प्रस्ताव पर आधारित स्विश चैलेंज पद्धत्ति के अधीन होगी तथा क्रेता को उच्चतम बोली के मिलान का अधिकार होगा। यह नीलामी बोली बाजार मूल्य का पता लगाने के लिये प्रकाशित है तथा सम्पत्ति खरीदने के इच्छुक अन्य क्रेता ऊंची बोली राशि का प्रस्ताव कर सकते हैं जिसे मूल प्रस्तावक की बोली से मिलान किया जायेगा तथा यदि मूल प्रस्तावक मूल्य का मिलान करने में विफल होते हैं तो सम्पत्ति की बिक्री ऐसे बोलीदाता को की जायेगी जिन्होंने अधिक राशि के लिये बोली दिये हैं, अतएव मूल प्रस्ताव को प्रथम् अवज्ञा का अधिकार है।

आगे विवरणों तथा बिक्री के नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया सम्पर्क करें

श्री राजेन्द्र भोसले	टेली- (022)-66572724, मोबाइल- 9833546349	ई-मेल : rbhosale@sicomindia.com
श्रीमती दिशा मराठे	टेली- (022)-66572766, मोबाइल- 9920829081	ई-मेल : sware@sicomindia.com
श्री संजय कुमार - आरओ, दिल्ली	टेली- (011)-23736738, मोबाइल- 9868020160	ई-मेल : skumar@sicomindia.com

ऋणधारक/गारन्टर के लिए सूचना
नीलामी बिक्री तिथि को अथवा उससे पूर्व उपरोक्त बकाये तथा मासिक रेस्ट्स के साथ ब्याज, लागत, चार्जेज आदि का भुगतान करने के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उपरोक्त खाता में ऋणधारक/गारन्टर के लिये भी यह सूचना है जिसमें विफल होने पर उपरोक्त तिथि एवं समय में सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, उनसे ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जायेगी। आप उपरोक्त नियमों एवं शर्तों पर सार्वजनिक नीलामी सूचना में निर्दिष्ट प्रस्ताव तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) के साथ आयोजित की जाने वाली नीलामी में भाग लेने के लिये स्वतंत्र हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाईट- www.sicomindia.com देखें।
तिथि : 26.12.2019
स्थान : मुम्बई
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी, सिकॉम लि.

Edelweiss Asset Reconstruction
E-AUCTION SALE NOTICE
ई-नीलामी बिक्री सूचना
EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED
CIN: U67100MH2007PLC174759
Retail Central Office:- 1st Floor, Raheja Centre Point, 294 CST Road, Near Mumbai University, Kalina, Mumbai 400098.
Regd. Office : Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098.

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE SECURED ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8 (6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("RULES")

The financial facility of Magma Housing Finance Limited (MHFL) (hereinafter referred to as "Assignor") have been assigned to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited acting in its capacity as trustee of EARC TRUST SC 370 mentioned clearly in column provided. Pursuant to the said assignment, EARC stepped into the shoes of the Assignor and exercises its rights as the secured creditor. That EARC in its capacity as secured creditor had taken possession of the below mentioned immovable secured assets under 13 (4) of SARFAESI Act and Rules thereunder. Notice of 15 Days is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Guarantor (s) that the below described immovable secured assets mortgaged in favor of the Secured Creditor the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer (AO) of Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis, for recovery of the amounts mentioned herein below due to EARC together with further interest and other expenses/costs thereon deducted for any money received by EARC from Borrower and Guarantor. The Reserve Price, Earnest Money Deposit and date and time of auction are mentioned below.

Details of Secured Assets Put for Auction:

Sl. No.	Loan Account No	Name of Borrower / Co-Borrower	Trust Name	Bank A/c Details	Total O/s Dues as on 24.12.2019	Reserve Price (Rs.) In INR	Earnest Money Deposit (EMD) in INR	Date & Time of Auction	Type of Possession
1	HL/0052/H/14/1001 51 /MHFL	Mukesh Kumar Mahawar, Debock Sales and Marketing Pvt Ltd, Priyanka Sharma	EARC-TRUST SC 370	ICICI Bank Ltd., Nariman Point; 000405118258; ICIC0000004	Rs. 83,17,164/-	Rs. 38,00,000/-	Rs. 3,80,000/-	13/01/2020 at 12.30 PM	Physical

Property Description: All that Flat No.D-901 & D-902, on Ninth Floor, in "Tower-9", ("Majestic Heights") situated at Plot of Group Housing No.S-25, Part Khasra NO.495, 496, 501 situated at Central Spine, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan adm 3221.38sq.ft i.e., 1610sq.ft each flat.

Important Information regarding Auction Process:

1	All Demand Drafts (DD) shall be drawn in favor of Trust name as mentioned above and payable at Mumbai.	
2	Last Date of Submission of EMD	Received 1 day prior to the date of auction
3	Place for Submission of Bids	At Retail Central Office, Mumbai (mentioned above)
4	Place of Auction (Web Site for Auction)	E-Auction (https://auction.edelweissarc.in)
5	Contact Persons with Phone Nos.	Mr. Anshuman More, Mobile No.7738771766
6	Date & Time of Inspection of the Property	As per prior appointment

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in EARC's website i.e. **https://auction.edelweissarc.in**

Date: 24.12.2019
Place Mumbai, Maharashtra
Sd/- Authorized Officer
For Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

www.readwhere.com

खबर कोना

हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में बुधवार को शॉट लगाते शिखर धवन।

धवन के शतक से दिल्ली की अच्छी शुरुआत

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

फॉर्म में लौटे शिखर धवन के 137 रन की मदद से दिल्ली ने हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मैच के पहले दिन छह विकेट पर 269 रन बनाए। कड़ाके की सर्दी में फिरोजशाह कोटला पर खेले जा रहे इस मैच में धवन ने 198 गेदों का सामना करके 137 रन बनाए। पिछले 15 महीने में पहला प्रथम श्रेणी मैच खेल रहे धवन ने 19 चौके और दो छक्के लगाए। इससे पहले सुबह मोहम्मद सिराज ने कुणाल चंदेला (एक) और ध्रुव शोरे (0) को जल्दी आउट कर दिया। एक समय दिल्ली का स्कोर पांच विकेट पर 128 रन था। धवन 67 के स्कोर पर रवि किरण की गेंद पर बाल-बाल बचे जब वह नोबॉल रही। धवन ने अनुज रावत (29) के साथ छठे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। नीतिश राणा ने भी 25 रन बनाए।

टाटा ओपन के तीसरे संस्करण में वापसी करेंगे पियरे और कार्लोविच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

बेनोइट पियरे और पिछली बार के उपविजेता इवो कार्लोविच यहां बालेवाड़ी स्टेडियम में अगले साल तीन से नौ फरवरी तक आयोजित होने वाले टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण में वापसी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से आयोजित होने वाले इस टेनिस टूर्नामेंट में पूर्व विंबलडन क्वार्टर फाइनलिस्ट और एटीपी एकल रैंकिंग में करिअर की सर्वश्रेष्ठ 16वीं रैंकिंग हासिल करने वाले फिलिप कोलश्राइबर पहली बार भाग लेने जा रहे हैं। भारत के प्रमुख एटीपी 250 टूर्नामेंट का यह 25वां साल है। 30 वर्षीय पियरे 2016 में करिअर की सर्वश्रेष्ठ 18वीं रैंकिंग हासिल कर चुके हैं और 2018 में वह दो एटीपी खिताब जीत चुके हैं।

53वीं सीनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप आज से

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर।

दक्षिण एशियाई खेलों के बाद अब भारतीय खो-खो जगत एक बार फिर हाई लेबल एक्शन के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के बेमेतारा में 26 से 30 दिसंबर के बीच 53वीं सीनियर राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप (महिला एवं पुरुष) 2019-20 का आयोजन होना है। भारतीय खो-खो महासंघ (केकेएफआइ) के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ एमेच्योर खो-खो संघ द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस प्रतियोगिता में देश भर से जुटने वाली 33 पुरुष टीमें और 31 महिला टीमें अपने-अपने वर्ग में खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करती दिखेंगी।

दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने विराट कोहली

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

पिछले कुछ सालों से खेल के तीनों प्रारूपों में समान दबदबा बनाए रखने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। मशहूर पत्रिका 'द क्रिकेटर' ने पिछले दस वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 50 क्रिकेटरों की सूची तैयार की है जिसमें पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटर शामिल हैं।

भारत से कोहली के अलावा इस सूची में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (14वें), वनडे में तीन दोहरे शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा (15वें), विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (35वें), ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (36वें) और महिला टीम की दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज (40) शामिल हैं।

पत्रिका ने कोहली के बारे में लिखा है, 'दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए भारतीय कप्तान सर्वसम्मत चयन थे। विराट कोहली ने इस दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में सर्वाधिक 20,960 रन बनाए।' सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला दूसरे स्थान पर हैं लेकिन उन्होंने कोहली से लगभग 5000 रन कम बनाए हैं।

सचिन तेंदुलकर ने इसी दशक में 100 शतकों का इतिहास रचा और फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। इसमें लिखा गया है, 'तेंदुलकर ने 2013 में जब 100 शतकों के रेकार्ड के साथ संन्यास लिया तो कहा जाने लगा कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा लेकिन अब कोहली 70 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज रिकी पोंटिंग से केवल एक शतक पीछे हैं।'

कोहली ने अपने 70 शतकों में से 69 शतक 2010 से 2019 के बीच लगाए। उन्होंने अब तक कप्तान के रूप में कुल 166 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं लेकिन जिम्मेदारी के साथ उनकी बल्लेबाजी में अधिक निखार आया क्योंकि इन मैचों में उनका औसत 66.88 है। दशक के चोटी के क्रिकेटरों की सूची में शीर्ष दस में कोहली के बाद जेम्स एंडरसन, आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिस पैरी, स्टीवन स्मिथ, हाशिम अमला, केन विलियमसन, एबी डिविलयर्स, कुमार संगकारा, डेविड वार्नर और डेल स्टेन को रखा गया है।

अश्विन भारतीयों में दूसरे स्थान पर हैं। वह 2010 से लेकर 2019 तक सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने टैस्ट मैचों में 362 और सीमित ओवरों के मैचों में 202 विकेट लिए हैं। रोहित ने सलामी बल्लेबाज के रूप में तीनों प्रारूप में खुद को साबित किया है।

भारत से कोहली के अलावा इस सूची में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (14वें), वनडे में तीन दोहरे शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा (15वें), विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (35वें), ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (36वें) और महिला टीम की दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज (40) शामिल हैं।

20960

रन बनाए है भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एक दशक में। सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में हाशिम अमला दूसरे स्थान पर हैं।

32 साल बाद आस्ट्रेलिया के सामने कीवियों की चुनौती

मेलबर्न, 25 दिसंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भले ही पड़ोसी हैं लेकिन बॉक्सिंग डे टैस्ट के लिए दोनों को मैदान पर आमने-सामने होने में 32 साल लग गए। ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी गुरुवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक दूसरे का सामना करेंगे। इन दोनों टीमों के बीच दूसरा टैस्ट खेला जाएगा जिसमें न्यूजीलैंड श्रृंखला बराबर करने की कोशिश करेगा। आस्ट्रेलिया ने पर्थ में पहला टैस्ट मैच 296 रन के बड़े अंतर से जीता था।

न्यूजीलैंड इससे पहले 26 दिसंबर यानि बॉक्सिंग डे को मेलबर्न में आखिरी बार 1987 में खेला था। तब वर्तमान टीम के उसके केवल चार खिलाड़ियों नील वैगनर, रोस टेलर, बीजे वाटलिंग और कोलिन डि ग्रैंडहोम का ही जन्म हुआ था। तेज गेंदबाज टिम साउथी ने माना कि यह उनकी टीम के लिए विशेष क्षण है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मैच के पहले दिन लगभग 75 हजार दर्शकों के पहुंचने की संभावना है।

न्यूजीलैंड ने मैच के लिए अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने चोट से उबरने के बाद वापसी की है जबकि जीत रावल की जगह शीर्ष क्रम में टॉम ब्लंडेल को रखा गया है। बोल्ट पर्थ में पहले टैस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। टॉम लैथम के साथ ब्लंडेल पारी का आगाज करेंगे। ब्लंडेल ने अब तक दो टैस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने अपना आखिरी मैच दिसंबर 2017 में खेला था और उसमें भी वह आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। ब्लंडेल अमूमन मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए उतरते थे।

बॉक्सिंग डे टैस्ट

इस बीच आस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने कहा कि उनकी टीम पांच विशेषज्ञ गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। एमसीजी का विकेट पिछले दो 'बॉक्सिंग डे' टैस्ट मैच के दौरान सपाट बना रहा और उसमें 20 विकेट लेना चुनौती बन रही थी हालांकि एक महीने पहले यहां खतरनाक पिच के कारण शैफील्ड शील्ड मैच रद्द करना पड़ा था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पेन ने कहा कि फैसला आखिरी क्षणों में पिच को देखने के बाद ही किया जाएगा। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार संभावना पांच गेंदबाजों के साथ उतरने की है और ऐसे में क्वींसलैंड के तेज गेंदबाज माइकल नेसेर को पदार्पण का मौका मिल सकता है।

आस्ट्रेलिया अमूमन चार विशेषज्ञ गेंदबाजों के साथ खेलता रहा है जिनमें तीन तेज गेंदबाज और एक स्पिनर शामिल होता है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के अनुसार इससे पहले वह 2013 में श्रीलंका के खिलाफ सिडनी टैस्ट मैच में पांच विशेषज्ञ गेंदबाजों के साथ उतरा था। अगर वह पांच गेंदबाजों के साथ उतरता है तो मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, नाथन लियोन के साथ नेसेर को रखा जा सकता है जबकि चोटिल जोश हेजलवुड की जगह जेम्स पैटिनसन लेंगे। ऐसे में ट्रेविस हेड को बाहर बैठना पड़ सकता है।

न्यूजीलैंड के कई दिग्गज क्रिकेटरों को यह मौका नहीं मिला इसलिए यह खास है। हर कोई बॉक्सिंग डे टैस्ट मैच देखते हुए बड़ा हुआ है। दर्शक और इतिहास इसके साथ हैं और न्यूजीलैंड को 30 साल से भी अधिक समय से इसमें खेलने का मौका नहीं मिला है, यह थोड़ा अलग है।

- टिम साउथी, न्यूजीलैंड।

टीम के बारे में बाद में पता चलेगा। विकेट कैसा होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन हम दोनों परिस्थितियों (पांच गेंदबाजों के साथ खेलने या नहीं खेलने) के लिए तैयार हैं। हमने दिमाग में दो अलग टीमों का खाका तैयार कर रखा है। हम अंतिम फैसला गुरुवार को करेंगे।

-टिम पेन, आस्ट्रेलिया

न्यूजीलैंड इससे पहले 26 दिसंबर यानि बॉक्सिंग डे को मेलबर्न में आखिरी बार 1987 में खेला था।

1987 में टीम के उसके केवल चार खिलाड़ियों नील वैगनर, रोस टेलर, बीजे वाटलिंग और कोलिन डि ग्रैंडहोम का ही जन्म हुआ था।

पाकिस्तान में टैस्ट मैच खेलने को तैयार नहीं बांग्लादेश

ढाका, 25 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान में टैस्ट मैच नहीं खेलने के अपने फैसले पर अडिग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने कहा कि उनकी टीम वहां टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने को तैयार है। वे टैस्ट श्रृंखला किसी तटस्थ स्थल पर खेलना चाहेंगे। बीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निजामुद्दीन चौधरी ने मंगलवार को एक बार फिर बोर्ड का रूख साफ किया।

बांग्लादेश बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने इस सप्ताह मीडिया से कहा था कि वे सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान में टैस्ट नहीं खेलेंगे।

इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष एहसान मनि ने कहा कि 'इसमें कोई शक नहीं' कि उनकी टीम अब अपने घरेलू मुकाबलों को देश में ही खेलेगी। 'द डेली स्टार' ने निजामुद्दीन के हवाले से लिखा, 'हम अपने रुख पर अडिग हैं। हम पाकिस्तान में सिर्फ टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेलना चाहते हैं। श्रृंखला से संबंधित हितधारक नहीं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में सबसे लंबे प्रारूप का क्रिकेट खेले।'

उन्होंने कहा कि दरअसल, हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हम टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल सकते हैं लेकिन टैस्ट का आयोजन तटस्थ स्थल पर होना चाहिए। मनि ने बीसीबी को ई-मेल भेज कर टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने के लिए 'स्वीकार्य कारण' देने को कहा। दो मैचों की यह टैस्ट श्रृंखला 18 जनवरी से शुरू होगी जो आइसीसी विश्व टैस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।

बांग्लादेश बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने इस सप्ताह मीडिया से कहा था कि वे सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान में टैस्ट नहीं खेलेंगे। टैस्ट श्रृंखला के लिए श्रीलंका की मेजबानी करने के बाद मनि ने कहा था कि पाकिस्तान अब सुरक्षित है। श्रीलंकाई टीम पर 2009 में हुई आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में यह पहली टैस्ट श्रृंखला थी।

टीम से जुड़े बेन स्टोक्स

सेंचुरियन (दक्षिण अफ्रीका) 25 दिसंबर (एएफपी)।

इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स पिता की तबीयत में सुधार होने के बाद बुधवार को टीम के साथ जुड़ गए और अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। इंग्लैंड की टीम यहां सुपर स्पोर्ट्स पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रहे पहले टैस्ट में भिड़ेगी।

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी करके कहा कि स्टोक्स के पिता गेड अब भी जोहानिसबर्ग के अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष में हैं लेकिन इलाज का सकारात्मक असर हुआ है और उनकी स्थिति स्थिर है। गेड टैस्ट मैच देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे लेकिन उन्हें सोमवार को गंभीर बीमारी के बाद जोहानिसबर्ग के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिता के साथ मौजूद रहने के कारण स्टोक्स ने मंगलवार को अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया था। बीमारी के कारण अभ्यास मैच से दूर रहने वाले तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर स्वस्थ हो गए हैं।

भारत को मिल सकती है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप की मेजबानी

नई दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा)।

बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों (2022) से निशानेबाजी को बाहर किए जाने के बाद भारत के विरोध को देखते हुए उसकी मेजबानी में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 के आयोजन की संभावना बढ़ गई है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) ने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) से इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव देने को कहा है।

इस प्रस्ताव को जनवरी के प्रारंभ में सीजीएफ की खेल समिति के सामने पेश करने के लिए कहा गया है जिसे मंजूरी के लिए इसकी कार्यकारी समिति के पास भेजा जाएगा। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया पांच दिसंबर को म्यूनिख में सीजीएफ और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आइएसएसएफ) के बीच हुई बैठक के बाद आई है।

आइओए के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को लिखे पत्र में सीजीएफ ने कहा कि वह भारतीय राष्ट्रीय राइफल महासंघ (एनआरएआइ) के अध्यक्ष नरिंदर सिंह और व्लादिमीर लिसिन की अगुआई वाले आइएसएसएफ के प्रस्ताव से उत्साहित है। इसमें 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले इस आयोजन की मेजबानी का प्रस्ताव है।

रणजी ट्रॉफी : रेलवे ने मुंबई को 114 रन पर समेटा

मुंबई, 25 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय टैस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी साव जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी के बाद भी रेलवे ने ग्रुप बी के मैच के शुरुआती दिन मुंबई की पारी को 114 रन पर समेट दिया। रणजी इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है जब 41 बार की चैंपियन टीम की पारी लंच से पहले ही खत्म हो गई।

रेलवे के लिए प्रथम श्रेणी करिअर का तीसरा मैच खेल रहे टी प्रदीप ने 10.3 ओवर में 37 रन देकर छह विकेट लिए। दाएं हाथ के मध्यम गति के इस तेज गेंदबाज का रणजी में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मुंबई ने भी हालांकि दीपक शेट्टी (20 रन पर तीन विकेट) की अगुआई में रेलवे के पांच बल्लेबाजों को 43 रन तक पवेलियन भेज दिया था लेकिन कप्तान कर्ण शर्मा (नाबाद 24) और अरिंदम घोष (नाबाद 52) ने छठे विकेट के लिए 73 रन की अटूट साझेदारी कर दिन का खेल खत्म होने तक टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया। मैसुरु में खेले जा रहे ग्रुप के दूसरे मैच में के. अभिनय (37 रन पर पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर हिमाचल प्रदेश ने कर्नाटक की पहली को 166 रन पर समाप्त कर दिया। कर्नाटक के लिए सिर्फ कप्तान करुण नायर ही लंबी पारी खेल सके। टैस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले नायर ने 185 गेंद की पारी में आठ चौके की मदद से 85 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक कर्नाटक ने भी 29 रन तक हिमाचल प्रदेश के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। हिमाचल की टीम अभी 137 रन से पीछे है जबकि उसके सात विकेट बचे हुए हैं। कम स्कोर वाले ग्रुप के अन्य मुकाबले में ईश्वर पांडे के छह विकेट के बूते मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु को 149 रन पर आउट कर दिया। वहीं युवा सलामी हार्विक देसाई, अनुभवी चेतेश्वर पुजारा और शेलडन जैक्सन की अर्धशतकीय पारियों से सौराष्ट्र ने राजकोट में ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में उत्तर प्रदेश के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने तक आठ विकेट पर 322 रन बना लिए।

कोलकाता में खेले गए मुकाबले में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक रमन के नाबाद 110 रन की मदद से बंगाल ने आंध्र के खिलाफ पहले दिन चार विकेट पर 241 रन बनाए।

प्रदर्शन पर हावी रहा संघ का निलंबन और गुटबाजी

कोलकाता, 25 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय तीरंदाजों के कुछ प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन पर 2019 में राष्ट्रीय महासंघ का निलंबन और गुटबाजी हावी रही। अब जब तोक्यो ओलंपिक में कुछ महीनों का समय बचा है तब भी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। भारतीय तीरंदाजी को अगस्त में करारा झटका लगा जब विश्व तीरंदाजी ने भारतीय संघ (एएआइ) को निलंबित कर दिया। विश्व संस्था ने यह फैसला दो गुटों द्वारा दिल्ली और चंडीगढ़ में समानांतर चुनाव कराने के कारण लिया क्योंकि यह उसके दिशानिर्देशों के खिलाफ है।

तीरंदाजी

इस निलंबन के कारण बैंकाक एशियाई चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन करने वाले तीरंदाजों पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें विश्व तीरंदाजी के ध्वज तले तटस्थ तीरंदाज के रूप में भाग लेने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीयों ने एशिया में कोरिया के बाद खुद को दूसरा मजबूत प्रतिस्पर्धी साबित किया। अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा ने कंपाउंड मिश्रित युगल का स्वर्ण जीतकर कोरिया को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया था। लेकिन जब वे पोडियम पर पहुंचे तो न तो राष्ट्रगान बजा और ना ही तिरंगा लहराया और इन खिलाड़ियों को 'ओलंपिक एथलीट' के तौर पर संबोधित किया गया। वर्मा ने जीत के बाद कहा कि यह बहुत बुरा अहसास था और इससे हमारे प्रतिस्पर्धी भी हैरान थे। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा सभी से आग्रह है कि वह इस गुटबाजी को छोड़ें क्योंकि इसका खामियाजा हम तीरंदाजों को भुगतना पड़ रहा है। असल में भारतीयों को बैंकाक में खेलने की अनुमति केवल इसलिए मिली क्योंकि यह महाद्वीपीय ओलंपिक क्वालीफायर था जिसमें दीपिका कुमारी ने तोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया।

निलंबन के कारण बैंकाक एशियाई चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन करने वाले तीरंदाजों पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें विश्व तीरंदाजी के ध्वज तले तटस्थ तीरंदाज के रूप में भाग लेने पर मजबूर होना पड़ा।

निलंबन के कारण भारत को नेपाल में दक्षिण एशियाई खेलों में भी प्रवेश नहीं मिला जिसका फायदा उठाकर बांग्लादेश ने दांव पर लगे सभी दस स्वर्ण पदक जीते। रियो ओलंपिक में जगह बनाने से चूकने वाली भारतीय पुरुष टीम ने डेन बोस्क विश्व चैंपियनशिप से तोक्यो ओलंपिक में अपना स्थान पक्का किया। इस टीम में तरुणदीप राय, अतनु दास और प्रवीण जाधव शामिल हैं। ये तीनों विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचे जहां उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस चैंपियनशिप के इतर ही विश्व तीरंदाजी के 15 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने एएआइ को निलंबित करने का फैसला किया जो एक महीने बाद घोषित किया गया। तीरंदाजी संघ का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है। जनवरी में चुनाव होने की संभावना है लेकिन आगामी ओलंपिक में तीरंदाज भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे या नहीं इसको लेकर कयास ही लगाए जा रहे हैं।

'गांगुली का चार देशों के टूर्नामेंट का विचार 'फ्लॉप' होगा'

कराची, 25 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि बीसीसीबाइ अध्यक्ष सौरव गांगुली द्वारा प्रस्तावित चार देशों के टूर्नामेंट का विचार असफल साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसका हाल भी उसी तरह से होगा जैसे की 'बिग थ्री (क्रिकेट खेलने वाले बड़े देश) मॉडल' का हुआ था। इस पूर्व विकेटकीपर को लगता है कि इससे भारत, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें अन्य सदस्य राष्ट्रों को अलग करने की कोशिश कर रही है।

लतीफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि इस तरह का टूर्नामेंट खेलकर ये चार देश दूसरे सदस्य देशों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जो अच्छा विचार नहीं है। मुझे हालांकि लगता है कि यह उसी तरह से फ्लॉप होगा जैसे कुछ वर्ष पूर्व लाए गए बिग थ्री मॉडल के साथ हुआ था।

पिछले सप्ताह गांगुली ने कहा था कि क्रिकेट के बड़े देशों के बीच 2021 तक चार देशों की टूर्नामेंट करने की योजना पर काम हो रहा है। इसके बारे में इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट आस्ट्रेलिया से चर्चा हो रही है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 39, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना- एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com